



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 37]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 16, 1978/भाद्र 25, 1900

No. 37]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 16, 1978/BHADRA 25, 1900

इस भाग में शिर्ष पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर)
केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India
(other than the Ministry of Defence) by Central Authorities
(other than the Administrations of Union Territories)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1978

का०प्रा० 2662—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 8 के उपनियम (2), नियम 12 के उपनियम (2) के खंड (ख) और नियम 24 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के भूतपूर्व वित्त मंत्रालय (कंपनी विधि प्रशासन) की, समय-समय पर यथा संगोदित, अधिसूचना सं० का०नि० प्रा० 624, तारीख 28 फरवरी, 1957 को अधिकांत करते हुए, निवेश देते हैं कि—

(1) आदेश की अनुसूची के भाग 1 के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट, साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' के पदों की बाबत, स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी नियुक्त प्राधिकारी होगा और स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, स्तम्भ 5 में विनिर्दिष्ट शास्तियों के संबंध में अनुशासन प्राधिकारी होगा; तथा

(2) उक्त अनुसूची के भाग 2 और भाग 3 के स्तम्भ में विनिर्दिष्ट, साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' तथा साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'घ' के पदों की बाबत, स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी नियुक्त प्राधिकारी होगा, तथा स्तम्भ 4 और स्तम्भ 6 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, स्तम्भ 5 में विनिर्दिष्ट शास्तियों के संबंध में क्रमशः अनुशासन प्राधिकारी अपील प्राधिकारी होंगे।

घनसूची

भाग 1—साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ब'

कार्यालय का नाम	पदों का वर्णन	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्तियां अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी और वे शास्तियां जो बहु अधिरोपित कर सकेंगी (निबन्ध 11 में सब सं० के प्रतिनिवेश से)	
			प्राधिकारी	शास्तियां
1	2	3	4	5
सचिवालय	सभी राजपत्रित पद	सचिव (कम्पनी कार्य)	सचिव (कम्पनी कार्य)	सभी
	सभी अराजपत्रित पद	संयुक्त सचिव (कम्पनी कार्य)	संयुक्त सचिव (कम्पनी कार्य)	सभी
सचिवालय से मिले कार्यालय :				
1. क्षेत्रीय निदेशक, कंपनी विधि बोर्ड	सभी राजपत्रित पद	सचिव (कम्पनी कार्य)	सचिव (कम्पनी कार्य) क्षेत्रीय निदेशक	सभी (1) उसके अपने कार्यालय में तथा कम्पनी रजिस्ट्रार/शासकीय समापकों के कार्यालयों में कार्य करने वाले व्यक्तियों की बाबत।
2. कम्पनी रजिस्ट्रार				
3. शासकीय समापक		संयुक्त सचिव (कम्पनी कार्य)	संयुक्त सचिव (कम्पनी कार्य) क्षेत्रीय निदेशक	सभी (1) से (4) उसके अपने कार्यालय में तथा कम्पनी रजिस्ट्रार/शासकीय समापकों के कार्यालयों में कार्य करने वाले व्यक्तियों की बाबत।
4. रजिस्ट्रार अवरोधक व्यापार करार	सभी राजपत्रित पद	सचिव (कम्पनी कार्य)	सचिव (कम्पनी कार्य) रजिस्ट्रार अवरोधक व्यापार करार	सभी
	सभी अराजपत्रित पद	संयुक्त सचिव (कम्पनी कार्य)	संयुक्त सचिव (कम्पनी कार्य) रजिस्ट्रार अवरोधक व्यापार करार	(1) सभी (1) से (4)
5. अन्वेषण निदेशक	सभी अराजपत्रित पद	संयुक्त सचिव (कम्पनी कार्य)	संयुक्त सचिव (कम्पनी कार्य) अन्वेषण निदेशक	सभी (1) से (4)
6. लोक न्यायी	सभी पद	लोक न्यायी	लोक न्यायी	सभी

भाग 2—साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग'

कार्यालय का नाम	पदों का वर्णन	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्तियाँ अधिरोपित करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा वे शास्तियाँ जो वह अधिरोपित कर सकेगा (नियम 11 में मव सं० के प्रतिनिर्देश से)		अपील प्राधिकारी
			प्राधिकारी	शास्तियाँ	
1	2	3	4	5	6
सचिवालय से भिन्न कार्यालय:					
1. क्षेत्रीय निदेशक कंपनी विधि बोर्ड	(क) 480 रु० प्रतिमास के अधिकतम वेतन वाले वेतनमान के पद। (ख) अन्य सभी पद	उपनिदेशक (लेखा)/ संयुक्त निदेशक (लेखा)	उप-निदेशक (लेखा)/ संयुक्त निदेशक (लेखा)	सभी	क्षेत्रीय निदेशक
2. कंपनी रजिस्ट्रार	(क) 480 रु० प्रति मास के अधिकतम वेतन वाले वेतनमान के पद। (ख) अन्य सभी पद	क्षेत्रीय निदेशक कंपनी रजिस्ट्रार	क्षेत्रीय निदेशक कंपनी रजिस्ट्रार	सभी	संयुक्त सचिव (कंपनी कार्य) क्षेत्रीय निदेशक
3. शासकीय समापक	(क) 480 रु० प्रतिमास के अधिकतम वेतन वाले वेतनमान के पद। (ख) अन्य सभी पद	शासकीय समापक क्षेत्रीय निदेशक	शासकीय समापक क्षेत्रीय निदेशक	सभी (1) से (4)	प्रादेशिक निदेशक संयुक्त सचिव (कंपनी कार्य) क्षेत्रीय निदेशक
4. रजिस्ट्रार अवरोधक व्यापार करार	(क) 480 रु० प्रतिमास के अधिकतम वेतन वाले वेतनमान के पद (ख) अन्य सभी पद	संयुक्त रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार	संयुक्त रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार	सभी	संयुक्त सचिव (कंपनी कार्य) क्षेत्रीय निदेशक रजिस्ट्रार
5. अन्वेषण निदेशक	(क) 480 रु० प्रति मास के अधिकतम वेतन वाले वेतनमान के पद (ख) अन्य सभी पद	संयुक्त निदेशक निदेशक	संयुक्त निदेशक निदेशक	सभी	निदेशक संयुक्त सचिव (कंपनी कार्य)
6. लोक न्यासी	सभी पद	कंपनी लेखापाल	कंपनी लेखापाल	सभी	लोक न्यासी

भाग 3—साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ब'

कार्यालय का नाम	पदों का वर्णन	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्तियाँ अधिरोपित करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा वे शास्तियाँ जो वे अधिरोपित कर सकेगा (नियम 11 में मव सं० के प्रति निर्देश से)		अपील प्राधिकारी
			प्राधिकारी	शास्तियाँ	
1	2	3	4	5	6
सचिवालय से भिन्न कार्यालय:					
1. क्षेत्रीय निदेशक कंपनी विधि बोर्ड	सभी पद	उपनिदेशक (लेखा)/ संयुक्त निदेशक (लेखा)	उपनिदेशक (लेखा)/ संयुक्त निदेशक (लेखा)	सभी	क्षेत्रीय निदेशक
2. कंपनी रजिस्ट्रार	सभी पद	कंपनी रजिस्ट्रार	कंपनी रजिस्ट्रार	सभी	क्षेत्रीय निदेशक
3. शासकीय समापक	सभी पद	शासकीय समापक	शासकीय समापक	सभी	क्षेत्रीय निदेशक
4. रजिस्ट्रार अवरोधक व्यापार करार	सभी पद	उप-निदेशक	उप-निदेशक	सभी	संयुक्त रजिस्ट्रार
5. अन्वेषण निदेशक	सभी पद	संयुक्त निदेशक	संयुक्त निदेशक	सभी	निदेशक
6. लोक न्यासी	सभी पद	कंपनी लेखापाल	कंपनी लेखापाल	सभी	लोक न्यासी

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 1st September, 1978

S.O. 2662—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 9, clause (b) of sub-rule (2) of rule 12 and sub-rule (1) of rule 24 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, and in supersession of the Notification of the Government of India in the Late Ministry of Finance (Company Law Administration) No. S. R. O. 624, dated the 28th February, 1957, as amended from time to time, the President hereby directs that—

(1) in respect of the posts in the General Central Service Group B, specified in column 2 of the Part I of the Schedule to the Order, the authority specified in column 3 shall be the Appointing Authority and the authority specified in column 4 shall be the Disciplinary Authority in regard to penalties specified in column 5; and

(2) in respect of the posts in the General Central Service Group C and the General Central Service Group D, specified in column 2 of Part II and Part III of the said Schedule, the authority specified in column 3 shall be the Appointing Authority and the authorities specified in columns 4 and 6 shall be the Disciplinary Authority and the Appellate Authority respectively in regard to the penalties specified in column 5.

SCHEDULE

PART I—General Central Service Group 'B'

Name of Office	Description of posts	Appointing Authority	Authority competent to impose penalties and penalties which it may impose (with reference to item number in rule 11)	
			Authority	Penalties
1	2	3	4	5
Secretariat	All Gazetted Posts	Secretary (Company Affairs)	Secretary (Company Affairs)	All
	All Non-Gazetted posts	Joint Secretary (Company Affairs)	Joint Secretary (Company Affairs)	All
Non-Secretariat Offices :				
1. Regional Director, Company Law Board.	All Gazetted Posts	Secretary (Company Affairs)	Secretary (Company Affairs) Regional Director	All (i) in respect of persons working in his own office and offices of the Registrar of Companies/Official Liquidators.
2. Registrar of Companies.	All Non-Gazetted posts	Joint Secretary (Company Affairs)	Joint Secretary (Company Affairs) Regional Director	All
3. Official Liquidators				(i) to (iv) in respect of person working in his own office and office of the Registrar of Companies/Official liquidators.
4. Registrar, Restrictive Trade Agreements	All Gazetted posts	Secretary (Company Affairs)	Secretary (Company Affairs) Registrar, Restrictive Trade Agreements.	All (i)
	All Non-Gazetted posts.	Joint Secretary (Company Affairs)	Joint Secretary (Company Affairs) Registrar, Restrictive Trade Agreements	All (i) to (iv)
5. Director of Investigation	All Non-Gazetted posts	Joint Secretary (Company Affairs)	Joint Secretary (Company Affairs) Director of Investigation	All (i) to (iv)
6. Public Trustee	All posts	Public Trustee	Public Trustee	All

PART II—General Central Service, GROUP 'C'

Name of Office	Description of Posts	Appointing Authority	Authority competent to impose penalties and penalties which it may impose (with reference to item numbers in rule 11)		Appellate Authority
			Authority	Penalties	
1	2	3	4	5	6
Non-Secretariat Offices					
1. Regional Director, Company Law Board.	(a) Posts in the scale of pay carrying a maximum pay of Rs. 480/—p. m.	Deputy Director (Accounts)/Joint Director (Accounts)	Deputy Director (Accounts)/Joint Director (Accounts)	All	Regional Director
	(b) All other posts.	Regional Director	Regional Director	All	Joint Secretary (Company Affairs)
2. Registrar of Companies.	(a) Posts in the scale of pay carrying a maximum pay of Rs. 480/—p. m.	Registrar of Companies	Registrar of Companies	All	Regional Director
	(b) All other posts.	Regional Director	Regional Director	All	Joint Secretary (Company Affairs)
3. Official Liquidators	(a) Posts in the scale of pay carrying a maximum pay of Rs. 480/—p. m.	Official Liquidator	Official Liquidator	All	Regional Director
	(b) All other posts.	Regional Director	Regional Director	All	Joint Secretary (Company Affairs)
4. Registrar, Restrictive Trade Agreements	(a) Posts in the scale of pay carrying a maximum pay of Rs. 480/—p. m.	Joint Registrar	Joint Registrar	All	Regional Director
	(b) All other posts.	Registrar	Registrar	All	Joint Secretary (Company Affairs)
5. Director of Investigation	(a) Posts in the scale of pay carrying a maximum pay of Rs. 480/—p. m.	Joint Director	Joint Director	All	Director
	(b) All other posts.	Director	Director	All	Joint Secretary (Company Affairs)
6. Public Trustee	All Posts	Company Accountant	Company Accountant	All	Public Trustee

PART—III—General Central Service Group 'D'

Name of Office	Description of Posts	Appointing Authority	Authority competent to impose penalties and penalties which it may impose (with reference to item number in rule 11)		Appellate Authority
			Authority	Penalties	
1	2	3	4	5	6
Non-Secretariat Offices					
1. Regional Director, Company Law Board.	All posts	Deputy Director (Accounts)/Joint Director (Accounts).	Deputy Director (Accounts)/Joint Director (Accounts)	All	Regional Director
2. Registrar of Companies	All posts	Registrar of Companies	Registrar of Companies	All	Regional Director
3. Official Liquidator	All posts	Official Liquidator	Official Liquidator	All	Regional Director
4. Registrar, Restrictive Trade Agreements.	All posts	Deputy Director	Deputy Director	All	Joint Registrar
5. Director of Investigation	All posts	Joint Director	Joint Director	All	Director
6. Public Trustee	All posts	Company Accountant	Company Accountant	All	Public Trustee

[F. No. A-42015/29/76-Ad. II]

I. L. NAGPAL, Under Secy.

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1978

शुद्धीपत्र

का०प्रा० 2663.—भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 25 मार्च, 1978 के पृष्ठ 886 में प्रकाशित भारत सरकार, विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना सं० का० प्रा० 802 तारीख 10 मार्च, 1978 में क्रम संख्या 3 में "सयद अब्दुल हलीम साहब चिश्ती, खादिम मोहल्ला, अजमेर" के स्थान पर "सयद हलीम चिश्ती, महबूब मंजिल, खादिम मोहल्ला, अजमेर" पढ़ें।

[फा० सं० 11/3/76-वकफ]

एच० सी० वरमानी, विशेष कार्य अधिकारी (वकफ)

(Legislative Department)

New Delhi, the 4th September, 1978

CORRIGENDUM

S.O. 2663.—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Legislative Department) No. S.O. 802 dated the 10th March, 1978, published in the Gazette of India, Part II-Section 3, sub-section (ii) dated the 25th March, 1978, at page 886, in serial number 3, for "Syed Abdul Haleem Sahib Chishty, Khadim Mohalla, Ajmer" read "Syed Haleem Chishty, Mehboob Manzil, Khadim Mohalla Ajmer".

[File No. 11/3/76-Wakf]

S.O. 2664.—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Legislative Department) No. S.O. 516 (E), dated the 24th August, 1978, published in the Gazette of India, Extraordinary, part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 24th August, 1978 at page 1006 for "New Delhi, the 24th August" read "New Delhi, the 24th August, 1978".

[F. No. 14/8/74-Wakf]

S.O. 2665.—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Legislative Department) No. S.O. 500(E), dated the 11th August, 1978, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) dated the 11th August, 1978, at page 973 for "F. 4/4/73-Wakf" read "F. 4/3/73-Wakf".

[F. No. 4(9)/77-Wakf.]

H. C. VERMANI, Officer

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1978

का०प्रा० 2666:—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1973 का 2) की धारा 24 की उपधारा (6) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, दिल्ली के न्यायालय तथा दिल्ली के रीजिनल और अप्रीलीय न्यायालयों में श्री राम लाल नारंग तथा अन्यो के विरुद्ध दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के नियमित मामले संख्या 17/66-सी०आई०ए० (1) तथा 21/66-सी०आई०ए० (1) से उत्पन्न न्यायालयों के मामलों में अभियोजन के संचालन हेतु श्री धार० एल० मेहता, अधिवक्ता दिल्ली को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या 225/54/78-ए०पी०डी० (II)]

टी० के० सुब्रमणियन, अवसर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

New Delhi, the 1st September, 1978

S.O. 2666.—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints

Shri R. L. Mehta, Advocate, Delhi, as a Special Public Prosecutor for conducting the prosecution of the court cases arising out of the Delhi Special Police Establishment Regular cases Nos. 17/66-CIA(I) and 21/66-CIA(I) against Ram Lal Narang and others in the court of the Metropolitan Magistrate, Delhi and in revisional and appellate courts at Delhi.

[No. 225/54/78-AVD. II]

T. K. SUBRAMANIAN, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 15 मई, 1978

शुद्धीपत्र

भाय-कर

का०प्रा० 2667.—राजस्व विभाग, अधिसूचना सं० 593 (का०सं० 203/13/74-आई टी ए II), तारीख 17-4-1974 में निम्नलिखित संशोधन करता है:—

"क्षेत्रीय विकास अध्ययन केन्द्र, सुरत"
के स्थान पर,

"समाज अध्ययन केन्द्र, सुरत" पढ़ें।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 1977 से प्रभावी है।

[सं० 2293/का०सं० 203/13/74-आई टी ए II पी टी II]

जे० पी० शर्मा, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 15th May, 1978

CORRIGENDUM

INCOME TAX

S.O. 2667.—The Department of Revenue hereby amend the notification No. 593 (F. No. 203/13/74-ITA- II) dated the 17-4-1974 as under:—

For

Read

Centre for Regional Deve- Centre for Social Studies, Surat
lopment Studies, Surat.

This amendment is effective from 1st April, 1977.

[No. 2293/F. No. 203/13/74—ITA. II Pt. III]

J. P. SHARMA, Director

नई दिल्ली, 24 जून, 1978

भाय-कर

का०प्रा० 2668.—केन्द्रीय सरकार, भाय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (IV) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "निगमित और अनिगमित देवासवम्स सुचिन्द्रम" को निर्धारण वर्ष 1973-74 के लिए और से उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं० 236/का०सं० 197/9/78-प्रा०क० (ए०I)]

एम० शास्त्री, अवसर सचिव

New Delhi, the 24th June, 1978

INCOME-TAX

S.O. 2668.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Incorporated and Unincorporated Devaswoms, Suchindrum" for the purpose of the said section for and from the assessment year(s) 1973-74.

[No. 2360/F. No. 197/9/78-IT AI]

M. SHASTRI, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 1978

, प्रायकर

प्रा० का० 2269.—प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उप-खण्ड (iii) के अनुसरण में तथा भारत सरकार के राजस्व विभाग की दिनांक 19-5-1975 की अधिसूचना सं० 907 (फा० सं० 404/94/75-प्रा० क० सं० क०) के अधिलेखन में केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी श्री के० मीनाक्षी सुन्दरम् को उपर्युक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना श्री के० मीनाक्षी सुन्दरम् द्वारा कर वसूली अधिकारी के पद का कार्यभार संभालने की तारीख से लागू होगी।

[सं० 2472/फा० सं० 404/103/77-प्रा० क० सं० क०]

एच० वेण्कटरामन्, उप सचिव

New Delhi, the 18th August, 1978

INCOME-TAX

S.O. 2669.—In pursuance of sub-clause (iii) of of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Revenue No. 907 (F. No. 404/94/75-ITCC) dated 19-5-75 the Central Government hereby authorises Shri K. Meenakshi Sundaram being a Gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri K. Meenakshi Sundaram takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 2472/F. No. 404/103/77-ITCC]

H. VENKATARAMAN, Dy. Secy.

(बिक्री कर अनुभाग)

भावेरा

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1978

स्टाम्प

का० प्रा० 2670.— भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम को, डिबेंचरों के रूप में, उक्त निगम द्वारा जारी किए जाने वाले तीन करोड़ दो लाख, पचास हजार रुपये के अंकित मूल्य के बंधपत्रों पर स्टाम्प शुल्क के रूप में प्रभाय केवल 2, 26, 875 रुपये का समेकित स्टाम्प शुल्क भ्रवा करने की अनुज्ञा देती है।

[सं० 20/78-स्टाम्पस-फा० सं० 33/39/78-बि० क०]

एम० प्रार० वैद्य, भवर सचिव

(Sales Tax Section)

ORDER

New Delhi, the 31st August, 1978

STAMPS

S.O. 2670.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899) the Central Government hereby permits the Maharashtra Industrial Development Corporation, Bombay to pay consolidated stamp duty of two lakhs, twenty six thousands, eight hundred and seventy five rupees only, chargeable on account of the stamp duty on bonds in the form of debentures of the face value of three crores, two lakhs and fifty thousands of rupees to be issued by the said Corporation.

[No. 20/78-Stamp-F. No. 33/39/78-ST]

M. R. VAIDYA, Under Secy.

भारतीय रिजर्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 1978

New Delhi, the 26th August, 1978

का० प्रा० 2671.— भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसरण में 1978 के दिनांक 21 जुलाई को समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा।

S.O. 2671.—An Account pursuant to the Reserve Bank of India Act, 1934 for the week ended the 21st day of July, 1978.

इस विभाग

ISSUE DEPARTMENT

देयताएँ LIABILITIES	रुपये Rs.	रुपये Rs.	भास्तियाँ ASSETS	रुपये Rs.	रुपये Rs.
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट Notes held in the Banking Department	13,26,36,000		सोने का सिक्का और बुलियन :— Gold Coin and Bullion		
संचलन में नोट Notes in circulation	9186,07,34,000		(क) भारत में रखा हुआ (a) Held in India	214,21,78,000	
जारी किये गये कुल नोट Total Notes issued		9199,33,70,000	(ख) भारत के बाहर रखा हुआ (b) Held outside India	
			विदेशी प्रतिभूतियाँ Foreign Securities	2145,32,65,000	
			जोड़ Total		2359,54,43,000
			रुपये का सिक्का Rupce Coin		24,59,57,000
			भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियाँ Government of India Rupce Securities		6815,19,70,000
			देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य-पत्र Internal Bills of Exchange and other commercial paper
कुल देयताएँ Total Liabilities		9199,33,70,000	कुल भास्तियाँ Total Assets		9199,33,70,000

दिनांक : 26 जुलाई, 1978
Dated the 26th July, 1978

के० एस० कृष्णस्वामी, उप गवर्नर
K.S. KRISHNASWAMY, Dy. Governor

21 जुलाई, 1978 को भारतीय रिज़र्व बैंक के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण

Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, Banking

Department as on the 21st July, 1973

देयताएँ LIABILITIES	रुपये Rs.	अस्तित्व ASSETS	रुपये Rs.
चुकाता पूंजी Capital Paid Up	5,00,00,000	नोट Notes	13,26,26,000
आरक्षित निधि Reserve Fund	150,00,00,000	रुपये का सिक्का Rupee Coin	9,27,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	610,00,00,000	छोटा सिक्का Small Coin	4,88,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	195,00,00,000	खरीदे और भुनाये गये बिलः— Bills Purchased and Discounted :—	
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	915,00,00,000	(क) देशी (a) Internal	101,18,72,000
जमा राशियाँ :— Deposits :—		(ख) विदेशी (b) External
(क) सरकारी (a) Government		(ग) सरकारी खजाना बिल (c) Government Treasury Bills	692,97,00,000
(i) केन्द्रीय सरकार (i) Central Government	239,19,10,000	विदेशों में रखा हुआ बकाया* Balances Held Abroad*	1583,65,77,000
(ii) राज्य सरकारें (ii) State Governments	10,35,83,000	निवेश** Investments**	907,82,11,000
(ख) बैंक (b) Banks		ऋण और अग्रिम :— Loans and Advances to :—	
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक (i) Scheduled Commercial Banks	1678,20,55,000	(i) केन्द्रीय सरकार को (i) Central Government
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक (ii) Scheduled State Co-operative Banks	30,55,67,000	(ii) राज्य सरकारों को @ (ii) State Governments @	12,6,90,65,000
(iii) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक (iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	2,43,15,000	ऋण और अग्रिम :— Loans and Advances to :—	
(iv) अन्य बैंक Other Banks	1,97,06,000	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को† (i) Scheduled Commercial Banks†	217,82,78,000
(ग) अन्य (c) Others	1806,86,03,000	(ii) राज्य सहकारी बैंकों को‡ (ii) State Co-operative Banks‡	266,90,07,000
देय बिल Bills Payable	166,06,05,000	(iii) दूसरों को (iii) Others	4,63,25,000
अन्य देयताएँ Other Liabilities	555,03,31,000	राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश Loans, Advances and Investments from Na- tional Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	
		(क) ऋण और अग्रिम :— (a) Loans and Advances to :—	
		(i) राज्य सरकारों को (i) State Governments	110,72,21,000
		(ii) राज्य सहकारी बैंकों को (ii) State Co-operative Banks	18,11,03,000
		(iii) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को (iii) Central Land Mortgage Banks
		(iv) कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम को (iv) Agricultural Refinance and Develop- ment Corporation	215,80,00,000
		(ख) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश (b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures	7,80,37,000
		राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अग्रिम Loans and Advances from National Agricul- tural Credit (Stabilisation) Fund	
		राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम Loans and Advances to State Co-operative Banks	135,86,74,000

देयताएं LIABILITIES	रुपये Rs.	आस्तियां ASSETS	रुपये Rs.
		राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	
		(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम (a) Loans and Advances to the Development Bank	688,45,34,000
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांडों/डिबेंचरों में निवेश (b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank	
		अन्य आस्तियां Other Assets	1273,64,20,000
रुपये Rupees.	6365,66,75,000	रुपये Rupees.	6365,66,75,000

*नकदी, आवधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं।

*Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

**राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं हैं।

**Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

@राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं, परन्तु राज्य सरकारों को दिये गये अस्थायी ओवरड्राफ्ट शामिल हैं।
@Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, but including temporary overdrafts to State Governments.

†भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 17(4)(ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को भियादी बिलों पर अग्रिम दिये गये 2,76,00,000 रुपये शामिल हैं।
†Includes Rs 2,76,00,000/- advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act.

††राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरकरण) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं।

††Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

दिनांक 26 जुलाई, 1978

Dated the 26th day of July, 1978

के० एस० कृष्णस्वामी, उप गवर्नर

K.S. KRISHNA SWAMY, Dy. Governor

[No. F. 10/1/78-BOI

का० प्रा० 2672—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसरण में 1978 के दिनांक 28 जुलाई को समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा

S. O. 2672—An Account pursuant to the Reserve Bank of India Act, 1934 for the week ended the 28th day of July, 1978.

हज़ू विभाग

ISSUE DEPARTMENT

देयताएं LIABILITIES	रुपये Rs.	रुपये Rs.	आस्तियां ASSETS	रुपये Rs.	रुपये Rs.
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट Notes held in the Banking Department	27,82,55,000		सोने का सिक्का और बुलियन :— Gold Coin and Bullion		
संचलन में नोट Notes in circulation	9018,79,01,000		(क) भारत में रखा हुआ (a) Held in India	214,21,78,000	
जारी किये गये कुल नोट Total Notes issued		9046,61,56,000	(ख) भारत के बहार रखा हुआ (b) Held outside India	—	
			विदेशी प्रतिभूतियां Foreign Securities	2145,32,65,000	
			जोड़ Total		2359,54,43,000
			रुपये का सिक्का Rupee Coin		26,87,95,000
			भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां Government of India Rupee Securities		6660,19,18,000
			देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य-पत्र Internal Bills of Exchange and other commercial paper		
कुल देयताएं Total Liabilities		9046,61,56,000	कुल आस्तियां Total Assets		9046,61,56,000

दिनांक : 2 अगस्त, 1978

Dated the 2nd day of August, 1978

581 GI/78—2

आई० जी० पटेल, गवर्नर

I.G. PATEL, Governor

28 जुलाई, 1978 को भारतीय रिज़र्व बैंक के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण
Statement of the affairs of the Reserve Bank of India, Banking Department as on the 28th July, 1978

देयताएँ LIABILITIES	रुपये Rs.	प्रतिभ्याँ ASSETS	रुपये Rs.
शुद्धता पूंजी Capital Paid Up	5,00,00,000	नोट Notes	27,82,55,000
भारक्षित निधि Reserve Fund	150,00,00,000	रुपये का सिक्का Rupee Coin	4,83,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	610,00,00,000	छोटा सिक्का Small Coin	5,19,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	195,00,00,000	खरीदे और धुनाये गये बिल Bills Purchased and Discounted :—	—
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि National industrial Credit (Long Term Operations) Fund	915,00,00,000	(क) देशी (a) Internal	95,28,59,000
जमा राशि :— Deposits :—		(ख) विदेशी (b) External	
(क) सरकारी (a) Government		(ग) सरकारी खजाना बिल (c) Government Treasury Bills	594,82,70,000
(i) केन्द्रीय सरकार (i) Central Government	158,31,84,000	विदेशों में रखा हुआ बकाया* Balances Held Abroad*	1588,38,13,000
(ii) राज्य सरकारें (ii) State Governments	10,30,86,000	निवेश** Investments**	1043,06,89,000
(ख) बैंक (b) Banks		ऋण और प्रभिम :— Loans and Advances to :—	
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक (i) Scheduled Commercial Banks	1788,17,82,000	(i) केन्द्रीय सरकार को (i) Central Government	
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक (ii) Scheduled State Co-operative Banks	29,31,40,000	(ii) राज्य सरकारों को (ii) State Governments@	140,30,01,000
(iii) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक (iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	2,92,81,000	ऋण और प्रभिम :— Loans and Advances to :—	
(iv) अन्य बैंक (iv) Other Banks	2,41,98,000	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को (i) Scheduled Commercial Banks†	206,82,75,000
(ग) अन्य (c) Others	1809,69,98,000	(ii) राज्य सहकारी बैंकों को (ii) State Co-operative Banks‡	275,72,22,000
देय बिल Bills Payable	172,60,43,000	(iii) दूसरों को (iii) Others	4,43,25,000
अन्य देयताएँ Other Liabilities	557,73,50,000	राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण, प्रभिम और निवेश Loans, Advances and Investments from Na- tional Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	
		(क) ऋण और प्रभिम :— (a) Loans and Advances to :—	
		(i) राज्य सरकारों को (i) State Governments	110,71,97,000
		(ii) राज्य सहकारी बैंकों को (ii) State Co-operative Banks	18,04,71,000
		(iii) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को (iii) Central Land Mortgage Banks	
		(iv) कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम को (iv) Agricultural Refinance and Develop- ment Corporation	215,80,00,000
		(ख) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के डिपेंडेंसियों में निवेश (b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures	7,72,37,000
		राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और प्रभिम Loans and Advances from National Agricul- tural Credit (Stabilisation) Fund	
		राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और प्रभिम Loans and Advances to State Co-operative Banks	133,39,13,000

देयताएं LIABILITIES	रुपये Rs.	आस्तियां ASSETS	रुपये Rs.
		राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश Loans, Advances and Investments from Na- tional Industrial Credit (Long Term Opera- tions) Fund	
		(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम (a) Loans and Advances to the Development Bank	688,45,34,000
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांडों/डिबेंचरों में निवेश (b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank	..
		अन्य आस्तियां Other Assets	1255,59,99,000
रुपये Rupees	6406,50,62,000	रुपये Rupees	6406,50,62,000

*नकदी, आवधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं।

Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

**राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं हैं।
Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

@राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं, परन्तु राज्य सरकारों को विये गये अस्थायी ओवरड्राफ्ट शामिल हैं।

Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, but including temporary overdrafts to State Governments.

†भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17(4)(ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मियादी बिलों पर अग्रिम विये गये—
रुपये शामिल हैं।

Includes Rs. 2,76,00,000 advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act.

‡राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं।
दिनांक : 26 जुलाई, 1978

Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

दिनांक : 2 अगस्त, 1978

Dated the 2nd day of August, 1978

आई० जी० पटेल, गवर्नर

I.G. PATEL, Governor

[No. F. 10/1/78-BOI]

का०धा० 2673.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसरण में 1978 के दिनांक 4 अगस्त को समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा

S.O. 2673.—An Account pursuant to the RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 for the week ended the 4th day of August 1978

इस विभाग ISSUE DEPARTMENT

देयताएं LIABILITIES	रुपये Rs.	रुपये Rs.	आस्तियां ASSETS	रुपये Rs.	रुपये Rs.
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट Notes held in the Banking Department	23,31,65,000		सोने का सिक्का और बुलियन— Gold Coin and Bullion		
संचालन में नोट notes in circulation	9108,12,41,000		(क) भारत में रखा हुआ (a) Held in India	214,21,78,000	
जारी किये गए कुल नोट Total Notes issued		9131,44,06,000	(ख) भारत के बाहर रखा हुआ (b) Held outside India	..	
			विदेशी प्रतिभूतियां Foreign Securities	2145,32,65,000	
			कुल Total		2359,54,43,000
			रुपये का सिक्का Rupee Coin		26,71,13,000
			भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां Government of India Rupee Securities		6745,18,50,000
			देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य- पत्र Internal Bills of Exchange and other commercial paper		..
कुल देयताएं Total Liabilities		9131,44,06,000	कुल आस्तियां Total Assets		9131,44,06,000

दिनांक 9 अगस्त, 1978

Dated 9th day of August, 1978

आई० जी० पटेल, गवर्नर

I.G. PATEL, Governor

4 अगस्त, 1978 को भारतीय रिज़र्व बैंक के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण

Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, Banking Department as on the 4th August, 1978

देयताएं LIABILITIES	रुपये Rs.	भास्तियां ASSETS	रुपये Rs.
मुक्तता पूंजी Capital Paid Up	5,00,00,000	नोट Notes	23,31,65,000
भारक्षित निधि Reserve Fund	150,00,00,000	रुपये का सिक्का Rupee Coin	3,00,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	610,00,00,000	छोटा सिक्का Small Coin	5,58,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	195,00,00,000	खरीदे और धुनाये गये बिल Bills Purchased and Discounted:—	
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि National Industrial Credit (Long Term operations) Fund	915,00,00,000	(क) देशी (a) Internal	69,49,80,000
जमा राशियां:— Deposits:—		(ख) विदेशी (b) External
(क) सरकारी (a) Government	(ग) सरकारी खजाना बिल (c) Government Treasury Bills	959,20,31,000
(i) केन्द्रीय सरकार (i) Central Government	325,07,36,000	विदेशों में रखा हुआ धनाया Balances Held Abroad	1584,03,86,000
(ii) राज्य सरकारें (ii) State Governments	14,67,57,000	निवेश Investments**	932,26,84,000
(ख) बैंक (b) Banks		ऋण और अग्रिम:— Loans and Advances to:—	
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक Scheduled Commercial Banks	1868,24,83,000	(i) केन्द्रीय सरकार को Central Government
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक Scheduled State Co-operative Banks	29,21,41,000	(ii) राज्य सरकारों को State Governments@	93,50,51,000
(iii) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक Non-Scheduled State-Co-operative Banks	2,52,19,000	ऋण और अग्रिम:— Loans and Advances to:—	
(iv) अन्य बैंक Other Banks	2,26,37,000	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को Scheduled Commercial Banks†	216,72,57,000
(ग) अन्य (c) Others	1802,14,44,000	(ii) राज्य सहकारी बैंकों को State Co-operative Banks††	291,77,64,000
देय बिल Bills Payable	166,38,12,000	(iii) दूसरों को Others	4,72,00,000
अन्य देयताएं Other Liabilities	518,92,82,000	राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश Loans Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	
		(क) ऋण और अग्रिम:— (a) Loans and Advances to:—	
		(i) राज्य सरकारों को State Governments	110,71,97,000

(ii) राज्य सहकारी बैंकों को	
(ii) State Co-operative Banks.	17,79,37,000
(iii) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को	
Central Land Mortgage Banks	
(iv) कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम को	
Agricultural Refinance and Development Corporation	215,80,00,000
(ख) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश	
(b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures	7,72,37,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अग्रिम	
Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	
राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम	
Loans and Advances to State Co-operative Banks	132,68,47,000
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश	
Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	
(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम	
(a) Loans and Advances to the Development Bank	688,45,34,000
(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गए बांडों/डिबेंचरों में निवेश	
(b) Investment in Bonds/debentures issued by the Development Bank	..
अन्य आस्तियाँ	
Other Assets	1256,13,83,000
रुपये	
Rupees	6604,45,11,000

*मकदो, प्रावधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियाँ शामिल हैं।

Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

**राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं हैं।

Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

@राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से प्रवर्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं, परन्तु राज्य सरकारों को दिये गये अस्थायी ओवरड्राफ्ट शामिल हैं।

Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, but including temporary overdrafts to State Governments.

†भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17(4)(ग) के अन्तर्गत अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मीयादी बिलों पर अग्रिम दिये गये 2,76,00,000 रुपये शामिल हैं।

Includes Rs. 2,76,00,000 advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17 (4) (c) of the Reserve Bank of India Act.

‡राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रवर्त ऋण और अग्रिम नहीं हैं।

Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

दिनांक : 9 अगस्त, 1978

Dated the 9th day of August, 1978

आई० जी० पटेल, गवर्नर
I. G. PATEL, Governor,
[No. F. 10/1/78-BOI]

क्र.सं० 2674—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसरण में 1978 के विनांक 11 अगस्त को समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा
S.O. 2674.—An Account pursuant to the RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 for the week ended the 11th day of August, 1978

रुपू विभाग
ISSUE DEPARTMENT

देयताएं LIABILITIES	रुपये Rs.	रुपये Rs.	प्रास्तियां ASSETS	रुपये Rs.	रुपये Rs.
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट Notes held in the Banking Department	7,26,82,000		सोने का सिक्का और बुलियन:— Gold Coin and Bullion		
संचलन में नोट Notes in circulation	9234,41,41,000		(क) भारत में रखा हुआ (a) Held in India	214,21,78,000	
जारी किये गये कुल नोट Total Notes issued		9241,68,23,000	(ख) भारत के बाहर रखा हुआ (b) Held outside India		
			विदेशी प्रतिभूतियां Foreign Securities	2245,32,65,000	
			जोड़ Total		2459,54,43,000
			रुपये का सिक्का Rupee Coin		26,94,28,000
			भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां Government of India Rupee Securities		6755,19,52,000
			देशी चिन्तियम बिल और दूसरे बाणिज्य पत्र Internal Bills of Exchange and other commercial paper		
कुल देयताएं Total Liabilities		9241,68,23,000	कुल प्रास्तियां Total Assets		9241,68,23,000

विनांक 16 अगस्त, 1978
Dated the 16th day of August, 1978

आई.जी. पाटेल, गवर्नर
I.G. PATFL, Governor

11 अगस्त, 1978 को भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण

Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, Banking Department as on the 11th August, 1978

देयताएं LIABILITIES	रुपये Rs.	प्रास्तियां ASSETS	रुपये Rs.
धुक्ता पूंजी Capital Paid Up	5,00,00,000	नोट Notes	7,26,82,000
प्रारक्षित निधि Reserve Fund	150,00,00,000	रुपये का सिक्का Rupee Coin	3,24,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	610,00,00,000	छोटा सिक्का Small Coin	5,80,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	195,00,00,000	खरीदे और मुनाये गये बिल Bills Purchased and Discounted:—	
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि National Industrial Credit (Long Term Ope- rations) Fund	915,00,00,000	(क) देशी (a) Internal	61,13,61,000
		(ख) विदेशी (b) External	
		(ग) सरकारी खजाना बिल (c) Government Treasury Bills	1188,42,96,000

देयताएं Liabilities	रुपये Rs.	संपत्तियाँ Assets	रुपये Rs.
जमा राशियाँ:— Deposits:—		विदेशों में रखा हुआ बकाया Balances Held Abroad*	1504,00,64,000
(क) सरकारी (a) Government		निवेश Investments**	857,15,02,000
(i) केन्द्रीय सरकार (i) Central Government	435,98,38,000	ऋण और अग्रिम:— Loans and Advances to:—	
(ii) राज्य सरकारें (ii) State Governments	9,89,39,000	(i) केन्द्रीय सरकार को (i) Central Government	
(ख) बैंक (b) Banks		(ii) राज्य सरकारों को— (ii) State Governments@	149,43,53,000
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक (i) Scheduled Commercial Banks	1889,66,67,000	ऋण और अग्रिम:— Loans and Advances to:—	
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक (ii) Scheduled State Co-operative Banks	29,50,96,000	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को (i) Scheduled Commercial Banks†	222,05,80,000
(iii) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक (iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	2,32,74,000	(ii) राज्य सहकारी बैंकों को (ii) State Co-operative Banks‡	298,39,96,000
(4) अन्य बैंक (iv) Other Banks	2,00,74,000	(iii) दूसरों को (iii) Others	4,67,00,000
(ग) अन्य (c) Others	1776,02,82,000	राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	
देय बिल Bills Payable	164,82,39,000	(क) ऋण और अग्रिम:— (a) Loans and Advances to:—	
		(i) राज्य सरकारों को (i) State Governments	110,71,77,000
		(ii) राज्य सहकारी बैंकों को (ii) State Co-operative Banks	17,59,23,000
		(iii) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को (iii) Central Land Mortgage Banks	
		(4) कृषि पुनर्बिल और विकास निगम को (iv) Agricultural Refinance and Development Corporation	215,80,00,000
		(ख) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश (b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures	7,72,37,000
		राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अग्रिम Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	
		राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम Loans and Advances to State Co-operative Bank,	132,37,04,000

देयताएं Liabilities	₹. Rs.	आस्तियां Assets	₹. Rs.
अन्य देयताएं Other Liabilities.	520,88,93,000	राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश Loans, Advances and Investments from Na- tional Industrial Credit (Long Term Ope- rations) Fund (क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम (a) Loans and Advances to the Development Bank 688,80,35,000 (ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांडो/डिबेंचरों में निवेश (b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank अन्य आस्तियां Other Assets 1240,47,88,000	
रुपये Rupees	6706,13,02,000	रुपये Rupees	6706,13,02,000

*नकदी, आवधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं।

*Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

**राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि में से किए गए निवेश शामिल नहीं हैं।

**Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

@राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से प्रवस ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं, परन्तु राज्य सरकारों को दिये गये अस्थायी ओवरड्राफ्ट शामिल हैं।

@Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, but including temporary overdrafts to State Governments.

†भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17 (4) (ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मीयादी बिलों पर अग्रिम दिये गये 2,76,00,000 रुपये शामिल हैं।

† Includes Rs. 2,76,00,000 advanced to scheduled commercial banks against usance bills under section 17 (4) (c) of the Reserve Bank of India Act.

‡राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रवस ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं।

‡ Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

दिनांक 16 अगस्त, 1978

Dated the 16th day of August, 1978.

आई० जी० पटेल, गवर्नर

I.G. PATEL, Governor

[No. F. 10/1/78-BOI]

ब० ब० मीरचंदानी, प्रवर सचिव

C. W. MIRCHANDANI, Under Secy.

(विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

मुम्बई, 18 नवम्बर, 1977

क्र० प्रा० 2675.—विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 32 की उपधारा (11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिजर्व बैंक, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक एवं समीचीन है, यह निदेश देता है कि उपधारा (7) की कोई बात नेपाल और भूटान से भिन्न किसी देश को की जाने वाली विदेश यात्रा के लिए टिकट खरीदने को लागू नहीं होगी परन्तु यह तब जब यहाँ विनिविष्ट शर्तों का पालन किया जाए, अर्थात्:—

- (1) यात्री, प्रस्तावित विदेश यात्रा की तारीख से ठीक पूर्व के दो वर्षों की अवधि के दौरान, सिवाय नेपाल और भूटान के, भारत से बाहर न गया हो।
- (2) यात्रा, सामान्य सीधे मार्ग से विनिविष्ट गन्तव्य स्थान को और गन्तव्य स्थान से की जाएगी।
- (3) यात्री राजन्ड ट्रिप टिकट पर यात्रा करेगा।
- (4) यात्री, नीचे दी हुई अनुसूची में विनिविष्ट प्राधिकृत व्यवहारियों की किसी अधिसूचित शाखा में, सत्यापन के लिए और इस आशय का प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए कि वह विदेश यात्रा के लिए पात्र है, निम्नलिखित वस्तावेज प्रस्तुत करेगा, अर्थात्:—

(i) यात्री का वर्तमान पारपत्र और जहाँ आवश्यक हो वहाँ अवसित पारपत्र जिससे कि इस आदेश के अनुसार विदेश यात्रा के लिए पात्रता सिद्ध होती हो; और

(ii) सम्यक्तः भरा गया विहित घोषणापत्र, उतनी प्रतियों में जितनी विनिविष्ट की जाए और जिन पर उम अनु-ज्ञप्त को एयरलाइन/नौवहन कंपनी या यात्रा अभिकरण द्वारा, जिससे वह विदेश यात्रा के लिए यात्राटिकट खरीदना चाहता है, प्रतिहस्ताक्षर किए जाएं।

स्पष्टीकरण:—इस आदेश के प्रयोजनार्थ श्रीलंका, बंगला देश, मालदीव, मारिशस और सीशेलस को, किसी विशेष सुविधा का लाभ उठाकर की जाने वाली यात्राओं को विदेश यात्राओं के रूप में नहीं माना जाएगा। यह आदेश 1 दिसम्बर, 1977 से प्रभावी होगा।

अनुसूची

1. बैंक आफ बड़ोदा।
2. बैंक आफ इंडिया।
3. कनारा बैंक।
4. सेंट्रल बैंक आफ इंडिया।
5. इंडियन ओवरसीज बैंक।
6. पंजाब नेशनल बैंक।
7. भारतीय स्टेट बैंक।
8. सिंडीकेट बैंक।
9. यूनियन बैंक आफ इंडिया।
10. युनाइटेड कमर्शियल बैंक।

[आदेश सं० ई सी० सी प्रो० पी० एण्ड सी० 1/9-77]
एम० नरसिंहम, गवर्नर

(Exchange Control Department)

(Central Office)

Bombay, the 18th November, 1977

S.O. 2675.—In exercise of the powers conferred by sub-section (11) of Section 32 of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973, the Reserve Bank, being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby directs that nothing in sub-section (7) shall apply to the booking of passage for foreign travel to any country other than Nepal and Bhutan provided that the conditions specified herein are complied with, namely:—

- (1) Traveller has not gone out of India except to Nepal and Bhutan during the period of two years immediately preceding the date of the proposed foreign travel.
- (2) Travel shall be to and from a specified destination by normal direct route.
- (3) Traveller shall perform the journey on round trip ticket.
- (4) Traveller shall produce at any of the notified branches of the authorised dealers specified in the Schedule hereunder, for verification and obtaining a certificate to the effect that he is eligible for foreign travel, the following documents namely:—
(i) the current passport of the traveller and wherever necessary the expired passport to establish the eligibility for foreign travel in terms of this order, and
(ii) the prescribed declaration form duly completed in such number of copies as may be specified, and countersigned by licensed airline/shipping company or travel agency from whom he proposes to purchase the passage ticket for foreign travel.

Explanation: For the purpose of this order, visits to Sri Lanka, Bangladesh, Maldives, Mauritius and Seychelles availing of any special facility will not be treated as foreign visits

This order shall take effect from 1st December, 1977.

SCHEDULE

- (1) Bank of Baroda.
- (2) Bank of India.
- (3) Canara Bank.
- (4) Central Bank of India.
- (5) Indian Overseas Bank.
- (6) Punjab National Bank.
- (7) State Bank of India.
- (8) Syndicate Bank.
- (9) Union Bank of India.
- (10) United Commercial Bank.

[Order No. EC. CO. P&C/9-77]

M. NARASIMHAM, Governor.

मुम्बई, 6 जनवरी, 1978

क्र० प्रा० 2676.—विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 32 की उप-धारा (11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिजर्व बैंक अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक एवं समीचीन है, यह निदेश देता है कि उसके आदेश सं० ईसी० सीप्रो० पी० एण्ड सी-1/9-77, तारीख 18 नवम्बर, 1977 में तत्काल निम्नलिखित संशोधन किये जाएंगे, अर्थात्:—

उक्त आदेश में—

(1) शर्त सं० (1) के स्थान पर निम्नलिखित शर्त रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(i) इस आदेश के अनुसरण में या विदेश यात्रा स्कीम, 1970 के अधीन अनुदत्त सुविधाओं का लाभ उठाते हुए, यात्री ने पूर्ववर्ती कैलेंडर वर्ष के प्रारंभ से विदेश यात्रा न की हो।”

- (ii) विद्यमान स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् "स्पष्टीकरण : इस आदेश के प्रयोजनार्थ :—

(क) यह माना जाएगा कि यात्री ने उस वर्ष अपनी यात्रा प्रारंभ की है जब वह भारत से प्रस्थान करता है, चाहे उसके लौटने का वर्ष कुछ भी क्यों न हो;

(ख) इस आदेश के अधीन या विदेश यात्रा स्कीम, 1970 के अधीन उपलब्ध सुविधा का लाभ उठाकर की जाने वाली यात्राओं से अन्यथा यात्री द्वारा की जाने वाली विदेश यात्रा पर, इस आदेश के अधीन विदेश यात्रा के लिए उसकी पात्रता अवधारित करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा।"

[आदेश सं० ईसी० सीओ० पी० एण्ड सी-2/9-78]

पी० आर० नागिया, उप-राज्यपाल

Bombay, the 6th January, 1978

S.O. 2676.—In exercise of the powers conferred by sub-section (11) of Section 32 of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973, the Reserve Bank, being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby directs that the following amendments shall, with immediate effect, be made to its Order No. EC. CO. P&C. 1-9-77 dated November 18, 1977, namely :—

In the said order—

- (i) For the condition No. (1) the following shall be substituted, namely :—

"(1) Traveller has not undertaken foreign travel since the commencement of the previous calendar year availing of the facility granted pursuant to this order or under the Foreign Travel Scheme, 1970."

- (ii) For the existing Explanation the following shall be substituted, namely :—

"Explanation.—For the purpose of this order—

- (a) the traveller shall be deemed to have undertaken his travel in the year in which he leaves India irrespective of the year in which he returns;
- (b) a traveller's visits to a foreign country otherwise than by availing of the facility under this order or under Foreign Travel Scheme, 1970 shall not be taken into account for determining his eligibility for foreign travel under this Order."

[Order No. EC. CO. P&C. 2/9-78]

P. R. NAGIA, Dy. Governor.

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग विभाग)

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 1978

का०आ० 2677.—गोवा, दमण और दीव (बैंक पुनर्निर्माण) अधिनियम, 1962 की धारा 4(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 31 मार्च, 1978 की अधिसूचना संख्या 22(1)-बी०ओ० III/78 के सिल मिले में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि जब कभी बैंकों नेशनल अल्ट्रामेरिनो एंड बैंक्स इकोनॉमिका डी० गोवा के वर्तमान अभिरक्षक श्री बी० एन० नादकर्णी छुट्टी पर या नगर (स्टेशन) से बाहर जायेंगे तब श्री राम मोहन, एस०आर०बी० डिवीजन, भारतीय स्टेट बैंक, पणजी (गोवा) श्री बी०एन० नादकर्णी की अनुपस्थिति में, अभिरक्षक का कार्यभार चलाएंगे।

[संख्या 22(6)-बी०ओ० III/78]

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 29th July, 1978

S.O. 2677.—In exercise of the powers conferred under Regulation 4(1) of the Goa, Daman and Diu (Banks Reconstruction) Regulation, 1962, and in continuation of Notification No. 22(1) B.O. III/78, dated the 31st March, 1978 the Central Government hereby directs that whenever Shri V. N. Nadkarni, the present Custodian of Banco Nacional Ultramarino and Caixa Economica De Goa, proceeds on leave or goes out of station, Shri Ram Mohan, SIB Division, State Bank of India, Panaji (Goa) shall discharge the duties of the Custodian in the absence of Shri V. N. Nadkarni.

[No. 22(6)-B.O. III/78]

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 1978

का०आ० 2678.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सफारिश पर एतद्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (1) के उपबन्ध सिंडीकेट बैंक, नतीपाल पर, 6 जून, 1979 तक उस सीमा तक लागू नहीं होंगे, जहां तक कि उक्त उपबन्ध, इसके अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कर्नाटक स्माल इन्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड बंगलूर के निदेशक बनने पर इसविषये रोक लगाते हैं कि वह कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अन्तर्गत एक पंजीकृत कम्पनी है।

[सं० 15(15)-बी०ओ० III/78]

New Delhi, the 28th August, 1978

S.O. 2678.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 10 of the said Act shall not apply to the Syndicate Bank, Manipal upto 6th June 1979 in so far as the said provisions prohibit its Chairman and Chief Executive Officer from being a director of the Karnataka Small Industries Development Corporation Ltd., Bangalore, being a company registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956).

[No. 15(15)-B.O. III/78]

का०आ० 2679.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सफारिश पर, एतद्वारा घोषणा करती है कि उपर्युक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के उपबन्ध, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया पर, इस अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष तक की अवधि के लिए उस सीमा तक लागू नहीं होंगे, जहां तक कि उपर्युक्त उपबन्ध, बैंक पर मैन्स एसोसिएटेड पल्प एंड पेपर मिल्स लिमिटेड के 30 प्रतिशत से अधिक के शेयर अधिक के रूप में रखने पर रोक लगाते हैं।

[संख्या 15(17)-बी०ओ० III/78]

S.O. 2679.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-section (2) of section 19 of the said Act shall not apply to Central Bank of India for a period of two years from the date of notification in so far as the said provisions prohibit the bank from holding more than 30 per cent of shares in M/s. Associated Pulp & Paper Mills Ltd., as a pledges.

[No. 15(17)-B.O. III/78]

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1978

का० प्रा० 2680.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबन्ध, संघ शासित राज्य दिल्ली के पीसंगीपुर में 3 बीघा 12 बिसवा तथा संघ शासित राज्य दिल्ली में निकटवर्ती ग्राम असाहतपुर खादर में 1 बीघा की माप वाली जायदाद के मामले में, पंजाब एंड सिन्ध बैंक लिमिटेड पर 8 जून, 1979 तक लागू नहीं होंगे।

[संख्या 15(10)-बी०प्रो० III/78]

New Delhi, the 31st August, 1978

S.O. 2680.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of section 9 of the said Act shall not apply upto 8th June 1979 to the Punjab and Sind Bank Ltd. in respect of the properties measuring 3 Bighas 12 Biswas in Peasongipur, Union Territory of Delhi and 1 Bigha in adjoining village Asulatpur Khadar in the Union Territory of Delhi.

[No. 15(10)-B.O. III/78]

का० प्रा० 2681.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 19(2) के उपबन्ध इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया पर उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां तक उक्त उपबन्ध इस बैंक की गिरवीदार के रूप में एक्सें इलेक्ट्रो इंडस्ट्रीज प्रा० लिमिटेड के 30 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने पर रोक लगाते हैं।

[संख्या 15(18)-बी० प्रो० III/78]

S.O. 2681.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of section 19(2) of the said Act shall not apply for a period of one year from the date of this notification to the United Bank of India in so far as the said provisions prohibit the bank from holding more than 30 per cent shares of the Acme Electro Industries Pvt., Ltd., as pledges.

[No. 15(18)-B.O. III/78]

का० प्रा० 2682.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 2 के उपबन्ध, 31 मार्च, 1979 तक सिन्डनेज बैंक लिमिटेड, कलकत्ता पर इसके द्वारा गिरवीदार के रूप में रखे गये हैं, निम्नलिखित कम्पनियों के शेयरों पर, जैसा कि उनके नाम के आगे ही दिखाया गया है, लागू नहीं होंगे।

(लाख रुपयों में)

कम्पनी का नाम	गिरवी की तारीख	धारित शेयरों का चुकता मूल्य
(1) जे० के० ओटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	24-11-1966 03-02-1967	1.65 0.25
(2) ग्लोब यूनाइटेड इंजीनियरिंग एंड फाउंड्री कम्पनी लिमिटेड	20-11-1967 16-02-1968 16-03-1968	8.80 8.81 0.05

[संख्या 15(20)-बी०प्रो० III/78]

मे० प्रा० उसगांवकर, धनर सचिव

S. O. 2682.—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India hereby declares that the provisions of sub-Section 2 of Section 19 of the said Act shall not apply, till the 31st March 1979, to Grindlays Bank Ltd., Calcutta in respect of the shares held by it as pledgee of the undernoted companies as shown against their names.

(In lakhs of rupees)

Name of the company	Date of Lodgement	Paid up value of shares held
(1) Jay Kay Automobiles Pvt. Ltd.	24-11-1966 03-02-1967	1.65 0.25
(2) Globe United Engineering and Foundry Co. Ltd.	20-11-1967 16-02-1968 16-03-1968	8.80 8.81 0.05

[No. 15 (20)-B.O. III/78]

M. B. USGAONKAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1978

का० प्रा० 2683.—राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 (1951 का 63) की धारा 46 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निवेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 29, 30, 31, 32, 32अ, 32ब, 32ग, 32घ, 32ङ और 32च तमिलनाडु इंडस्ट्रीयल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मद्रास पर लागू होंगे।

[संख्या 11-35/74/आई० एफ० II]

एम० जी० गुप्ता, निदेशक

New Delhi, the 4th September, 1978

S.O. 2683.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 46 of the State Financial Corporations Act, 1951 (63 of 1951), the Central Government hereby directs that the provisions of sections 29, 30, 31, 32, 32B, 32C, 32D, 32E, and 32F of the said Act shall apply to the Tamil Nadu Industrial Investment Corporation Ltd., Madras.

[No. F. 11-35/77-IF.II]

M.G. GUPTA, Director.

वित्त मंत्रालय

(अधिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 1978

का० प्रा० 2684.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबन्ध 2 मार्च, 1978 से 1 मार्च, 1981 तक 3 वर्षों की अवधि के लिए महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड पर उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां तक उसका संबंध इस बैंक द्वारा साबनपुरा, सक्कर साथ और तवाबपुरा में कुछ गैर-बैंकिंग सम्पत्तियों अर्थात् 3 भवनों के स्वामी होने से है।

[संख्या 8/9/78-ए० सी०]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 6th September, 1978

S.O. 2684.—In exercise of the powers conferred by Section 53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) the Central Government on the recommendations of the Reserve Bank of India hereby declares that the provisions of Section 9 of the said Act shall not apply to the Maharashtra State Co-operative Bank Ltd., Bombay in so far as they relate to its holding of certain non-banking assets viz. 3 buildings at Amravati in Sabanpura, Sakkar Sath and Nababpura for a period of 3 years from 2 March 1978 to 1 March 1981.

[No. 8-9/78-AC]

का० प्रा० 2685.—बैंकारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबंध इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 1 मार्च, 1981 में बिष्णुपुर टाउन सहकारी बैंक लिमिटेड बिष्णुपुर पर उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहाँ तक उनका संबंध इस बैंक द्वारा पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के पी० एस० बिष्णुपुरमोजा मधुबन में खतियान संख्या 77 आर० एस० संख्या 18 में गैर-बैंकिंग परिसम्पत्तियों अर्थात् 30 डेसीमल भूमि के प्लॉट संख्या 842 और 76 डेसीमल भूमि के प्लॉट संख्या 845 का स्वामी होने से है।

[संख्या 8-9/78-ए० सी०]

S.O. 2685.—In exercise of the powers conferred by the section 53 read with section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of section 9 of the said Act shall not apply to the Bishnupur Town Co-operative Bank Ltd., Bishnupur in so far as they relate to its holding of non-banking assets viz. 30 decimals of land in plot no. 842 and 76 decimals of land in plot no. 845 both in Khatian No. 77, R. S. No. 18, Mauza-Madhuban, P. S. Bishnupur, District Bankura, West Bengal from the date of publication of this notification to 1 March 1981.

[No. 8-9/78-AC]

M. P. VARMA, Under Secy.

शुद्धि-पत्र

का० प्रा० 2686.—भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3 (ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० 8-9/79-ए० सी०, दिनांक 29 जून, 1978 में जो अशुद्धि रह गई थी निम्न प्रकार शुद्ध की जाती है :—

“(होनायर ताफुका)” के वाद और “और कागलगांव” से पूर्व, शब्द “मगनाशिनी” के स्थान पर “मघनाशिनी” पढ़ा जाए।

[संख्या 8-9/78-ए० सी०]

एम० पी० वर्मा, अध्वर सचिव

नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

प्रवेश

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 1978

का० प्रा० 2687.—संबंधी विश्व फास्टनर्स, जिला सुरेन्द्रनगर, गुजरात को स्वतन्त्र विदेशी मुद्रा के मुद्दे रूप से पूंजीगत माल के आयात के लिए 84,730 रु० (\$9439) का एक आयात लाइसेंस सं० पी/सीजी/2070962/सी/एसएस/61/एच/41-42, दिनांक 1-12-76 प्रदान किया गया था। उन्होंने उक्त लाइसेंस की अनुसूचि सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि लाइसेंस की मूल सीमा-शुल्क

प्रयोजन प्रति सुरेन्द्र नगर से बम्बई यात्रा करते समय खो गई है। भागे यह भी बताया गया है कि आयात लाइसेंस किसी भी सीमा-शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत कराये बिना और बिल्कुल ही प्रयुक्त हुए बिना खो गया है। अपने तर्क के समर्थन में, लाइसेंसधारी ने नोटरी पब्लिक गुजरात राज्य के सम्मुख विधिवत शपथ लेकर स्टैम्प पेपर पर एक शपथ-पत्र दाखिल किया है।

2. तदनुसार, मैं संतुष्ट हूँ कि फर्म से लाइसेंस की मूल-सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई है। इसलिए, यथासंशोधित आयात (नियंत्रण) अधिनियम, 1955, दिनांक 7-12-55 के उप खंड 9 (सी० सी०) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर सर्वोच्च विश्व फास्टनर्स, सुरेन्द्रनगर को जारी किए गए आयात लाइसेंस सं० पी०/सी जी०/2070902, दिनांक 1-12-76 को मूल सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति एतद्द्वारा रद्द की जाती है।

3. पार्टी को उक्त आयात लाइसेंस का दूसरा लाइसेंस (केवल सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रयुक्त अलग से जारी किया जा रहा है।

[सं० सी० जी० 4/1806(75)(13)/432]

MINISTRY OF COMMERCE & CIVIL SUPPLIES
AND CO-OPERATION

(Deptt. of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 30th August, 1978

S.O. 2687.—M/s. Kuick Fasteners, Distt. Surendranagar, Gujarat were granted an Import Licence No. P/CG/2070962/C/XX/H/41-42 dated 1-12-76 for Rs. 84,730 (\$ 9439) for the import of capital goods from U.S.A. against free foreign exchange. They have applied for issue of a Duplicate Customs Purposes Copy of said licence on the ground that the original Customs Purposes Copy of the licence has been lost while travelling from Surendranagar to Bombay. It has further been stated that the import licence has been lost without having been registered with any Customs authority and utilised at all. In support of their contention, the licence have filed an affidavit on Stamped Paper duly sworn before a Notary Public, Gujarat State.

2. I am, accordingly, satisfied that the original Customs Purposes copy of the licence has been lost by the firm. Therefore, in exercise of the powers conferred under Sub-clause 9(cc) of the Import (Control) order, 1955 dated 7-12-55, as amended, the said original Customs Purposes Copy of Import Licence No. P/CG/2070902 dated 1-12-1976 issued to M/s. Kuick Fasteners, Surendranagar is hereby cancelled.

3. A duplicate licence (Customs Purposes Copy only) of the said import licence is being issued to the party separately.

[No. CG. IV/1806(75)(13)/432]

प्रवेश

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1978

का० प्रा० 2688.—संबंधी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली की ब्रिटेन/अमेरिका/पश्चिमी जर्मनी/स्विट्जरलैंड से मूल उपकरणों के आयात के लिए 10,42,466 रु० (दस लाख ब्यालिस हजार चार सौ छियासठ हजार मात्र) का एक आयात लाइसेंस संख्या आई/सी जी/2033-908/एम/आई ए/67/एच/78/सी जी-2/एस एस, दिनांक 6-6-78 प्रदान किया गया था। उन्होंने उक्त लाइसेंस की अनुसूचि सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति और मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमा-शुल्क एवं मुद्रा विनियम प्रयोजन प्रतियां खो गई/अस्थानस्थ हो गई हैं। भागे यह भी बताया गया है कि मूल सीमा-शुल्क एवं मुद्रा विनियम प्रयोजन प्रतियां बिल्कुल भी प्रयुक्त नहीं हुई थी और इसमें 10,42,466 रु० की राशि शेष थी।

2. इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने नोटरी पब्लिक के सम्मुख विधिवत शपथ लेकर एक शपथ पत्र दाखिल किया है।

3. तदनुसार, मैं सन्तुष्ट हूँ कि उक्त लाइसेंस की ये मूल सीमा शुल्क एवं मुद्रा विनियम प्रयोजन प्रतियाँ खो गई हैं। इसलिए, यथासंशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 दिनांक 7-12-59 के उप-खण्ड-9 (सी.सी.) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, नई दिल्ली को जारी किए गए लाइसेंस संख्या आई/सी.जी./2033908, दिनांक 6-6-78 की उक्त मूल सीमा शुल्क एवं मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रयोजन प्रतियाँ एतद्वारा रद्द की जाती हैं।

4. उक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमा शुल्क एवं मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रयोजन प्रतियाँ लाइसेंसधारी को अलग से जारी की जा रही हैं।

[मिनिज संख्या सी.जी.-2/एच.आई./10/78-79/932]

जी० एस० ग्रेवाल, उभ मुख्य नियंत्रक,
कृते मुख्य नियंत्रक

New Delhi, the 1st September, 1978

S.O. 2688.—M/s. Bharat Heavy Electricals Ltd. New Delhi were granted an import licence No. 1/CG/2033908/S/1A/67/H/78/CGII/LS dated 6-6-78 for Rs. 10,42,466 (Rupees ten lakhs forty two thousand four hundred and sixty six only) for import of capital equipment from UK/USA/West Germany/Switzerland. They have applied for the issue of a duplicate Customs Purposes Copy and Exchange Control Purpose copy of the said licence on the ground that the original Customs and Exchange purposes copies have been lost/misplaced. It is further stated that the original Customs and Exchange purposes copies were not utilised at all and the balance available on it was Rs. 10,42,466.

2. In support of this contention, the application has filed an affidavit duly sworn in before Notary, Trichi.

I am accordingly satisfied that this original Customs and Exchange purpose copies of the said licence has been lost. Therefore in exercise of the powers conferred under Sub-Clause 9(OO) of the Import (Control) order 1955 dated 7-12-59 as amended the said original Customs and Exchange Control Purposes copies of the Licence No. 1/CG/2033908 dt. 6-6-78 issued to M/s. Bharat Heavy Electricals Ltd New Delhi are hereby cancelled.

3. The duplicate Customs and Exchange Control Purposes copies of the said licence are being issued separately to the licensee.

[No. CGII/HI/10/78-79/952]

G. S. GREWAL, Dy. Chief Controller

For Chief Controller

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 1978

का०भा० 2689.—खादी तथा अन्य हथकरघा उद्योग विकास (वस्त्र पर प्रतिरिक्त उत्पादन शुल्क) अधिनियम 1953 (1953 का 12) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने सुनिश्चित किया है कि निम्नलिखित स्पष्टीकरण की धारा 1(2) के अन्तर्गत जोड़ दिया जाये जो कि का०भा० सं० 657 (ई०) दिनांक 7 अक्टूबर, 1976 को प्रकाशित की गई थी।

स्पष्टीकरण.—इन संशोधित नियमों को पूर्वव्यापी संज्ञा देने के कारण निम्नलिखित है :—

प्रसंस्कृत रेयन तथा कृत्रिम रेयन वस्त्र केन्द्रीय उत्पाद तथा नमक अधिनियम 1944 के अन्तर्गत निर्धारित उत्पादन शुल्क से मुक्त थे किन्तु खादी तथा अन्य हथकरघा उद्योग विकास (वस्त्र पर प्रतिरिक्त उत्पाद शुल्क) अधिनियम 1953 के अन्तर्गत लगाये जाने वाले प्रतिरिक्त उत्पाद शुल्क (हथकरघा उपकर) से मुक्त नहीं थे। मार्च 1, 1975 को तयकृत नियमों को अधिसूचित करने के बाद बुने हुये बोरों के माल से एच०डी०पी०ई० वस्त्रों का उत्पादन होने लगा। इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि ये वस्त्र केवल पैकिंग के लिये ही प्रयोग किये गये थे न कि पहनने के लिये, इसलिये ये वस्त्र हथकरघा उपकर के कर, जो कि 1 मार्च, 1975 से लगाया जाना था, से मुक्त किये जाने के लिये थे। का०भा० 657(ड) के अन्तर्गत अधिसूचना द्वारा स्पष्टीकरण किया जाता है और एच०डी०पी०ई० बुने हुये वस्त्रों की स्थिति को नियमित आधार पर रखा जाता है।

[का० सं० 12011/1/77-एफ० एंड ए०]

दावत राम, उप सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 21st August, 1978

S.O. 2689.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of Section 5 of the Khadi and other Handloom Industries Development (Additional Excise Duty on Cloth) Act, 1953 (12 of 1953), the Central Government has decided that the following may be added as explanation under Rule 1(2) published vide S. O. No. 657 (E) dated 7th October, 1976.

Explanation.—The reasons for giving retrospective effect to the Amendment Rules are as follows. The processed rayon or artificial silk fabrics were exempt from the duty of excise leviable under the Central Excise and Salt Act, 1944 but, were, however, not exempt from Additional Excise Duty (Handloom Cess) leviable under the Khadi and Other Handloom Industries Development (Additional Excise Duty on 1st March, 1975, HDPE fabrics which formed woven on 1st March, -975, HDPE fabrics which formed woven sack-material came into production. Having regard to the fact that these fabrics were used exclusively for packing purposes and not for clothing, these fabrics were intended to be exempt from the levy of the handloom cess which was leviable from 1st March, 1975. The notification under S.O. 657(E) seeks to clarify and place the position with regard to HDPE woven fabrics on a regular footing.

[F. No. 12011/1/77-F&A]

DAULAT RAM, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1978

का०भा० 2690.—केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि केन्द्रीय सिल्क बोर्ड अधिनियम 1948 (1948 का 61वाँ) की धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (ड) के अनुसरण में, राज्य सभा ने केन्द्रीय सिल्क बोर्ड के सदस्य के रूप में 16 अगस्त, 1978 से सेवा करने के लिए राज्य सभा के निम्नलिखित दो सदस्यों को चुना है :—

1. श्रीमती अजीजा हमाम

2. श्री एन० टोमयोक सिंह

[का० सं० 25012/24/76-सिल्क]

एस० वेणुगोपालन, निदेशक

New Delhi, the 31st August, 1978

S.O. 2690.—The Central Government hereby notify that the Rajya Sabha has, in pursuance of clause (c) of sub-section (3) of Section 4 of the Central Silk Board Act, 1948

(61 of 1948), elected the following two members of the Rajya Sabha with effect from 16th August, 1978 to serve as members of the Central Silk Board :—

1. Shrimati Aziza Imam
2. Shri Ng. Tempok Singh

[F. No. 25012/24/76-Silk]
S. VENUGOPALAN, Director

आदेश

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1978

का.प्र. 2691/15/उ० वि० प्र०/78.—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास विनियम) अधिनियम 1951 (1951 का 65 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० प्र० 461 (अ) तारीख 22 जुलाई, 1978 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश में, अंतिम पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

“उपर्युक्त निकाय 25 सितम्बर, 1978 से पूर्व अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा।”

[फा० सं० 2(40)/78-सी० यू० सी०]
आर० आर० पाहवा, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th September, 1978

S.O. 2691/15/IDRA/78.—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S. O. 641(E) dated 22nd July, 1978, namely :—

In the said Order, for the last paragraph, the following paragraph shall be substituted, namely :—

“The above body shall submit its report to the Central Government before the 25th September, 1978.”

[File No. 2/40/78-CUC]

R. R. PAHWA, Under Secy.

पेट्रोलियम, रसायन और उर्ध्वक मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 28 अगस्त 1978

का.प्र. 2692.—यसः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप नं० 90 से जी० जी० एस-III तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों की बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब, पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आयोग सक्षम अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बवोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आशय करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

कूप नं० 90 से जी० जी० एस-III तक पाइप लाइन बिछाने के लिए
राज्य : गुजरात जिला : खेड़ा तालुका : मातर

गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर ए आर सेन्टीयर ई
पानसोली	215/4	0 02 63
	214/2	0 02 40
	214/1	0 04 80
	213/2	0 02 18
	218/2-3	0 09 85
	211/2	0 03 15
	211/1 पो	0 02 53
		0 01 80
	220/2	0 06 83
	220/1	0 04 28
	223	0 04 80
	244/2	0 03 35
	244/1	0 04 50
	244/3	0 12 16
	245	0 05 10

[सं० 12016/8/78-प्र० 4]

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS & FERTILIZER

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 28th August, 1978

S. O. 2692.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from well No. 90 to G. G. S. III in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission

And Whereas, it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of right of user in a land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-9;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Acquisition of R. O. U. for Laying pipeline from well No. 90 to GGS—III

State : Gujarat	District : Kaira	Taluka : Matar		
Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
PANSOLI	215/4	0	02	63
	214/2	0	02	40
	214/1	0	04	80
	213/2	0	02	18
	218/2-3	0	09	85
	211/2	0	03	15
	211/1P	0	02	53
	Cart-track	0	01	80
	220/2	0	06	83
	220/1	0	04	28
	223	0	04	80
	244/2	0	03	35
	244/1	0	04	50
	244/3	0	12	16
	245	0	05	10

[No. 12016/8/78—Prod. IV]

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 1978

क्रा० प्रा० 2693—भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहाँ संलग्न अनुसूची में प्रदर्शित किया गया है और पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाइन (प्रयोगकर्ता भूमि अधिग्रहण अधिकार) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है गुजरात राज्य के मेहसाणा तेल क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि में बेधान सं० — स्थल डी० के से जी०जी० एस एससी बी सोकासण-1 तक पेट्रोलियम के लिए भूमि उपयोग के अधिकार प्राप्त किये गए हैं तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपर्युक्त नियम के खण्ड 7 के उपखण्ड (1) की धारा (1) में निर्दिष्ट कार्य विनांक 30-4-74 से समाप्त कर दिया गया है।

अतः अब पेट्रोलियम पाइप लाइन के नियम (प्रयोगकर्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) नियम, 1963 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी एतद्-द्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्ति की तिथि अधिसूचित करते हैं।

अनुसूची

एस डी के से एस सी टी से जी जी एम सोभा 1 तक पाइप लाइन कार्य की समाप्ति

संस्थालय का नाम	गाँव	क्रा० प्रा० सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक	हेबुवा	1108	9-4-77	30-4-74

[सं० 12016/5/78-प्रो०-I]

New Delhi, the 30th August, 1978.

S.O. 2693—Whereas by the notification of Government of India as shown in scheduled appended hereto and issued under sub-section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in land) Act, 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule

appended thereto for the transport of petroleum from d.s. SDK to SCB to GGS-sob-1 in Mehasana oil field in Gujarat State

And Whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub-section (1) of section 7 of the said Act on 30-4-74.

Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of user in land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of operation of Pipeline from DS. SDK to SCB to GGS Sob-1

Name of Ministry	Villages	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Petroleum, Chemicals & Fertilizer	Hebua	1108	9-4-77	30-4-78

क्रा० प्रा० 2694—भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहाँ संलग्न अनुसूची में प्रदर्शित किया गया है और पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाइन (प्रयोगकर्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है गुजरात राज्य के डबका तेल क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि में बेधान स्थल सं० जीसी०एस डबका से ए० बी० जी० एल वाल्व प्लेट फार्म तक पेट्रोलियम के लिये भूमि उपयोग के अधिकार प्राप्त किए गए हैं।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपर्युक्त नियम के खण्ड 7 के उपखण्ड (1) की धारा (1) में निर्दिष्ट कार्य विनांक 25-6-78 से समाप्त कर दिया गया है।

अतः अब पेट्रोलियम पाइप लाइन के नियम (प्रयोगकर्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) नियम, 1963 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी एतद् द्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्ति की तिथि अधिसूचित करते हैं।

अनुसूची

जी० सी० एस० डबका से ए० बी० जी० एल० वाल्व प्लेट फार्म तक पाइप लाइन कार्य की समाप्ति

संस्थालय का नाम	गाँव	क्रा० प्रा० सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक	जलालपुर मोभा गाँवसया	2080	15-7-79	25-6-78

[सं० 12016/5/78-प्रो०-II]

S.O. 2694 Whereas by the notification of Government of India as shown in schedule appended hereto and issued under sub-section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in lands) Act, 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from d.s. DABKA GCS to ABGL VALVE PLAT FORM in DABKA oil field in Gujarat State.

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub-section (1) of section 7 of the said Act on 25-6-78.

Now therefore, under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of user in land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of operation of Pipeline From DABKA GCS to ABGL Valve Platform.

Name of Ministry	Villages	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation.
Petroleum, Chemicals & Fertilizer	Jalalpur Mobha Gawasad	2080	15-7-78	25-6-78

[No. 12016/5/78-Prod-II]

का० आ० 2695.—भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा जैसा कि वहाँ संलग्न अनुसूची में प्रदर्शित किया गया है और पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (प्रयोगकर्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के डबका तेल क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि में वेधान स्थल सं० डबका जी० सी० ए० से ए० बी० जी० ए० वाल्व प्लेट फार्म तक पेट्रोलियम के लिए भूमि उपयोग के अधिकार प्राप्त किये गए हैं।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपर्युक्त नियम के खण्ड 7 के उपखण्ड (1) की धारा (1) में निर्दिष्ट कार्य दिनांक 25-6-78 और 30-6-78 से समाप्त कर दिया गया है।

अतः अब पेट्रोलियम पाइप लाइन के नियम (प्रयोगकर्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) नियम, 1963 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी एतद्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्ति की तिथि अधिसूचित करते हैं।

अनुसूची

डबका जी० सी० ए० से ए० बी० जी० ए० वाल्व प्लेट फार्म तक पाइप लाइन कार्य की समाप्ति

मंत्रालय का नाम	गाँव	का० आ० सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक	सरसावनी आमला साधी (सर्वे नं० 452, 453 और सड़क के लिये)	2081	15-7-78	25-6-78
	साधी (सर्वे नं० 453, 452 और सड़क के सिवाय) आंती			30-6-78
	अम्बाडा (सर्वे नं० 120 और 109 के सिवाय)			25-6-78
	अम्बाडा (सर्वे नं० 120 और 109 के लिये) राजपुरा			

[सं० 12016/5/78-प्रो० III]

S.O.—2695. Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (1) of Section 6 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of right of user in land) Act, 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from DABKA GCS to ABGL VALVE PLATFORM in DABKA oil field in Gujarat State.

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub-section (1) of section 7 of the said Act on 25-6-78 and 30-6-78.

Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of user in land) Rules, 1963 the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of Operation of Pipeline from DABKA GCS to ABGL Valve Platform

Name of Ministry	Villages	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Petroleum, Chemicals & Fertilizer	SARSAVANI AMLA SADHI (for Sr. Nos. 452, 453 & Road)	2081	15-7-78	25-6-78
	SADHI (except Sr. Nos. 453, 452 & Road) ANTI AMBADA (except Sr. Nos. 120 & 109).			30-6-78
	AMBADA (for Sr. Nos. 120 & 109) RAJUPURA			25-6-78

[No. 12016/5/78-Prod-III]

का० आ० 2696.—भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा जैसा कि वहाँ संलग्न अनुसूची में प्रदर्शित किया गया है और पेट्रोलियम और खनिज लाइन प्रयोगकर्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया गुजरात राज्य के मेहसाणा तेल क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि में वेधान स्थल सं० — एन के बीजे से एन एनए तक पेट्रोलियम के लिये भूमि उपयोग के अधिकार प्राप्त किए गए हैं।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपर्युक्त नियम के खण्ड 7 के उपखण्ड (1) की धारा (1) में निर्दिष्ट कार्य दिनांक 9-2-77 से समाप्त कर दिया गया है।

अतः अब पेट्रोलियम पाइप लाइन के नियम प्रयोगकर्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार नियम, 1963 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी एतद्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्ति तिथि अधिसूचित करते हैं।

अनुसूची

शेन के बी जे से श्रेय शेन शेन तक पाइप लाइन कार्य की समाप्ति

मंत्रालय का नाम	गाँव	का० प्रा० सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
पेट्रोलियम रसायन	तेलावा	2075	15-7-78	9-2-77
और उर्वरक	हेबुवा			

[सं० 12016/5/78, प्रो० IV]

S.O. 2696.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in land Act, 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from d.s. MKBT to SNA in Mehsana oil field in Gujarat State.

And Whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub section (1) of section 7 of the said Act on 9-2-77.

Now Therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of user in land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of Operation of Pipeline From D.S. NKBJ to SNA

Name of Ministry	Villages	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Petroleum, Chemicals & Fertilizer	Telavi lipura	2075	15-7-78	9-2-77

[No. 12016/5/78-Prod.-IV]

का० प्रा० 2697—भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहाँ संलग्न अनुसूची में प्रदर्शित किया गया है और पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाइन प्रयोगकर्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के मेहसाणा तेल क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि में वेधान स्थल सं० एस० डी० एफ० से जी० जी० एस० कम सी० टी० एफ० सोमासन तक पेट्रोलियम के लिये भूमि उपयोग के अधिकार प्राप्त किये गए हैं।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपर्युक्त नियम के खण्ड 7 के उपखण्ड (1) की धारा (1) में निर्दिष्ट कार्य दिनांक 15-1-78 से समाप्त कर दिया गया है।

अतः अब पेट्रोलियम पाइप लाइन के नियम (प्रयोगकर्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) नियम, 1963 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी एतद्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्ति की तिथि अधिसूचित करते हैं।

581 GI/78—4

अनुसूची

एस० डी० एफ० से जी० जी० एस० कम सी० टी० एफ० सोमासन तक पाईप लाइन कार्य की समाप्ति

मंत्रालय का नाम	गाँव	का० प्रा० सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
पेट्रोलियम रसायन	हेबुवा	2078	15-7-78	15-1-78
और उर्वरक				

[सं० 12016/5/78 प्रो० V]

S.O. 2697.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in land Act, 1962 the right of user has been acquired hereto and issued under sub section (1) of section 6 of the in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from d.s. SDF to GGS in CTF Sob in Mehsana oil field in Gujarat State.

AND WHEREAS the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub section (1) of section 7 of the said Act on 15-1-68.

NOW THEREFORE under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of user in land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of Operation of Pipeline from D.S. SDF to GGS in CTF Sob

Name of Ministry	Villages	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Petroleum, Chemicals & Fertilizer	Hebuva Punasan	2078	15-7-78	15-1-78

[No. 12016/5/78-Prod.-V]

का० प्रा० 2698—भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहाँ संलग्न अनुसूची में प्रदर्शित किया गया है और पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाइन (प्रयोगकर्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है गुजरात राज्य के मेहसाणा तेल क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि में वेधान स्थल सं० —— से सी० सी० से श्रेय तक पेट्रोलियम के लिये भूमि उपयोग के अधिकार प्राप्त किये गए हैं।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपर्युक्त नियम के खण्ड 7 के उपखण्ड (1) की धारा (1) में निर्दिष्ट कार्य दिनांक 1-1-76 से समाप्त कर दिया गया है।

अतः अब पेट्रोलियम पाईप लाइन के नियम (प्रयोगकर्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) नियम, 1963 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी एतद्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्ति की तिथि अधिसूचित करते हैं।

अनुसूची

ग्रेस डी सी से ग्रेस बी क्षेत्र तक पाइप लाइन कार्य की समाप्ति

मंत्रालय का नाम	गांव	का. आ. सं.	भारत के कार्य समाप्ति राजपत्र में की तिथि प्रकाशन की तिथि	
पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक	पुनासन जगुदन	2076	15-7-78	1-1-76

[सं. 12016/5/78-प्रो. VI]

एस० एम० वाई० नदिम, अवर सचिव

S. O. 2698 :— Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in land) Act, 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from d.s. SDC to SBX in Mehsana oil field in Gujarat State.

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub section (1) of section 7 of the said Act on 1-1-76.

Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of user in land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of Operation of Pipeline from D.S. SDC to SBX

Name of Ministry	Villages	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Petroleum, Chemicals & Fertilizer	Punasan Jagudan	2076	15-7-78	1-1-76

[No. 12016/5/78-Prod.-VI]

S.M.Y. NADEEM, Under Secy.

स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 अगस्त 1978

का. आ. 2699—भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा-2 की उपधारा (2) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् एतद्वारा उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अनुसूची में:—

(1) इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों में "ओटोमीरिनो लेरिंगालोजी में डिप्लोमा छी० एल० प्रो०" प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि रख ली जाए, अर्थात् :—

"मास्टर आफ सर्जरी (आर्थोपेडिक्स) एम० एस० (आर्थो)"

(2) ए० पी० सिंह विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों में "मास्टर आफ सर्जरी (आप्यलमालोजी) —एम० एस० (आप्यलमालोजी)" प्रविष्टि के साथ निम्नलिखित प्रविष्टि रख ली जाए अर्थात् :—

"मास्टर आफ सर्जरी (एनाटोमी) —एम० एस० (एनाटोमी)"

(3) बरहामपुर विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों में "डॉक्टर आफ मेडिसिन (पैथालोजी) —एम० डी० (पैथालोजी)" प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां रख ली जाएं, अर्थात् :—

"मास्टर आफ सर्जरी (एनाटोमी) —एम० एस० (एनाटोमी)"

(4) भोपाल विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों में "मास्टर आफ सर्जरी (एनाटोमी) —एम० एस० (एनाटोमी)" प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां रख ली जाएं, अर्थात् :—

"मास्टर आफ सर्जरी (आम्सट्रैटिक्स एण्ड ग्यानाकालोजी) —एम० एस० (आम्सट्रैटिक्स एण्ड ग्यानाकालोजी)"

डॉक्टर आफ मेडिसिन (आम्सट्रैटिक्स एण्ड ग्यानाकालोजी) —एम० डी० (आम्सट्रैटिक्स एण्ड ग्यानाकालोजी)"

(5) बिहार विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों में "मास्टर आफ सर्जरी (ओटोरीनो लेरिंगालोजी) —एम० एस० ओटोरीनो लेरिंगालोजी)"

प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां रख ली जाएं, अर्थात् :—

"मास्टर आफ सर्जरी (आप्यलमालोजी) —एम० एस० (आप्यलमालोजी)"

डॉक्टर आफ मेडिसिन (फोरेन्सिक मेडिसिन) —एम० एस० (फोरेन्सिक मेडिसिन)।

(6) बम्बई विश्वविद्यालय संबंधी प्रविष्टियों में "डिप्लोमा इन आप्यलमालोजी —डी० प्रो०" प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि रख ली जाएं, अर्थात् :—

"मास्टर आफ सर्जरी (आप्यलमालोजी) —एम० एस० (आप्यलमालोजी)।

डॉक्टर आफ मेडिसिन (पाडियाट्रिक्स) —एम० डी० (पाडियाट्रिक्स)

डॉक्टर आफ मेडिसिन (पैथालोजी) —एम० डी० (पैथालोजी)

मास्टर आफ सर्जरी (आर्थोपेडिक्स) —एम० एस० (आर्थो)

* डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोलोजी डाइग्नोसिस—डी० एम० प्रार० डी०

* 30 अप्रैल, 1979 से पहले प्रदान करने पर यह अर्हता एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी।

(7) बी० एन० चक्रवर्ती विश्वविद्यालय संबंधी प्रविष्टियों में "डॉक्टर आफ मेडिसिन (सोशल एण्ड प्रिवेंटिव मेडिसिन) —एम० डी० (सोशल एण्ड प्रिवेंटिव मेडिसिन) प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां रख ली जाएं, अर्थात् :—

"मास्टर आफ सर्जरी (जनरल सर्जरी) ... एम० एस० (जनरल सर्जरी)

डॉक्टर आफ मेडिसिन (पैथालोजी) ... एम० डी० (पैथालोजी)

डॉक्टर आफ मेडिसिन (मेडिसिन) —एम० डी० (मेडिसिन)"

(8) कलकत्ता विश्वविद्यालय संबंधी प्रविष्टियों में "डॉक्टर आफ मेडिसिन (फिजिआलोजी)—एम० डी० (फिजिआलोजी)" प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां रख ली जाएं, अर्थात् :—

डिप्लोमा इन आप्यलमालोजी—डी० धो० (पीडियाट्रिक्स) डॉक्टर आफ मेडिसिन (पीडियाट्रिक्स)—एम० डी० (पीडियाट्रिक्स) मास्टर आफ सर्जरी (एनाटोमी)—एम० एस० (एनाटोमी)

(9) दिल्ली विश्वविद्यालय संबंधी प्रविष्टियों में "डिप्लोमा इन वेनरालोजी एण्ड डर्माटोलोजी—डी० सी० डी०" प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि रख ली जाए, अर्थात् :—

"डिप्लोमा इन आटोलोजी एण्ड लेरिगलोजी—डी० एल० धो०"
3 अप्रैल, 1979 को या इससे पहले प्रदान करने पर यह अर्हता एक मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी।

(10) जबलपुर विश्वविद्यालय संबंधी प्रविष्टियों में डॉक्टर आफ मेडिसिन (फिजिआलोजी)—एम० डी० (फिजिआलोजी), प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि रख ली जाए, अर्थात् :—

मास्टर आफ सर्जरी (सर्जरी)—एम० एस० (सर्जरी),

(11) काकतिआ विश्वविद्यालय संबंधी प्रविष्टियों में "बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी...एम० बी० बी० एस०", प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि रख ली जाए अर्थात् :—

"डिप्लोमा इन क्लिनिकल पैथालोजी—डी० सी० पी०",

(12) कर्नाटक विश्वविद्यालय संबंधी प्रविष्टियों में "डॉक्टर आफ मेडिसिन (फार्माकालोजी)...एम० डी० (फार्माकालोजी)" प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां रख ली जाएं, अर्थात् :—

"डॉक्टर आफ मेडिसिन (फिजिआलोजी)...एम० डी० (फिजिआलोजी)
डिप्लोमा इन क्लिनिकल पैथालोजी—डी० सी० पी०",

(13) केरल विश्वविद्यालय संबंधी प्रविष्टियों में "डिप्लोमा इन आप्यलमालोजी...डी० धो०", प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां रख ली जाएं अर्थात् :—

"डॉक्टर आफ मेडिसिन (पीडियाट्रिक्स)—एम० डी० (पीडियाट्रिक्स)
डिप्लोमा इन साइकालोजीकल मेडिसिन—डी० पी० एम०

डॉक्टर आफ मेडिसिन (फोरेंसिक मेडिसिन)—एम० डी० (फोरेंसिक मेडिसिन)

मास्टर आफ सर्जरी (पीडियाट्रिक्स सर्जरी)—एम० सी० एच० (पीडियाट्रिक्स सर्जरी) "

(14) कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय संबंधी प्रविष्टियों में "डॉक्टर आफ मेडिसिन (सोशल एण्ड प्रिवेंटिव मेडिसिन)...एम० डी० प्रविष्टि के बाद (सोशल एण्ड प्रिवेंटिव मेडिसिन)" प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां रख ली जाएं, अर्थात् :—

"मास्टर आफ सर्जरी (जनरल सर्जरी)—एम० एस० (जनरल सर्जरी)
डॉक्टर आफ मेडिसिन (पैथालोजी)—एम० डी० (पैथालोजी)
डॉक्टर आफ मेडिसिन (मेडिसिन)—एम० डी० (मेडिसिन)"

(15) ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय संबंधी प्रविष्टियों में "बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी—एम० बी० बी० एस०" प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां रख ली जाएं, अर्थात् :—

"मास्टर आफ सर्जरी (आप्यलमालोजी)—एम० एस० (आप्यलमालोजी)
डॉक्टर आफ मेडिसिन (फोरेंसिक मेडिसिन)—एम० डी० (फोरेंसिक मेडिसिन)

डॉक्टर आफ मेडिसिन (पैथालोजी)—एम० डी० (पैथालोजी)

डॉक्टर आफ मेडिसिन (मेडिसिन)—एम० डी० (मेडिसिन)

डॉक्टर आफ मेडिसिन (मेडिसिन एण्ड ग्यानां)...एम० डी० मिड एण्ड गहनां)

डॉक्टर आफ मेडिसिन (फार्माकालोजी)—एम० डी० (फार्माकालोजी)
डॉक्टर आफ मेडिसिन (फिजिआलोजी)—एम० डी० (फिजिआलोजी)
डॉक्टर आफ मेडिसिन (फिजिआलोजी एण्ड मेडिसिन)—एम० डी० (फिजिआलोजीकल मेडिसिन)

मास्टर आफ सर्जरी (एनाटोमी)—एम० एस० (एनाटोमी)
मास्टर आफ सर्जरी (सर्जरी)—एम० एस० (सर्जरी)

मास्टर आफ सर्जरी (मिड एण्ड गहनां)—एम० एस० (मिड एण्ड गहनां)

मास्टर आफ सर्जरी (आउसट्रिटिक्स एण्ड गहनाकालोजी)—एम० डी० (आउसट्रिटिक्स एण्ड गहनाकालोजी)

मास्टर आफ सर्जरी (ई०एन०टी०)एम०एस० (ई०एन०टी०)
डॉक्टर आफ मेडिसिन (एनेस्थीजीआलोजी)—एम०एस० (एनेस्थीजीआलोजी)

(16) एम०एस० विश्वविद्यालय बड़ौदा से संबंधित प्रविष्टियों में "डॉक्टर आफ मेडिसिन (फिजिआलोजी)—एम० डी० (फिजिआलोजी)" प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि रख ली जाए, अर्थात् :—

"डॉक्टर आफ मेडिसिन (एनेस्थीसिया)—एम० डी० (एनेस्थीसिया)"

(17) एम०एस० बड़ौदा विश्वविद्यालय और इससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित विश्वविद्यालय और प्रविष्टियां रख ली जाएं, अर्थात् :—

"महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय

मास्टर आफ सर्जरी (जनरल सर्जरी)—एम०एस० (जनरल सर्जरी)
बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी—एम० बी० बी० एस०
डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ—डी० सी० एच०

मास्टर आफ सर्जरी (आर्थोपेडिक्स)—एम०एस० (आर्थोपेडिक्स)

डॉक्टर आफ मेडिसिन (पीडियाट्रिक्स)—एम० डी० (पीडियाट्रिक्स)

डॉक्टर आफ मेडिसिन (वेनरालोजी और वेनराली समेत डर्माटोलोजी)
एम० डी० वेनरालोजी और वेनराली समेत (डर्माटोलोजी)

मास्टर आफ सर्जरी (आप्यलमालोजी)—एम०एस० (आप्यलमालोजी)

मास्टर आफ सर्जरी (ई०एन०टी०)—एम०एस० (ई०एन०टी०)

डॉक्टर आफ मेडिसिन (आउसट्रिटिक्स और गहनाकालोजी)—एम० डी० (आउसट्रिटिक्स और गहनाकालोजी)

डिप्लोमा इन एनेस्थीसियालोजी—डी० ए०

डॉक्टर आफ मेडिसिन (सोशल एण्ड प्रिवेंटिव मेडिसिन)—एम० डी० (सोशल और प्रिवेंटिव मेडिसिन)

डॉक्टर आफ मेडिसिन (पैथालोजी)—एम० डी० (पैथालोजी)

डॉक्टर आफ मेडिसिन (मेडिसिन)—एम० डी० (मेडिसिन)

18. मिथिला विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों में बैचलर आफ मेडिसिन और बैचलर आफ सर्जरी—एम० बी० बी० एस०" प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां रख ली जाएं, अर्थात् :—

मास्टर आफ सर्जरी (आप्यलमालोजी)—एम०एस० (आप्यलमालोजी)

डॉक्टर आफ मेडिसिन (फोरेंसिक मेडिसिन)—एम० डी० (फोरेंसिक मेडिसिन)

डॉक्टर आफ मेडिसिन (पैथालोजी)—एम० डी० (पैथालोजी)

डॉक्टर आफ मेडिसिन (मेडिसिन)—एम० डी० (मेडिसिन)

डॉक्टर आफ मेडिसिन (मिडवाइकरी और ग्यानाकालोजी)—एम० डी० मिडवाइकरी और ग्यानाकालोजी)

डाक्टर आफ मेडिसिन (फरमाकालोजी)—एम०डी० (फरमाकालोजी)
 डाक्टर आफ मेडिसिन (फिजिआलोजी)—एम०डी० (फिजिआलोजी)
 डाक्टर आफ मेडिसिन (फिजिआलोजीकल मेडिसिन)—एम०डी०
 (फिजिआलोजीकल मेडिसिन)

मास्टर आफ सर्जरी (एनाटोमी)—एम०एस० (एनाटोमी)

मास्टर आफ सर्जरी (सर्जरी)—एम०एस० (सर्जरी)

मास्टर आफ सर्जरी (मिड०एण्ड गइना०)—एम०एस० (मिड०एण्ड गइना०)

मास्टर आफ सर्जरी (ब्राह्मटेड्रिक्स एण्ड गइनाकालोजी)—एम०डी०
 (ब्राह्मटेड्रिक्स एण्ड गइनाकालोजी)

मास्टर आफ सर्जरी (ई०एन०टी०)—एम०एस० (ई०एन०टी०)

डाक्टर आफ मेडिसिन (एनेस्थेसियालोजी)—एम०डी० (एनेस्थेसियालोजी)

(19) नागार्जुन विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों में "बैचलर
 आफ मेडिसिन और बैचलर आफ सर्जरी—एम०बी०बी०एस०" प्रविष्टि
 के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रख ली जायें, अर्थात्:—

डाक्टर आफ मेडिसिन (जनरल मेडिसिन)—एम०डी० (जनरल मेडिसिन)

डाक्टर आफ मेडिसिन (बैक्टिरियोलोजी सहित पैथोलोजी)—एम०
 डी० (बैक्टिरियोलोजी सहित पैथोलोजी)

डाक्टर आफ मेडिसिन (डर्माटोलोजी)—एम०डी० (डर्माटोलोजी)

डाक्टर आफ मेडिसिन (ब्राह्मटेड्रिक्स और गइनाकालोजी)—एम०
 डी० (ब्राह्मटेड्रिक्स और गइनाकालोजी)

मास्टर आफ सर्जरी (जनरल सर्जरी)—एम०एस० (जनरल सर्जरी)

मास्टर आफ सर्जरी (एनाटोमी)—एम०एस० (एनाटोमी)

मास्टर आफ सर्जरी (आप्यलमालोजी)—एम०एस० (आप्यलमालोजी)

मास्टर आफ सर्जरी (ई०एन० टी०)—एम०एस० (ई०एन०टी०)

डिप्लोमा इन आप्यलमालोजी—डी०ओ०

डिप्लोमा इन एनेस्थेसियालोजी—डी०ए०

डिप्लोमा इन गइनाकालोजी और ब्राह्मटेड्रिक्स—डी०जी०ओ०

डिप्लोमा इन मैडिकल रेडियोलोजी और डाइग्नोसिस—
 डी०एम०आर०डी०",

(20) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से संबंधित प्रविष्टियों में
 "राष्ट्रीय आयु विज्ञान (मनचिकित्सा) अकादमी की सवस्थता"
 एम०एन०ए० एम० एस० (मनचिकित्सा) प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित
 प्रविष्टियाँ रख ली जायें, अर्थात्:—

"मेम्बरशिप आफ दी नेशनल एकडमी आफ मैडिकल साइंसिस
 (पैडियाट्रिक्स)—एम०एन०ए०एम०एस० (पैडियाट्रिक्स)

मेम्बरशिप आफ दी नेशनल एकडमी आफ मैडिकल साइंसिस
 (आर्थोपेडिक्स)—एम०एन०ए०एम०एस० (आर्थोपेडिक्स)

मेम्बरशिप आफ दी नेशनल एकडमी आफ मैडिकल साइंसिस (रेडियो-
 डाइग्नोसिस)—एम०एन०ए०एम०एस० (रेडियोडाइग्नोसिस)

मेम्बरशिप आफ दी नेशनल एकडमी आफ मैडिकल साइंसिस
 (रेडियोथेरापी)—एम०एन० एम०एस० (रेडियोथेरापी)

मेम्बरशिप आफ दी नेशनल एकडमी आफ मैडिकल साइंसिस (हेल्थ
 एडमिनिस्ट्रेशन)—एम०एन०ए०एम०एस० (हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन)"

(21) पंजाब विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों में "मास्टर
 आफ सर्जरी (प्लास्टिक सर्जरी)—एम०सी०एच० (प्लास्टिक सर्जरी)"
 प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि रख ली जायें, अर्थात्:—

डाक्टर आफ मेडिसिन (एनेस्थेसियालोजी)—एम०डी० (एनेस्थेसिय
 लोजी)

(22) राजस्थान विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों में "डाक्टर
 आफ मेडिसिन" (ब्राह्मटेड्रिक्स एण्ड गइनाकालोजी)—एम०डी०
 (ब्राह्मटेड्रिक्स एण्ड गइनाकालोजी)" प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित
 प्रविष्टियाँ रख ली जायें, अर्थात्:—

"डाक्टर आफ मेडिसिन (एनेस्थेसियालोजी)—एम०डी० (एनेस्थे-
 सियालोजी)

मास्टर आफ सर्जरी (एनेस्थेसियालोजी)—एम०डी० (एनेस्थेसियालोजी)
 डिप्लोमा इन मैडिकल रेडियोलोजी डाइग्नोसिस—डी०एम०आर०डी०

*डाक्टर आफ मेडिसिन (रेडियोलोजी)—एम०डी० (रेडियोलोजी)

*यदि यह अर्हता 30 अप्रैल, 1979 से पूर्व प्रदान की गई हो तो
 इसे मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता माना जायेगा",

(23) राजी विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों में "मास्टर
 आफ सर्जरी (एनाटोमी —एम०एस० एनाटोमी) प्रविष्टि के बाद
 निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रख ली जायें, अर्थात्:—

"डाक्टर आफ मेडिसिन (पैथोलोजी)—एम०एडी० (पैथोलोजी)

डाक्टर आफ मेडिसिन (पीडियाट्रिक्स)—एम०डी० (पीडियाट्रिक्स)

डाक्टर आफ मेडिसिन (फार्माकालोजी)—एम०डी० (फार्माकालोजी)

*यदि यह अर्हता 30 अप्रैल, 1979 से पूर्व प्रदान की गई हो तो इसे
 एक मान्यता प्राप्त अर्हता माना जायेगा।"

(24) रविशंकर विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों में "डाक्टर
 आफ मेडिसिन (पैथोलोजी)—एम०डी० (पैथोलोजी)" प्रविष्टि के बाद
 निम्नलिखित प्रविष्टि रख ली जायें, अर्थात्:—

"मास्टर आफ सर्जरी (आप्यलमालोजी)—एम०एस० (आप्यलमालोजी)

(25) रोहतक विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों में "डाक्टर
 आफ मेडिसिन (सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन)—एम०डी० (सोशल एण्ड
 प्रिवेंटिव मेडिसिन)" प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रख ली
 जायें, अर्थात्:—

"मास्टर आफ सर्जरी (जनरल सर्जरी)—एम०एस० (जनरल सर्जरी)

डाक्टर आफ मेडिसिन (पैथोलोजी)—एम०डी० (पैथोलोजी)

डाक्टर आफ मेडिसिन (मैडिसिन)—एम०डी० (मैडिसिन)",

(26) सम्बलपुर विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों में "डाक्टर
 आफ मेडिसिन (ब्राह्मटेड्रिक्स एण्ड गइनाकालोजी)—एम०डी० (ब्राह्मटे-
 ड्रिक्स एण्ड गइनाकालोजी)" प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि रख
 ली जायें, अर्थात्:—

"डाक्टर आफ मेडिसिन (फार्माकालोजी)—एम०डी० (फार्माकालोजी)",

(27) शिवाजी विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों में "बैचलर आफ
 मेडिसिन और बैचलर आफ सर्जरी—एम०बी०बी०एस०" प्रविष्टि के बाद
 निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रख ली जायें, अर्थात्:—

डाक्टर आफ मेडिसिन (फार्माकालोजी)—एम०डी० (फार्माकालोजी)

"डाक्टर आफ मेडिसिन (ब्राह्मटेड्रिक्स एण्ड गइनाकालोजी)—एम०डी०
 (ब्राह्मटेड्रिक्स एण्ड गइनाकालोजी)",

डिप्लोमा इन ब्राह्मटेड्रिक्स एण्ड गइनाकालोजी—डी०जी०ओ०",

(28) उत्कल विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों में "डिप्लोमा
 इन बाइरुड हेल्थ डी०सी०एच०" प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि
 रख ली जायें अर्थात्:—

"मास्टर आफ सर्जरी (आप्यलमालोजी)—एम०एस० (आप्यलमालोजी)"

[सं० बी०-11015/7/78-एम०ई० (सीति)]

आर०बी० श्रीनिवासन, उप सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 24th August, 1978

S.O. 2699.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 11 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Central Government, after consulting the Medical Council of India, hereby makes the following further amendments in the First Schedule to the said Act, namely :—

In the said Schedule :—

(i) In the entries relating to University of Allahabad, after the entry "Diploma in Oto-rhino Laryngology..... D.L.O.", the following entry shall be inserted, namely :—

"Master of Surgery (Orthopaedics).....M.S. (Ortho)";

(ii) in the entries relating to A. P. Singh University, after the entry "Master of Surgery (Ophthalmology).....M.S. (Ophthalmology)", the following entry shall be inserted, namely :—

"Master of Surgery (Anatomy).....M.S. (Anatomy)";

(iii) in the entries relating to Berhampur University, after the entry "Doctor of Medicine (Pathology).....M.D. (Pathology)", the following entries shall be inserted, namely :—

"Master of Surgery (Anatomy).....M.S. (Anatomy)";

(iv) in the entries relating to Phopal University, after the entry "Master of Surgery (Anatomy).....M.S. (Anatomy)", the following entries shall be inserted, namely :—

"Master of Surgery (Obstetrics & Gynaecology)..... M.S. (Obst. & Gyne.)"

Doctor of Medicine (Obstetrics & Gynaecology)..... M.S. (Obst. & Gyne.)";

(v) in the entries relating to Bihar University, after the entry "Master of Surgery of (Otorhinolaryngology)..... M.S. (Otorhinolaryngology)", the following entries shall be inserted, namely :—

"Master of Surgery (Ophthalmology).....M.S. (Ophth.)"

Doctor of Medicine (Forensic Medicine).....M.D. (Forensic Medicine).

(vi) in the entries relating to University of Bombay, after the entry "Diploma in Ophthalmology.....D.O.", the following entry shall be inserted, namely :—

"Master of Surgery (Ophthalmology).....M.S. (Ophth.)"

Doctor of Medicine (Paediatrics).....M.D. (Paed.)

Doctor of Medicine (Pathology).....M.D. (Path.)

Master of Surgery (Orthopaedics).....M.S. (Ortho.)

*Diploma in Medical Radiology Diagnosis..... D.M.R.D.

*This qualification shall be recognised medical qualification when granted before the 30th April, 1979";

(vii) in the entries relating to B. N. Chakravarty University after the entry "Doctor of Medicine (Social and Preventive Medicine).....M.D. (Soc. Prev. Med.)", the following entries shall be inserted, namely :—

"Master of Surgery (General Surgery).....M.S. (Genl. Surgery)"

Doctor of Medicine (Pathology).....M.D. (Path.)

Doctor of Medicine (Medicine).....M.D. (Med.)";

(viii) in the entries relating to Calcutta University, after the entry "Doctor of Medicine (Physiology).....M.D. (Physiology)", the following entries shall be inserted, namely :—

(Physiology)", the following entries shall be inserted, namely :—

"Diploma in (Ophthalmology).....D.O.

Doctor of Medicine (Paediatrics).....M.D. (Paed.)

Master of Surgery (Anatomy).....M.S. (Anatomy)";

(ix) in the entries relating to Delhi University, after the entry "Diploma in Venerology & Dermatology.....D.V.D.", the following entry shall be inserted, namely :—

"Diploma in Otology & Laryngology.....D.L.O.

This qualification shall be a recognised medical qualification when granted on or before 30th April, 1979";

(x) In the entries relating to Jabalpur University, after the entry "Doctor of Medicine (Physiology).....M.D. (Physiology)", the following entry shall be inserted, namely :—

"Master of Surgery (Surgery).....M.S. (Surgery)";

(xi) in the entries relating to Kakatiya University, after the entry "Bachelor of Medicine & Bachelor of SurgeryM.B.B.S.", the following entry shall be inserted, namely :—

"Diploma in Clinical Pathology.....D.C.P.";

(xii) in the entries relating to Karnatak University, after the entry "Doctor of Medicine (Pharmacology).....M.D. (Pharm.)", the following entries shall be inserted, namely :—

"Doctor of Medicine (Physiology).....M.D. (Physiology)"

Diploma in Clinical Pathology.....D.C.P.";

(xiii) in the entries relating to Kerala University, after the entry "Diploma in Ophthalmology.....D.O.", the following entries shall be inserted, namely :—

"Doctor of Medicine (Paediatrics).....M.D. (Paed.)"

Diploma in Psychological Medicine.....D.P.M.

Doctor of Medicine (Forensic Medicine).....M.D. (Forensic Medicine)

Master of Surgery (Paediatric Surgery).....M.Ch. (Paed. Surgery)";

(xiv) in the entries relating to Kurushetra University, after the entry "Doctor of Medicine (Social and Preventive Medicine).....M.D. (Soc. & Prev. Med.)", the following entries shall be inserted, namely :—

"Master of Surgery (General Surgery).....M.S. (General Surgery)";

Doctor of Medicine (Pathology).....M.D. (Path.)

Doctor of Medicine (Medicine).....M.D. (Medicine)";

(xv) in the entries relating to Lalit Narayan Mithila University, after the entry "Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery.....M.B.B.S.", the following entries shall be inserted, namely :—

"Master of Surgery (Ophthalmology).....M.S. (Ophth.)"

Doctor of Medicine (Forensic Medicine).....M.D. (Forensic Medicine)

Doctor of Medicine (Pathology).....M.D. (Path.)

Doctor of Medicine (Medicine).....M.D. (Med.)

Doctor of Medicine (Mid. & Gynae.).....M.D. (Mid. & Gynae.)

Doctor of Medicine (Pharmacology).....M.D. (Pharm.)

Doctor of Medicine (Physiology).....M.D. (Phys.)

Doctor of Medicine (Psychological Medicine)..... M.D. (Psych. Med.)

Master of Surgery (Anatomy).....M.S. (Anatomy)

Master of Surgery (Surgery).....M.S. (Surgery)
 Master of Surgery (Mid. & Gynae.).....M.S. (Mid. and Gynae.)
 Master of Surgery (Obstetrics & Gynaecology).....M.D. (Obst. & Gynae.)
 Master of Surgery (E.N.T.).....M.E. (E.N.T.)
 Doctor of Medicine (Anaesthesiology).....M.D. (Anaes.)"

(xvi) in the entries relating to M.S. University of Baroda, after the entry "Doctor of Medicine (Physiology).....M.D. (Physiology)", the following entry shall be inserted, namely :—

"Doctor of Medicine (Anaesthesia).....M.D. (Anaes.)";

(xvii) after the M. S. University of Baroda and the entries relating thereto the following university and the entries shall be inserted, namely :—

"Maharshi Dayanand University.

Master of Surgery (General Surgery).....M. S. (General Surgery).

Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery.....M.B.B.S.

Diploma in Child Health.....D.C.H.

Master of Surgery (Orthopaedics).....M.S. (Ortho).

Doctor of Medicine (Paediatrics).....M.D. (Paed.)

Doctor of Medicine (Dermatology including Ven. & bprosy).....M.D. (Derm. including Ven. & bprosy).

Master of Surgery (Ophthalmology).....M.S. (Ophth.)

Master of Surgery (E.N.T.).....M.S. (E.N.T.)

Doctor of Medicine (Obstetrics & Gynaecology).....M.D. (Obst. & Gynae.)

Diploma in Anaesthesiology.....D.A.

Doctor of Medicine (Soc. & Prev. Medicine).....M.D. (Soc. & Prev. Med.)

Doctor of Medicine (Pathology).....M.D. (Path.)

Doctor of Medicine (Medicine).....M.D. (Medicine)";

(xviii) in the entries relating to Mithila University, after the entry "Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery.....M.B.B.S.", the following entries shall be inserted, namely :—

"Master of Surgery (Ophthalmology).....M.S. (Ophth.)

Doctor of Medicine (Forensic Medicine).....M.D. (Forensic Med.)

Doctor of Medicine (Pathology).....M.D. (Path.)

Doctor of Medicine (Medicine).....M.D. (Med.)

Doctor of Medicine (Mid. & Gynae.).....M.D. (Mid. & Gynae.)

Doctor of Medicine (Pharmacology).....M.D. (Pharm.)

Doctor of Medicine (Physiology).....M.D. (Phys.)

Doctor of Medicine (Psychological Medicine).....M.D. (Psych. Med.)

Master of Surgery (Anatomy).....M.S. (Anatomy)

Master of Surgery (Surgery).....M.S. (Surgery)

Master of Surgery (Mid. & Gynae.).....M.S. (Mid. and Gynae.)

Master of Surgery (Obstetrics & Gynaecology).....M.D. (Obst. & Gynae.)

Master of Surgery (E.N.T.).....M.S. (E.N.T.)

Doctor of Medicine (Anaesthesiology).....M.D. (Anaes.)";

(xix) in the entries relating to Nagarjuna University, after the entry "Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery....

.....M.B.B.S.", the following entries shall be inserted, namely :—

"Doctor of Medicine (General Medicine).....M.D. (Gen. Med.)

Doctor of Medicine (Pathology including Bacteriology).....M.D. (Path. including Bacteriology).

Doctor of Medicine (Dermatology).....M.D. (Derm.)

Doctor of Medicine (Obstetrics & Gynaecology).....M.D. (Obst. & Gynae.)

Master of Surgery (General Surgery).....M.S. (Gen. Surgery)

Master of Surgery (Anatomy).....M.S. (Anat.)

Master of Surgery (Ophthalmology).....M.S. (Ophth.)

Master of Surgery (E.N.T.).....M.S. (E.N.T.)

Diploma in Ophthalmology.....D.O.

Diploma of Anaesthesiology.....D.A.

Diploma in Gynaecology and Obstetrics.....D.G.O.

Diploma in Medical Radiology & Diagnosis.....D.M.R.D."

(xx) in the entries relating to National Board of Examinations New Delhi, after the entry "Membership of National Academy of Medical Sciences (Psychiatry).....M.N.A.M.S. (Psychiatry)", the following entries shall be inserted, namely :—

Membership of the National Academy of Medical Sciences (Paediatrics).....M.N.A.M.S. (Paed.)

Membership of the National Academy of Medical Sciences (Orthopaedics).....M.N.A.M.S. (Ortho.)

Membership of the National Academy of Medical Sciences (Radio-Diagnosis).....M.N.A.M.S. (Radio-Diag.)

Membership of the National Academy of Medical Sciences (Radio-Therapy).....M.N.A.M.S. (Radio-Therapy)

Membership of the National Academy of Medical Sciences (Health Administration).....M.N.A.M.S. (Health Admn.)"

(xxi) in the entries relating to the Punjab University, after the entry "Master of Surgery (Plastic Surgery).....M.Ch. (Plastic Surgery)", the following entry shall be inserted, namely :—

"Doctor of Medicine (Anaesthesiology).....M.D. (Anaes.)";

(xxii) in the entries relating to the University of Rajasthan after the entry "Doctor of Medicine (Obstetrics & Gynaecology).....M.D. (Obst. & Gynae.)", the following entries shall be inserted, namely :—

"Doctor of Medicine (Anaesthesiology).....M.D. (Anaes.)

Master of Surgery (Anaesthesiology).....M.S. (Anaes.)

Diploma in Medical Radiology Diagnosis.....D.M.R.D.

*Doctor of Medicine (Radiology).....M.D. (Radiology).

*This qualification shall be recognised medical qualification when granted before 30th April, 1979";

(xxiii) in the entries relating to Ranchi University, after the entry "Master of Surgery (Anatomy).....M.S. (Anatomy)", the following entries shall be inserted, namely :—

"*Doctor of Medicine (Pathology).....M.D. (Path.)

Doctor of Medicine (Paediatrics).....M.D. (Paed.)

Doctor of Medicine (Pharmacology).....M.D. (Pharm.)

*This qualification shall be recognised medical qualification when granted before 30th April, 1979";

(xxiv) in the entries relating to Ravishankar University, after the entry "Doctor of Medicine (Pathology).....M.D. (Path.)", the following entry shall be inserted, namely :—

"Master of Surgery (Ophthalmology).....M.S. (Ophth.)";

(xxv) in the entries relating to the Rohtak University, after the entry "Doctor of Medicine (Social and Preventive Medicine).....M.D. (Soc. & Prev. Med.)", the following entries shall be inserted, namely :—

"Master of Surgery (General Surgery).....M.C. (Gen. Surgery)

Doctor of Medicine (Pathology).....M.D. (Path.)

Doctor of Medicine (Medicine).....M.D. (Med.)

(xxvi) in the entries relating to Sambalpur University, after the entry "Doctor of Medicine (Obstetrics & Gynaecology).....M.D. (Obst. & Gynae.)", the following entry shall be inserted, namely :—

"Doctor of Medicine (Pharmacology).....M.D. (Pharm.)";

(xxvii) in the entries relating to Shivaji University, after the entry "Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery.....M.B.B.S.", the following entries shall be inserted, namely :—

'Doctor of Medicine (Pharmacology).....M.D. (Pharm.)

Doctor of Medicine (Obstetrics & Gynaecology).....M.D. (Obst. & Gynae.)

Diploma in Obstetrics & Gynaecology.....D.G.O.";

(xxviii) in the entries relating to Utkal University, after the entry "Diploma in Child Health.....D.C.H.", the following entry shall be inserted, namely :—

"Master of Surgery (Ophthalmology).....M.S. (Ophth.)"

[No. V. 11015/7/78-M.E. (Policy)]

R. V. SRINIVASAN, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 1978

क्रा० प्र० 2700.—केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (बंगलौर) की नियमावली 1976 के नियम 1 के उप-नियम (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित क्षेत्र निधिष्ट करती है जिन पर ये नियम 16 दिसम्बर, 1977 से लागू होंगे, अर्थात् :—

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय जयानगर (संख्या 6) संख्या 21/2/1, 9 मेन, 14वां क्रॉस, 111 ब्लॉक, जयानगर, बंगलौर-560011.

इस औषधालय की सीमा :

उत्तर पूर्व में लाल बाग रोड के संगम से हासुर रोड तक नाले से घिरा हुआ क्षेत्र,

पूर्व में बेनेरागुट्टा रोड और एनेकल रोड से खूबी खर फैक्ट्री तक होसुर रोड (नाले) से घिरा हुआ क्षेत्र,

दक्षिण में खूबी खर फैक्ट्री से कनकपुरा रोड तक 100 फीट रिंग रोड से घिरा हुआ क्षेत्र, कनकपुरा रोड, कांडरेना हाहली रोड से कांडरेना हाहली ग्राम तक का क्षेत्र;

पश्चिम में कांडरेनाहाहली ग्राम से मैसूर बैंक कालोनी बस स्टाप तक पावर लाइन से घिरा हुआ क्षेत्र (इसको तोका कोडरेनाहाहली, बन शंकरा स्टेज II, त्यागराजनगर, अशोक नगर होगी);

उत्तर पश्चिम में मैसूर बैंक कालोनी बस स्टाप से कांधेरगुप्पे रोड तक विक रोड से घिरा हुआ क्षेत्र, कांधेर गुप्पे रोड से अशोक नगर के 6ठें क्रॉस तक, अशोक नगर के 6ठें क्रॉस से एन० प्र० कालोनी के 7वें क्रॉस की ओर नेटकालप्पा सर्किल तक, दीवान माधव राव रोड, कनकपुरा

रोड का कुछ भाग (के० प्र० पार्क के सामने), कृष्णराव रोड से लाल बाग रोड वेस्ट तक, कुम्भीगल रोड लालबाग रोड से नाले तक का क्षेत्र।

निम्नलिखित क्षेत्र जो पहले बासवान गुड्डी औषधालय के अन्तर्गत आते थे, अब वे जयानगर औषधालय के अन्तर्गत आएंगे :—

1. बिस्मन गार्डन
2. चिन्नेना पाट्या
3. सिद्धापुरा
4. जयानगर
5. 7वें क्रॉस के दक्षिण की ओर एन० प्र० कालोनी का भाग।
6. दीवान माधव राव रोड और नेटकालप्पा सर्किल के दक्षिण की ओर का बासवान गुड्डी का भाग।
7. टाटा सिल्क फार्म
8. बाइरासांद्रा
9. तिलक नगर
10. येडियुर नागासांद्रा
11. त्यागराज नगर

उपरोक्त क्षेत्रों के अलावा अनुसूची 'क' में दिए गए निम्नलिखित प्रतिरिक्त क्षेत्र भी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय जयानगर (संख्या 6) के अन्तर्गत आएंगे।

सूची 'क'

1. बाइरासांद्रा विस्तार
2. मारानहाहली
3. सारासकी अप्रहारा
4. सारासकी
5. कांडरेना हाहली
6. बनशंकरा II स्टेज

व्याख्यात्मक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (बंगलौर) नियमावली, 1976 के अनुसरण में बंगलौर के कतिपय प्रतिरिक्त क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना 16 दिसम्बर, 1977 से प्रारम्भ की गई थी। किन्तु कतिपय अपरिहार्य कारणों की वजह से इस संबंध में आवश्यक सूचना अधि जारी करने में देर हो गई। अतः एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि इस योजना को प्रस्तावित पिछली तारीख से लागू करने से किसी व्यक्ति के हित पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[संख्या एस० 11012/3/78-के० स० स्वा० यी० (नीति)]

रा० क० जिनंदल, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd September, 1978

S.O. 2700.—In pursuance of sub-rule (3) of rule 1 of the Central Government Health Scheme (Bangalore) Rules, 1976, the Central Government hereby specifies the following areas to which the said rules shall extend with effect from the 16th December, 1977, namely :—

CGHS DISPENSARY JAYANAGAR (No. 6) No. 21/2/1,
IX MAIN, 14TH CROSS, III BLOCK, JAYA-
NAGAR, BANGALORE-560011.

Area bounded :

In the North East by the drain from the junction of Lal Bagh Road upto Hosur Road,

In the East by Hosur Road (from drain), Bannerghatta Road and Anekal Road upto Ruby Rubber Factory.

In the South by 100 ft. Ring Road from Ruby Rubber Factory to Kanakapura Road, Kanakapura Road, Kaderena Halli Road, upto Kaderenhalli village ;

In the West by the power-line from Kaderenhalli village upto Mysore Bank Colony Bus-Stop (bounding Kaderenhalli, Banashankri Stage II, Thyagarajanagar, Ashok Nagar);

In the North West by Link Road from Mysore Bank Colony Bus-stop upto Katherguppe Road, Katherguppe Road upto 6th Cross of Ashok Nagar, 6th Cross of Ashok Nagar leading to 7th Cross of N.R. Colony upto Netkalappa Circle, Diwan Madhava Rao Road, Part of Kanakapura Road (opposite to K.R. Park), Krishna Rao Road upto Lal bagh Gate West, Krumbigal Road, Lalbagh Road upto Drain.

The undermentioned areas which were previously covered by Basavangudi Dispensary will now be covered by Jayanagar Dispensary.

1. Wilson Garden
2. Chinnaina palya
3. Siddapura
4. Jayanagar
5. Part of N.R. Colony falling to the South of 7th Cross.
6. Part of Basavangudi, falling to South of Diwan Madhava Rao Road and Netkalappa Circle.
7. Tata Silk Farm
8. Pyrasandra
9. Tilak Nagar
10. Yediyur Nagasandra
11. Thyagaraja nagar

Apart from the above areas, the undermentioned additional areas given in Schedule 'A' will be covered by the CGHS Dispensary Jayanagar (No. 6).

Schedule 'A'

1. Byrasandra Extension
2. Maranahalli
3. Sarakki Agrahara
4. Sarakki
5. Kaderenhalli
6. Banashankri II Stage

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government Health Scheme was extended to certain additional areas of Bangalore in pursuance of Central Government Health Scheme (Bangalore) Rules, 1976 with effect from 16th December, 1977. However the issue of necessary notification notifying the same was delayed due to certain unavoidable reasons. It is hereby declared that the proposed retrospective effect will not adversely affect the interest of any body.

[No. S. 11012/3/78-CGHS(P)]

R. K. JINDAL, Under Secy.

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1978

कां.प्रां. 2701.—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन जारी की गई, भारत सरकार के भूतत्त्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं. कां.

कां.प्रां. 252.—तारीख 15 जनवरी, 1956 के अनुसरण में, उक्त अधिसूचना से उपावद्ध अनुसूची "क" में वर्णित 3310.30 बीघा माप की भूमि को तथा अनुसूची "ख" में वर्णित 1372.44 बीघा माप की भूमि में खनिजों के खनन, खदान, बेधन, खोदायी, तलाश, निष्कासन, उन पर कार्य करने तथा उनकी हवाई करने के अधिकार को अर्जित कर लिया है।

श्री राम नगोना उपाध्याय के पुत्र श्री कमलाचन्द्र उपाध्याय उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन हितवद्ध व्यक्ति हैं; इन्होंने प्रतिकर के संवाय के लिये सक्षम प्राधिकारी को दावा किया है और राज्य सरकार के प्राधिकारियों द्वारा किये गए अधिप्राप्ति के अनुसार उसके पक्ष में उक्त अर्जित क्षेत्र में से 1.69 एकड़ क्षेत्र के लिए प्रतिकर निर्धारित हुआ है।

उक्त अर्जन के लिए संवेद्य प्रतिकर की राशि करार द्वारा निश्चित नहीं की जा सकी है; प्रस्थापित प्रतिकर की राशि की पर्याप्तता के बारे में विवाद है और इस प्रकार प्रस्थापित राशि को हितवद्ध व्यक्ति ने अधिप्राप्ति के साथ स्वीकार किया है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 24 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हितवद्ध व्यक्ति को संवेद्य प्रतिकर की राशि का अवधारण करने के प्रयोजन के लिये एक प्राधिकरण का गठन करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अमर जिला और सेवान न्यायाधीश, रांची होंगे।

[सं. 19(65)/77-सी.एस.]

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

New Delhi, the 24th August, 1978

S.O. 2701.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel, No. S.O. 252, dated the 15th January, 1958 made under section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 3310.30 bighas described in Schedule 'A' and the rights to mine, quarry, bore, dig and search for, win, work and carry away minerals in the lands measuring 1372.44 bighas described in Schedule 'B' appended to the said notification.

And whereas Shri Kamla Chand Upadhyaya, son of Shri Ram Nagina Upadhyaya, the person interested under section 13 of the said Act, preferred his claim to the competent authority for payment of compensation and in accordance with the authentication made by the State Government authorities, compensation for an area of 1.69 acres out of the said acquisition was assessed in his favour.

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement, there being a dispute as to the sufficiency of amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by the person interested under protest.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby constitutes a Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi, for the purpose of determining the amount of compensation payable to the person interested.

[No. 19(65)/77-CL]

गुडि-नर

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 1978

कां.प्रां. 2702.—भारत के राष्ट्रपति, भाग 2, खण्ड 3 उपखण्ड (ii) तारीख 12, मार्च 1977 के पृष्ठ 989-990 पर प्रकाशित भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं. कां.प्रां. 279, तारीख

21 फरवरी, 1977 के हिन्दी पाठ में, पृष्ठ 989 पर अनुसूची में, दहेगांव से संबंधित क्रम सं० 3 के सामने,—(1) स्तंभ 7 के नीचे की प्रविष्टियों में '272.938' के स्थान पर '277.938' पढ़ें ;

(2) स्तंभ 9 के नीचे की प्रविष्टियों में, '28.98' के स्थान पर '28.89' पढ़ें ।

[सं० 19 (67)/76-सी० एन०]

CORRIGENDUM

New Delhi, the 28th August, 1978

S.O. 2702.—In the English version of the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. S.O. 779, dated the 21st February, 1977, published at pages 990-991 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 12th March, 1977, in the Schedule :—

(i) at page 990,—

(a) For the word 'big' read 'dig';

(b) under the heading "Area in acres", for sub-heading "Govern land" read "Government land".

(ii) at page 991, under the heading 'Plot numbers to be acquired in village Pipla'—

(a) after the figure, brackets and letter 6(P), the figure, brackets and letter '8(P)' be added;

(b) for the figures, brackets, letter and word '13(P) to 17' read '13 to 17'

[No. 19(67)/76-CL]

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1978

क्र० प्रा० 2703.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है ।

प्रतः अब केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोयले का पूर्वोक्षण करने के अपने प्राथम्य की सूचना देती है ।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक का निरीक्षण मुख्य खनन इंजीनियर (निर्माण और विकास) पूर्वी कोल फील्ड्स लिमिटेड डाकघर दिशोरगढ़ जिला बर्दवान पं० बंगाल या कलकत्ता बर्दवान (पश्चिमी बंगाल) के कार्यालय या कोयला नियंत्रक का कार्यालय, 1-काउन्सिल हाऊस स्ट्रीट, कलकत्ता में किया जा सकता है ।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि में हितवद्ध व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट सभी नक्शे, चार्ट और अन्य दस्तावेजों इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 90 दिन के भीतर मुख्य खनन इंजीनियर (निर्माण और विकास) पूर्वी कोलफील्ड्स लिमिटेड, दिशोरगढ़ को भेजेगा ।

अनुसूची

सोनपुर ब्लॉक

रानीगंज कोयला क्षेत्र

क्रा.सं० 33/1883

तारीख : 15-2-1978

(पूर्वोक्षण के लिए अधिसूचित भूमि वर्णित करते हुए)

क्रम	मौजा	थाना सं०	पुलिम स्टेशन	जिला	एकड़ों में क्षेत्र	टिप्पणियां
सं० (ग्राम)			(थाना)			
1	2	3	4	5	6	7
1.	नवाग्राम	20	अखल	बर्दवान	850.90	भाग
2.	भासुका	21	-यथोक्त-	बर्दवान	219.17	सम्पूर्ण

581 GI/78--5

1	2	3	4	5	6	7
3.	सोनपुर	22	अखल	बर्दवान	1352.40	सम्पूर्ण
4.	हंसडिहा	27	-यथोक्त-	-यथोक्त-	409.91	सम्पूर्ण
कुल क्षेत्र				2832.38 एकड़	(लगभग)	
या				1146.22 हेक्टेयर	(लगभग)	

सीमा वर्णन :

क-ख रेखा, सोनपुर और बिलपहाड़ी मौजों के मध्य सामान्य सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "ख" पर जा मिलती है ।

ख-ग रेखा, सोनपुर और दालुरखन्ध मौजों के मध्य सामान्य सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "ग" पर जा मिलती है ।

ग-घ रेखा, सोनपुर और जोलभांगा मौजों के मध्य सामान्य सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "घ" पर जा मिलती है ।

घ-ङ रेखा, नवाग्राम और जोलभांगा मौजों के मध्य सामान्य सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "ङ" पर जा मिलती है ।

ङ-च रेखा, नवाग्राम और भटमुरा के मध्य सामान्य सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "च" पर जा मिलती है ।

च-छ रेखा, नवाग्राम और कोनारडिही मौजों के मध्य सामान्य सीमा के भाग के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "ग" पर जा मिलती है ।

छ-ज रेखा, वर्तमान बंकोल कोलियरी की खनन पट्टी सीमा के साथ-साथ नवाग्राम मौजों को पार कर के जाती है और मौजा नवाग्राम की पश्चिमी सीमा पर बिन्दु "ज" पर मिलती है ।

ज-झ रेखा, नवाग्राम और शंकरपुर मौजों के मध्य सामान्य सीमा के भाग के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "झ" पर मिलती है ।

झ-ञ रेखा, हंसडिहा और शंकरपुर के मध्य सामान्य सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "ञ" पर मिलती है ।

ञ-ट रेखा, हंसडिहा और बानबहल मौजों के मध्य सामान्य सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "ट" पर मिलती है ।

ट-ठ रेखा, सोनपुर और बानबहल मौजों के मध्य सामान्य सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "ठ" पर मिलती है ।

ठ-ड रेखा, सोनपुर और कुमार खाला मौजों के मध्य सामान्य सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "ड" पर मिलती है ।

ड-ड रेखा, सोनपुर और बजरी मौजों के मध्य सामान्य सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "ड" पर मिलती है ।

ड-क रेखा, सोनपुर और केन्द्र खेतद्वी मौजों के मध्य सामान्य सीमा के साथ-साथ जाती है और आरंभिक बिन्दु "क" पर जा मिलती है ।

[सं० 19(15)/78-सी० एन०]

एम० आर० ए० रिजवी, निदेशक

New Delhi, the 4th September, 1978

S. O. 2703.—Whereas it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the lands mentioned in the Schedule hereto annexed ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal therein.

The plan of the area covered by this notification may be inspected in the office of the Chief Mining Engineer (Construction and Development), Eastern Coalfields Limited, Post Office Dishergarh, District-Burdwan, West Bengal, or in the Office of the Collector, Burdwan (West Bengal) or in the Office of the Coal Controller, Council House Street, Calcutta.

Any person interested in the lands covered by this notification shall deliver all maps, charts and other documents referred to in sub-section (7) of Section 13 of the said Act to the Chief Mining Engineer (Construction and Development), Eastern Coalfields Limited, Dishergarh, within ninety days from the date of the publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE
SONPUR BLOCK
RANIGANJ COALFIELD

Drg. No. 33/1883

Dated : 15-2-1978

(Showing lands notified for pro-specting)

Sl. No.	Mouza (Village)	Thana Number	Police Stn. (Thana)	Distri-ct	Area in acres	Remarks
1.	Nabagram	20	Andal	Burdwan	850.90	Part
2.	Bhaluka	21	do	do	219.17	Full
3.	Sonpur	22	do	do	1352.40	do
4.	Hansdiha	27	do	do	409.91	do
Total Area—				2832.38 acres	(approximately)	
				or 1146.22 hectares	(approximately)	

BOUNDARY DESCRIPTION :

- A—B Line passes along the common boundary between Sonpur and Bilpahari mouzas and meets at point 'B'.
- B—C Line passes along the common boundary between Sonpur and Dalurband mouzas and meets at point 'C'.
- C—D Line passes along the common boundary between Sonpur and Joalbhanga mouzas and meets at point 'D'.
- D—E Line passes along the common boundary between Nabagram and Joalbhanga mouzas and meets at point 'E'.
- E—F Line passes along the common boundary between Nabagram and Bhatmura mouzas and meets at point 'F'.
- F—G Line passes along part common boundary between Nabagram and Konardihi mouzas and meets at point 'G'.
- G—H Line passes across Nabagram mouza, along mining lease boundary of existing Bankola Colliery and meets at point 'H' on the Western boundary of mouza Nabagram.

- H—I Line passes along part common boundary between Nabagram and Shankarpur mouzas and meet at point 'I'.
- I—J Line passes along the common boundary between Hansdiha and Shankarpur mouzas and meets at point 'J'.
- J—K Line passes along the common boundary between Hansdiha and Banbahal mouzas and meets at point 'K'.
- K—L Line passes along the common boundary between Sonpur and Banbahal mouzas and meets at point 'L'.
- L—M Line passes along the common boundary between Sonpur and Kumar Khala mouzas and meets at point 'M'.
- M—N Line passes along the common boundary between Sonpur & Bajari mouzas and meets at point 'N'.
- N—A Line passes along the common boundary between Sonpur and Kendra Hottadi mouzas and meets at the starting point 'A'.

[No. 19(15)/78-CL]

S. R. A. RIZVI, Director.

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1978

का० प्रा० 2704.—केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उस समय की अवधि को और आगे बढ़ाकर 30 सितम्बर, 1978 करती है जिस बीच भारत सरकार के पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अपनी अधिसूचना सं० ए०वी० 15013/1/78-ए० दिनांक 7 जनवरी, 1978 द्वारा नियुक्त किए गए जांच न्यायालय से आशा की जाती है कि वह उपर्युक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट मामलों पर अपनी जांच का कार्य समाप्त कर लेगा और उनकी रिपोर्टें केन्द्रीय सरकार को दे देगा।

[का० सं० ए० वी० 15013/1/78-ए०]

एस० ए० ए० ए०, उप सचिव

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

New Delhi, the 1st September, 1978

S.O. 2704.—The Central Government hereby further extends upto the 30th September, 1978, the period of time within which the Court of Inquiry appointed by the Government of India in the Ministry of Tourism and Civil Aviation vide Notification No. Av. 15013/1/78-A, dated 7th January, 1978, will be expected to complete its inquiry into the matters specified in the notification mentioned above, and report to the Central Government.

[F. No. Av. 15013/1/78-A]

S. EKAMBARAM, Dy. Secy.

निर्माण और आवास मंत्रालय

(सम्पदा निदेशालय)

नई दिल्ली, 24 जुलाई 1978

का० प्रा० 2705.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में सहायक संपदा प्रबंधक, गिमला और फरीदाबाद कार्यालयों को ऐसे कार्यालय होने के कारण जहाँ कर्मचारी युनू ने हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है।

[सं० 1/78 का० सं० ई०/12012 (7)/77-हिन्दी]

पी० एस० परवानी, अपर संपदा निदेशक

MINISTRY OF WORKS & HOUSING

(Directorate of Estates)

New Delhi, the 24th July, 1978

S.O. 2705.—In pursuance of sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for Official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the Offices of the Assistant Estate Manager, Simla and Faridabad as being offices where the Staff have acquired a working knowledge of Hindi.

[No. 1/78/F. No. E/12012/(7)/77-Hindi.]

P. S. PARWANI, Additional Director of Estates

(दिल्ली प्रभाग)

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 1978

क्र. 2706.—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 3 की उपधारा (3) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग के मुख्य इंजीनियर, श्री एल. एच. भाटिया को श्री आर. एस. गुप्ता के स्थान पर पर दिल्ली विकास प्राधिकरण के इंजीनियर सदस्य के पद पर उस तारीख से नियुक्त किया है जिस तारीख को वे इस पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे।

[संख्या के०-11011/27/78-यू० डी० आई० ए०]

हरी राम गोयल, अवर सचिव

(Delhi Division)

New Delhi, the 29th August, 1978

S.O. 2706.—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (3) of section 3 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) the Central Government appoints Sh. L. H. Bhatia, Chief Engineer, Public Works Department, Government of Madhya Pradesh, as Engineer Member of the Delhi Development Authority with effect from the date he assumes charge of the post, vice Shri R. S. Gupta.

[No. K-11011/27/78-UDIA]

H. R. GOEL, Under Secy.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1978

सार्वजनिक सूचना

क्र. आ 2707.—केन्द्रीय सरकार दिल्ली मुख्य योजना/क्षेत्रीय योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का विचार कर रही है, एतद् द्वारा जिसे सार्वजनिक सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है। इस संशोधन के सम्बन्ध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव देना हो तो वे अपने आपत्ति या सुझाव इस सूचना के 30 दिन के भीतर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 5वीं मंजिल, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली, के पास लिखित रूप में भेज दें। जो व्यक्ति अपनी आपत्ति या सुझाव दें, वे अपना नाम एवं पूरा पता लिखें।

संशोधन :

'जोन डी-17 (बस्ती निजामुद्दीन) में 581.85 व. मी. (695.6 व. गज) का क्षेत्र जो पूर्व तथा दक्षिण पूर्व में आवासीय भूमि (बस्ती निजामुद्दीन) दक्षिण एवं दक्षिण-पश्चिम में सार्वजनिक तथा अर्ध-सार्वजनिक उपयोग (धार्मिक तथा मद्रासा कश्पि-उल्लोम), उत्तर-पश्चिम में मनोरंजन उपयोग तथा उत्तर एवं उत्तर-पूर्व में सार्वजनिक तथा अर्ध-सार्वजनिक उपयोग (पुलिस-स्टेशन) द्वारा घिरा हुआ है, इसे अब 'मनोरंजन' (जिला उद्यान तथा खेल के मैदान) से 'सार्वजनिक तथा अर्ध-सार्वजनिक उपयोग' (धार्मिक) में परिवर्तित किने जाने का प्रस्ताव है'।

2 शनिवार को छाड़कर और सभी कार्यशील दिनों में चे. वि. प्रा. के कार्यालय, 10वीं मंजिल, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली में उक्त अधि के दौरेन प्रस्तावित संशोधन का मानवीय निरीक्षण हेतु उपलब्ध होगा।

[सं. एफ. 20(2)/78-एस. पी.]

कृष्ण प्रताप, सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 16th September, 1978

PUBLIC NOTICE

S.O. 2707.—The following modification which the Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi/Zonal Development Plan is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send his objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, 5th Floor, Vikas Minar, I.P. Estate, New Delhi, within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and full address.

MODIFICATION

The land use of an area measuring 581.85 sq. mts. (695.6 sq. yds.) in Zone D-17 (Basti Nizamuddin) surrounded by residential land use (Basti Nizamuddin) in the east and south-east, public & semi-public use (religious & Madrasa Kaship-ul-Ullom) in the south and south-west, recreational use in the north-west and public & semi public use (Police Station) in the north & north-east, is proposed to be changed from 'recreational (district parks & playgrounds)' to 'public & semi-public use (religious)'.

2. The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of the Authority, 10th Floor, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi, on all working days except Saturdays, within the period referred to above.

[No. F. 20(2)/78-MP]

KRISHNA PRATAP, Secy.

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 1978

का० प्रा० 2708.—सार्वजनिक परिसर (अधिकृत दखलकारों की बेवजली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित सारिणी के कालम (1) में उल्लिखित अधिकारियों को जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है तथा आगे यह निदेश करती है कि उपरोक्त अधिकारी उक्त सारिणी में कालम (2) के तदनुकूपी इन्दराज में विनिर्दिष्ट सार्वजनिक परिसरों के सम्बन्ध में अपने-अपने अधिकार-क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर उपरोक्त अधिनियम द्वारा या उसके अन्तर्गत सम्पदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे अथवा इन्हें दिये गये कर्तव्यों का पालन करेंगे।

सारिणी

अधिकारी का पदनाम	सार्वजनिक परिसरों की कोटियां तथा अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाएं
(1)	(2)
(1) वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर तथा मण्डल इंजीनियर, सिकन्दराबाद (ब० ला०), हैदराबाद (मी० ला०), विजयवाड़ा, हुबली तथा गुन्तकाल मण्डल, दक्षिण मध्य रेलवे	दक्षिण मध्य रेलवे के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत आने वाले परिसर जो उनके अपने अधिकार-क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित हों।
(2) क्षेत्र अधीक्षक, आगरा क्षेत्र, झांसी मण्डल, मध्य रेलवे	आगरा क्षेत्र के भीतर स्थित मध्य रेल के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत आने वाले परिसर
(3) मण्डल इंजीनियर, हावड़ा, आसनसोल, धनबाद, दानापुर तथा सियालबहादुर मण्डल, पूर्वी रेलवे	हावड़ा, आसनसोल, धनबाद, दानापुर तथा सियालबहादुर मण्डलों के अधिकार क्षेत्र के भीतर स्थित पूर्वी रेलवे के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत आने वाले परिसर।

[फाइल सं० 69/डब्ल्यू 2/एल ई/13]

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 11th August, 1978

S.O. 2708.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officers mentioned in column (1) of the Table below, being gazetted officers of Government, to be Estate Officers for the purposes of the said Act and further directs that the said officers shall exercise the powers conferred, and perform

the duties imposed, on the Estate Officers by or under the said Act, within the local limits of their respective jurisdiction in respect of the public premises specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table.

TABLE

Designation of the Officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction
1	2
(1) Senior Divisional Engineers and Divisional Engineers of Secunderabad (B.G.), Hyderabad (M.G.) Vijaywada, Hubli and Guntakal Divisions of South Central Railway.	Premises under the administrative control of the South Central Railway situated within the local limits of their respective jurisdiction.
(2) Area Superintendent, Agra area of Jhansi Division of Central Railway.	Premises under the administrative control of the Central Railway situated within Agra area.
(3) Divisional Engineers, Howrah, Asansol, Dhanbad, Danapur and Sealdah Divisions of Eastern Railway.	Premises under the administrative control of the Eastern Railway situated within the jurisdiction of Howrah, Asansol, Dhanbad, Danapur and Sealdah Divisions.

[File No. 69/W2/LE/13]

का० प्रा० 2709.—सार्वजनिक परिसर (अधिकृत दखलकारों की बेवजली) अधिनियम, (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार के पूर्ववर्ती निर्माण आवास तथा सप्लाय मंत्रालय की अधिसूचना सं० एस० प्रो० 1294 ता० 15-4-1967 तथा एस० प्रो० 2601 ता० 4-11-1961 और पूर्ववर्ती स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास एवं नगर विकास मंत्रालय (निर्माण आवास एवं नगर विकास विभाग) की अधिसूचना सं० एस० प्रो० 2344 ता० 11-7-1970 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

- (1) अधिसूचना एस० प्रो० 1294 ता० 15-4-1967 की सारिणी में कालम 1 में मौजूदा इन्दराज के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

“मण्डल अधीक्षक, द० म० रेलवे, सिकन्दराबाद (ब० ला०) हैदराबाद (मी० ला०), विजयवाड़ा, हुबली तथा गुन्तकाल।”

- (2) अधिसूचना एस० प्रो० 2601 ता० 4-11-1961 की सारिणी में कालम 1 में क्रम सं० 1 और 6 के सामने मौजूदा इन्दराज के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

“1. मण्डल अधीक्षक, मध्य रेलवे, भुसावल, बम्बई, झांसी, जबलपुर, नागपुर और शोलापुर।”

“6. मण्डल अधीक्षक, दक्षिण रेलवे, मद्रास, मैसूर, शोलावाकोट, मदुरै तथा तिरुचिरापल्ली।”

- (3) अधिसूचना एस० नो० 2344 ता० 11-7-1970 के साथ संलग्न सारिणी में कालम 1 और 2 में क्रम सं० 4 के सामने मौजूदा इन्वराज के स्थान पर निम्नलिखित को क्रमशः प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

अधिकारी का पदनाम	सार्वजनिक परिसरों तथा अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं की कोटियां
1	2
"4. वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर, मध्य रेलवे, भुसावल, बम्बई, जबलपुर, झांसी, नागपुर तथा शोलापुर मण्डलों के अधिकार क्षेत्र के भीतर स्थित मध्य रेलवे के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत आने वाले परिसर।"	

[काइल सं० 69/डब्ल्यू 2/एल ई/13]

पी० एन० मोहिले, सचिव

S.O. 2709.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby makes the following amendments to the notifications of the Government of India in the late Ministry of Works, Housing and Supply Nos. S.O.1294 dated 15th April, 1967 and S.O.2601, dated 4th November, 1961 and late Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Department of Works, Housing and Urban Development) No. S.O.2344 dated 11th July, 1970, namely:—

- (i) In the notification S.O.1294, dated 15th April, 1967, in the Table for the existing entry in Column 1, the following shall be substituted, namely:—

"Divisional Superintendents, South Central Railway, Secunderabad (B.G.), Hyderabad (M.G.), Vijayawada, Hubli and Guntakal."

- (ii) In the notification S.O. 2601, dated 4th November, 1961 in the Table for the existing entry in Column 1, against S.Nos. 1 and 6 the following respectively shall be substituted, namely:—

"1. Divisional Superintendents, Central Railway, Bhusawal, Bombay, Jhansi, Jabalpur, Nagpur and Sholapur."

"6. Divisional Superintendents, Southern Railway, Madras, Mysore, Olavakhot, Madurai and Tiruchchirappalli."

- (iii) In the Table appended to notification S.O. 2344, dated 11th July, 1970, for the existing entry in Column 1 and

2 against S.No. (4) the following shall respectively be substituted, namely:—

Designation of the Officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction
1	2
4. Senior Divisional Engineers, Central Railway, Bhusawal, Bombay, Jabalpur, Jhansi, Nagpur and Sholapur Divisions.	Premises under the administrative control of the Central Railway situated within the respective jurisdiction of Bhusawal, Bombay Jabalpur, Jhansi, Nagpur and Sholapur Divisions."

[File No. 69/W2/LE/13]

P.N. MOHILE, Secy.

संसार मंत्रालय

(डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1978

का० न्या० 2710.—मिर्जापुर टेलीफोन एक्सचेंज व्यवस्था के स्थानीय क्षेत्र में बदली किये जाने की बावत जिन लोगों पर इस परिवर्तन का प्रभाव पड़ने की संभावना है एक सर्वसाधारण सूचना उन सबकी (जानकारी के) लिए जैसा कि भारतीय तार नियमावली, 1951 के नियम 434 (iii) (बीबी) में प्रपेक्षित है मिर्जापुर में चालू समाचार पत्रों में निकाला गया था और उनसे कहा गया था कि इस बारे में यदि उन्हें कोई प्राप्ति हो या उनके कोई सुझाव हों तो वे इस सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर भेजने का कष्ट करें।

उक्त सूचना सर्वसाधारण की जानकारी के लिए दिनांक 16-4-1978 को अंग्रेजी दैनिक 'नार्थ इण्डिया पत्रिका' में प्रकाशित कराई गई थी।

उक्त सूचना के उत्तर में जनसाधारण से कोई प्राप्तियां और सुझाव प्राप्त नहीं हुए ;

इसलिए अब उक्त नियमावली के नियम 434 (iii) (बीबी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, डाकतार ने घोषित किया है कि तारीख 16-9-1978 से मिर्जापुर का स्थानीय संशोधित क्षेत्र इस प्रकार होगा :—

मिर्जापुर टेलीफोन एक्सचेंज व्यवस्था :

मिर्जापुर टेलीफोन एक्सचेंज योजना का स्थानीय क्षेत्र वही होगा जो कि मिर्जापुर नगरपालिका के अन्तर्गत पड़ता है,

किन्तु वे टेलीफोन प्रयोगकर्ता जो कि मिर्जापुर नगरपालिका की सीमा के बाहर स्थित हैं किन्तु जिन्हें मिर्जापुर टेलीफोन एक्सचेंज व्यवस्था से सेवा प्रदान होती है वे इस व्यवस्था के किसी भी एक्सचेंज से जब तक 5 किलोमीटर दूरी के भीतर स्थित रहेंगे और इस व्यवस्था से जुड़े रहेंगे तब तक स्थानीय शुल्क दर से अदायगी करेंगे।

टिप्पणी :—किन्तु यह सीमा उत्तर में गंगा नदी तक ही सीमित होगी।

[सं० 3-14/76-पी० एच० बी०]

एम० बी० राममूर्ति, निदेशक फोन (ई)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P. & T. Board)

New Delhi, the 7th September, 1978

S.O. 2710.—Whereas a public notice for revising the local area of Mirzapur Telephone Exchange System was published as required by rule 434 (III) (bb) of the Indian Telegraph Rules, 1951 in the Newspapers in circulation at Mirzapur, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of 30 days from the date of publication of the notice in the Newspapers;

And whereas the said notice was made available to the public on 16-4-1978 in the English Daily "Northern India Patrika";

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said notice ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by rule 434 (III) (bb) of the said Rules, the Director General Posts & Telegraphs hereby declares that with effect from 16-9-78 the revised local area of Mirzapur shall be as under;

Mirzapur Telephone Exchange System.

The local area of Mirzapur Exchange System shall cover an area falling under the jurisdiction of Mirzapur Municipality, provided further that the telephone subscribers who are located outside Mirzapur Municipal limit but who are served from Mirzapur Telephone System shall continue to pay local tariffs as long as they are located within 5 KMs. of any Exchange of this system and remain connected to it.

Note.—This limit shall however be restricted to river Ganges in the North.

[No. 3-14/76-PHB]

M. B. RAMAMURTHY, Director of Phones (E)

पूति और पुनर्वास मंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली, 21 अगस्त 1978

का०आ० 2711.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम 1954 (1954 का 44) की धारा 34 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार, पूति और पुनर्वास मंत्रालय (पुनर्वास विभाग) की अधिसूचना संख्या 1 (4) / विशेष सेल/ 77-एस० एस० 11 दिनांक 5 अप्रैल, 1977 का अधिग्रहण करते हुए, केन्द्रीय सरकार यह निवेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा -33 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोग की जाने

वाली शक्तियों का, उत्तर प्रदेश राज्य में गुआथजा पूल की सम्पत्तियों के संबंध में, उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त सचिव तथा न्यायिक विभाग में संयुक्त विधि परामर्शी द्वारा भी प्रयोग किया जाएगा।

[सं० 1 (4) / विशेष सेल/ 77-एस० एस०-II]

MINISTRY OF SUPPLY & REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 21st August, 1978

S.O. 2711.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 34 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954, (44 of 1954), and in supersession of Government of India, Ministry of Supply and Rehabilitation, Department of Rehabilitation Notification No. 1(4)/Spl. Cell/77-SS/II, dated the 15th April, 1977, the Central Government hereby directs that any powers exercisable by it under Section 33 of the said Act shall be exercisable also by the Joint Secretary and Joint Legal Remembrancer in the Judicial Department of the Government of Uttar Pradesh, in addition to his own duties, in respect of the lands and properties forming part of the Compensation Pool within the State of Uttar Pradesh.

[No. 1(4)/Spl. Cell/77-SS. II]

का० आ० 2712.—निष्क्रान्त हित (पृथक्करण) अधिनियम, 1951 (1951 का LXIV) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार पूति और पुनर्वास मंत्रालय, पुनर्वास विभाग की अधिसूचना संख्या 1(8) विशेष सेल 75 एस० एस० ii, दिनांक 23-6-76 का अधिग्रहण करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा दिल्ली प्रशासन के सचिव (विधि तथा न्यायिक) श्री शान नन्द जैन को तत्काल प्रभाव से संघ शासित क्षेत्र दिल्ली के लिए अपील अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या 1(8)/विशेष सेल/75-एस० एस०-II]

वीना माथ असीजा संयुक्त निदेशक,

S.O. 2712.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13 of the Evacuee Interest (Separation) Act, 1951 (LXIV of 1951), and in supersession of Government of India in the Ministry of Supply & Rehabilitation, Department of Rehabilitation's Notification No. 1(8)/Spl. Cell/75-SS/II, dated 23-6-1976, the Central Government hereby appoints Shri Gian Chand Jain, Secretary (Law and Judicial), Delhi Administration, Delhi as Appellate Officer for the Union Territory of Delhi with immediate effect.

[No. 1(8)/Spl. Cell/75-SS. II]

D. N. ASIJA, Jt. Director

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1978

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 1978

का० प्रा० 2713.—मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के खण्ड (घ) के अनुसरण में श्री एम० के० रामेश जैन, सचिव, मध्य प्रदेश सरकार, श्रम विभाग, भोपाल को कर्मचारी राज्य बीमा निगम में उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्दिष्ट किया है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के अनुसरण में, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० प्रा० 1517 तारीख 14 अप्रैल, 1976 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, "[राज्य सरकारों द्वारा धारा 4 के खण्ड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट]" शीर्षक के नीचे मद 17 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"श्री रामेश जैन, सचिव,
मध्य प्रदेश सरकार,
श्रम विभाग,
भोपाल।"

[संख्या यू०-16012/14/76-एच० आई०]

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 29th August, 1978

S.O. 2713.—Whereas the State Government of Madhya Pradesh has, in pursuance of clause (d) of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) nominated Shri Ramesh Jain, Secretary to the Government of Madhya Pradesh, Labour Department, Bhopal, to represent that State on the Employees' State Insurance Corporation, in place of Shri S. K. Bagchi ;

Now, therefore, in pursuance of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 1517, dated the 14th April, 1976, namely :—

In the said notification, under the heading "[Nominated by the State Governments under clause (d) of section 4]", for the entry against item 17, the following entry shall be substituted, namely:—

"Shri Ramesh Jain,
Secretary to the Government of Madhya Pradesh,
Labour Department, Bhopal."

[No. U-16012/14/76-HI]

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 1978

का० प्रा० 2714.—कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 16 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा औद्योगिक सहकारिता के रूप में संगठित सभी हाथ करघा कारखानों को एक वर्ग के रूप में उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से प्रथम जनवरी, 1975 से 31 अगस्त, 1978 तक जिसमें वे दिन भी सम्मिलित हैं, और आगे के लिए छूट देती है।

[नं० 35014/20/75-पी० एफ० II]

New Delhi, the 30th August, 1978

S.O. 2714.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 16 of Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby exempts all handloom factories organised as industrial co-operatives, as a class, from the operation of the said Act for a further period from the 1st January, 1975 upto and inclusive of the 31st August, 1978.

[No. S. 35014(20)/75-PF. II]

का० प्रा० 2715.—केन्द्रीय सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के खण्ड (ग) के अनुसरण में श्री जी० एस० निमि के स्थान पर श्री पी० एस० हुबीब मोहम्मद, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के अनुसरण में, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० प्रा० 1517 तारीख 14 अप्रैल, 1976 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, "[केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 4 के खण्ड (ग) के अधीन नामनिर्दिष्ट]" शीर्षक के नीचे मद 5 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात् :—

"श्री पी० एस० हुबीब मोहम्मद,
संयुक्त सचिव,
भारत सरकार,
श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली।"

[संख्या यू० 16012/14/78-एच० आई०]

New Delhi, the 31st August, 1978

S.O. 2715.—Whereas the Central Government has in pursuance of clause (c) of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), nominated Shri P. S. Habeeb Mohamed, Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, as a member of the Employees' State Insurance Corporation, in place of Shri D. S. Nim ;

Now, therefore, in pursuance of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 1517, dated the 14th April, 1976, namely:—

In the said notification, under the heading "[Nominated by the Central Government under clause (c) of section 4]" for the entry against item 5, the following entry shall be substituted, namely:—

"Shri P. S. Habeeb Mohamed,
Joint Secretary to the Government of India,
Ministry of Labour, New Delhi."

[No. U-16012/14/78-HI]

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 1978

का० प्रा० 2716.—केन्द्रीय सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 8 के खण्ड (ख) के अनुसरण में श्री जी० एस० निमि के स्थान पर श्री पी० एस० हुबीब मोहम्मद, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली को कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थायी समिति के सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किया है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 8 के अनुसरण में, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० प्रा० 477 (क) तारीख 16 जुलाई, 1976 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, "[केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 8 के खण्ड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट]" शीर्षक के नीचे मद 2 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात् :—

"श्री पी० एस० हुबीब मोहम्मद,
संयुक्त सचिव, भारत सरकार,
श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली।"

[संख्या यू० 16012/14/78-एच० आई०]

एच० एस० सहस्राचार्य, उप सचिव

New Delhi, the 2nd September, 1978

S.O. 2716.—Whereas the Central Government has, in pursuance of clause (b) of section 8 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), nominated Shri P. S. Habeeb Mohamed, Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, as a member of the Standing Committee of the Employees' State Insurance Corporation, in place of Shri D. S. Nim;

Now, therefore, in pursuance of section 8 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S. O. 477 (E), dated the 16th July, 1976 namely :—

In the said notification, under the heading "(Nominated by the Central Government under clause (b) of section 8)", for the entry against item 2, the following entry shall be substituted, namely :—

"Shri P. S. Habeeb Mohamed,
Joint Secretary to the Government of India,
Ministry of Labour, New Delhi."

[No. U-16012/14/78-HI]

S. S. SAHASRANAMAN, Dy. Secy.

New Delhi, the 28th August, 1978

S.O. 2717.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Bangalore in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Mysore Cements Limited and their workmen, which was received by the Central Government on the 19th August, 1978.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, BANGALORE

Bangalore, the 10th August, 1978

Reference No. 3 of 1978 (Central)

I Party Workmen of Mysore Cements Ltd., Ammasandra, Tumkur District,	—Vs.—	II Party The Management of Mysore Cements Ltd., Ammasandra, Tumkur District.
--	-------	--

APPEARANCES

For the I Party : Sri M. C. Narasimhan, Advocate,
Bangalore.

For the II Party : Sri R. Gururajan, Advocate Bangalore.

REFERENCE

(No. L-29011/11/77-I. II. B. dated 2/3rd May 1978)

AWARD

As per Government Order No. L-29011/11/77-D. III. B. dated 2/3rd May 1978, issued in exercise of its powers conferred by Section 7-A and Clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government has referred the following dispute for adjudication by this Tribunal :—

"Whether the demands of the Mysore Cements Employees' Association for (a) Refixation of the norms of workloads for breaking and loading of Limestone and (b) fixation of Minimum guaranteed wages, based on the norms of the work-load as per (a) above, in the quarries of Mysore Cements Ltd., are justified? If not, to what relief are the workmen entitled and from which date?"

2. On receipt of the Reference, notices were issued to the Parties for their appearance and filing of their statements on 26-7-1978. When the case was taken up on 2-8-1978, to which date it stood adjourned as per the request of the II Party, who entered appearance through Counsel and represented that the dispute has been settled, the I Party's General Secretary, Shivanna, and the II Party's Counsel were present. Sri M. C. Narasimhan also filed vakalat on behalf of the I Party and was present. The Parties filed a Compromise petition requesting to pass an Award in terms thereof.

3. I have perused the Memorandum of Settlement entered into between the Parties on 18-8-1977. The fixation of the Standard work-load at 4.5 tonnes is fair and reasonable, being based on the average performance during the preceding 6 months with a slight enhancement of 0.1 tonne which is within the workers' capacity to achieve. The dispute covered by (b) of the Schedule to the Reference also gets settled when the standard work-load under point (a) is fixed for the minimum guarantee wages is based thereon.

4. In the result, in accepting the Settlement, an Award in terms thereof is passed. The settlement shall be annexed to the Award.

(Dictated to the Stenographer, transcribed by him and corrected by me).

F. L. F. ALVARES, Presiding Officer

Annexure to Award in Ref No. 3 of 1978 (Central)

BEFORE THE HONOURABLE INDUSTRIAL

TRIBUNAL, BANGALORE

Reference No. 3 of 1978 (Central)

Workmen represented by
the General Secretary,
Mysore Cement Employees'
Association, Ammasandra,
(Tumkur District).

—Vs.—

The Management of
Mysore Cements Ltd.,

Ammasandra, Tumkur District

With reference to this Hon'ble Tribunal's Notice No. I. T. 286/78-79 dated July 11, 1978, the I Party and II Party beg to submit this Joint application :

1. That the dispute referred by the Central Government for adjudication by this Hon'ble Tribunal in the instant reference, viz.

"Whether the demands of the Mysore Cements Employees' Association for (a) re-fixation of the norms of work loads for breaking and loading of limestone and (b) fixation of minimum guaranteed wages, based on the norms of the work-load as per (a) above, in the quarries of Mysore Cements Ltd., are justified? If not, to what relief are the workmen entitled and from which date?"

has already been settled by mutual agreement entered into on August 18, 1977, a copy of which is enclosed as Annexure 'A' hereto.

2. Both parties pray that this Hon'ble Court may please to pass an Award in terms of the Agreement without costs.

Sd/- N. Shivanna

I Party

General Secretary

Advocate for I Party

Sd/- G. V. Rao

II Party,

Manager, Factory & Personnel

Advocate for II Party

ANNEXURE 'A'

MYSORE CEMENTS LIMITED

AMMASANDRA

August, 18, 1977

Notes of the Contact Meeting held on 16-8-1977

Representing	Representing
Management.	Mysore Cements Employees' Association.
Shri N. L. Hamirvasia	President.
Shri G. Jagdeesh,	Shri H. N. Narendra Prasad
Quarry Manager.	Vice President.
Shri G. V. Rao	Shri N. Shivanna
Personnel Officer.	General Secretary,
	Shri D. B. Bomme Gowda
	Asst. Secretary.
	Shri K. Thirumale Gowda,
	Treasurer.

Work-load in quarry:—The actual performance of stone-breakers and loaders for the last six months was reviewed. It came to an average of 4.4 tonnes per capital per shift in the period February to July 1977. As a gesture in the interests of settling this dispute and with due regard to all the factors, Management representatives stated that the standard work-load may be fixed at 4.5 tonnes.

Association representatives stated that the actual performance viz. 4.4 tonnes may be taken as the standard work load. Management representatives stated that on principles the actual performance cannot be regarded as the optimum and, in any case, in settling this dispute there should be some efforts on the part of workers to improve their productivity. The improvement suggested by the Management is only marginal i.e. 0.1 tonne which is within the capacity of the workers to achieve as shown by actual figures of performance. Association representatives stated that they are fully with the Management in improving productivity but the question was whether the workers would be able to reach and maintain that standard.

After detail discussion it was agreed by both sides that 4.5 tonnes would be taken as the standard workload. Employees' Association representatives requested that this be reviewed at the end of 3 months to see how much improvement over the past performance could be reached with reference to the revised work-load.

Transport contract.—Management representatives stated that this matter is under examination. They may be able to indicate their definite stand in the matter after two or three weeks.

Canteen.—This is a matter coming under the Mines Act and has been taken up by the inspection Authorities. Details of the proposal to take over the Management of the Canteen are being worked out and it hoped to settle this matter early.

In view of the above, Employees' Association representatives stated that they would withdraw the strike notice.

Sd/- N. Shivanna,
General Secretary.

Sd/- G. V. Rao, Personnel Officer
[No. L-29011/11/77-D-III.B.]

New Delhi, the 7th September, 1978

S.O. 2718.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bharat Aluminium Co. Ltd., Korba, and their workmen, which was received by the Central Government on the 23rd August, 1978.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-
CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

Case No. CGIT/LC (R) (32)/1978

PARTIES :

Employers in relation to the Management of Bharat Aluminium Co. Ltd., Korba and their workmen represented through Shri S. R. Sharma C/o N. R. Sharma, Retired Station Master, P. O. Pendra Road, District Bilaspur (M. P.)

APPEARANCES :

For Workmen Shri S.R. Sharma

For Management Shri P.S. Nair, Advocate,

DISTRICT: Bilaspur INDUSTRY: Aluminium

AWARD

Dated : August 19, 1978.

This is a reference made by the Government of India in the Ministry of Labour vide its Order No. L-43012/5/77-D. III B, dated 28th June, 1978, for the adjudication of the following dispute :

"Whether the action of the Resident Director, Bharat Aluminium Co. Ltd., Korba, in employing S/Shri B. S. Markam, S. R. Sharma, Deso Singh, Hoshiyar Singh, B. J. Ballantayan and Nathulal as Wagon Loading Supervisors of Chukki Pani Railway Siding, Pendra Road, Bilaspur (M.P.) and paying wages of a Clerk, giving breaks after 3 months, amounted to unfair labour practice. If so, to what relief the 6 workmen are entitled ?"

2. Parties have filed a compromise petition dated 29-7-1978, according to which the management has regularised the workmen concerned with effect from the dates given against their names and the rest of the claims have been withdrawn by the workers. The terms of compromise petition, which shall form part of this award, appears to be fair and reasonable and an award is given accordingly.

S. N. JOHRI, Presiding Officer.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LAB-
OUR COURT, JABALPUR CAMP : RAIPUR

Reference No. CGIT/LC(R)(32)/1978 dt. 1st July, 1978

Fixed for 29th July, 1978

PARTIES :

Bharat Aluminium Co. Ltd., Korba for Distt. Bilaspur (MP)

And their workmen represented through Shri S. R. Sharma & others

The parties have compromised their case on the following terms :

TERMS

The management has regularised the workmen in question with effect from the dates mentioned against their name.

1.	Shri S. R. Sharma	Yardman	26-12-77
2.	Shri B. S. Markam	do	24-12-77
3.	Shri Deo Singh	S.S.W.	21-1-78
4.	Shri Hoshier Singh	S.S.W.	21-1-78
5.	Shri B. J. Ballantyne,	Mazdoor	21-1-78
6.	Shri Nathulal	Mazdoor	21-1-78

The workmen give up their claim for any other benefit for the prior periods of regularisation as mentioned above.

The above terms are fair and reasonable and in the interest of industrial peace.

PRAYER

It is therefore, prayed that an award may kindly be given in the terms of above settlement.

(Sd.) Illegible,
Counsel for Management,
S. R. Sharma, for Workmen.

[No. L-43012/5/77-D.III.B]

S. N. JOHRI, Presiding Officer.

New Delhi, the 7th September, 1978

S.O. 2719.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Madras in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Krishna Mines, Tirunelveli and their workmen, which was received by the Central Government on 26th August, 1978.

BEFORE THIRU K. SELVARATNAM, B. A., B. L.,

INDUSTRIAL TRIBUNAL, MADRAS

(Constituted by the Central Government)

Monday, the 14th day of August, 1978

Industrial Dispute No. 35 of 1977

(In the matter of the dispute for adjudication under Section 10 (1) (d) of the Industrial Dispute Act, 1947 between the Workmen and the Management of M/s. Krishna Mines, Tirunelveli).

BETWEEN

The workmen represented by

1. The President, Nellai Suranga Thozhilalar Sangam, 18E, Parasakthi Buildings, Tirunelveli-627801.
2. The Secretary, Thirunelveli Taluk National General Workers Union, Madurai Road, Thalaihuthu, Shankarnagar Post, Tirunelveli District.
3. The Secretary, Nellai Mavatta General Workers Union, Main Road, Thalaihuthu, Shankarnagar Post, Tirunelveli District.

AND

The Manager

Krishna Mines, Post Box No. 8,
5, Kailasapuram North Street,
Tirunelveli Jn., Tirunelveli (Tamil Nadu).

REFERENCE:

Order No. L-29011/9/77-D. III. B, dated 22nd June, 1977 of the Ministry of Labour, Government of India

This dispute coming on for final hearing on Saturday the 22nd day of July, 1978 upon perusing the reference, claim and counter statements and all other material papers on record and upon hearing the arguments of Thiru R. Raj. President

of Union No. 1 and of Thiruvallargal M. R. Narayanaswami and S. Jayaraman, Advocates for the management and Union Nos. 2 and 3 being absent and this dispute having stood over till this day for consideration, this Tribunal made the following.

AWARD [On Issue No 1(a)]

This is an Industrial Dispute referred to this Tribunal by the Government of India for adjudication under section 10 (1) (d) of the Industrial Dispute Act, 1947 between the Management of M/s. Krishna Mines, Tirunelveli and their workmen.

(2) The reference is as follows :

1. Whether the management of Messrs Krishna Mines, Post Box No. 8, No. 5, Kailasapuram North Street, Tirunelveli are justified :—

(a) In dismissing Shri S. Subramaniam, Mazdoor, from service with effect from 26th November, 1976 ;

(b) in deducting wages from their mine workers for short load with effect from November, 1976 in terms of the settlement dated 25-1-76. If not, to what relief are the affected workers entitled.

(3) The issue referred to consists of two parts. one is in the matter of dismissal of Thiru S. Subramaniam, Mazdoor from service and another is deduction of wages from mine workers for short load. The first part of the issue was taken up for enquiry at the request of the parties in the first instance. As this issue was not connected with the other issue, namely the Second issue entails much oral and documentary evidence, and the parties are not ready for the Second issue. The first issue was taken up for consideration.

(4) Union No. 1 filed a claim statement, wherein it is stated as follows : The worker Thiru S. Subramaniam was an active trade Unionist and also executive committee member of the Sangam. The Management did not relish his activities. Hence he was dismissed from service in the month of November, 1976 after only a farce of enquiry. The principles of natural justice was not followed during the enquiry. The enquiry was conducted by the Officer Manager and he is not an independent officer. The enquiry officer is biased against the workman and no opportunity was given to him to cross-examine the witnesses. The dismissal is only an act of victimisation. The worker had simply requested the Quarry Manager to supply good shoes to the workmen. He exhibited the shoes in worn out condition to the Quarry Manager and the Quarry Manager took this as an affront to him. In these circumstances, even assuming that he was guilty of misconduct that the punishment was quite disproportionate and the matter may be viewed leniently by this Tribunal.

(5) Union No. 2 filed a claim statement on similar lines of the 1st Union.

(6) Union No. 3 has not filed any claim statement.

(7) The Management filed a counter, wherein they contend as follows : As per the provisions of the Statute, all the workmen are to be provided with two pairs of shoes per year, one pair in the month of June and another pair in the month of December. In the year 1976, all the eligible workmen were provided with one pair of shoes in May, 1976. The workmen Thiru S. Subramaniam approached the Mines Manager on 8-9-1976 that he should be provided with one pair of shoes on the ground that the one that was supplied to him has become worn out. The Mines Manager said that he was unable to supply another shoe as he had already been supplied with one. Immediately he threw the shoes in front of the Manager and also told him that he may take the shoes and credit it in the accounts. By his behaviour he had shown disrespect to the Mines Manager which is a misconduct under Clause 17 (k) of the Standing Orders. Hence a charge-memo was issued to him on 13-9-1976. He denied the incident. Hence an enquiry was held. The Management allowed him to take the assistance of the co-employee who happened to be the Vice President of the Union. The enquiry was held in the presence of the employee and the Vice President of the Union and both of them participated in the proceedings and

cross-examined the witnesses who spoke in support of the charge. The workman simply denied the charges. After due enquiry the enquiry officer came to a finding that the charges were proved. Hence the findings of the Enquiry Officer were accepted by the Management and dismissed him from service with effect from 26-11-1976. Hence the allegation that the enquiry officer was biased against the workman is baseless. Having regard to the serious misconduct the Management has rightly dismissed him from service and his plea that punishment is excessive is not correct.

(8) On the side of the Management Exs. M-1 to M-18 were marked. Among the documents filed, Ex. M-2 is the report of Thiru Subbiah against the worker Subramanian. Ex. M-3 is the charge sheet. The charge was that he threw the shoes in front of the Mines Manager and he asked him to keep the shoes with him and also expressed derogatory words. Ex. M-4 is the explanation of the delinquent, wherein it is stated that he asked the Mines Manager another shoe in the place of worn out shoe and he did not behave improperly by throwing the shoe towards the Mines Manager. Therefore the only question to be considered is whether he threw the shoe in front of the Manager or simply showed the work out condition of the shoe towards the Manager and asked for replacement. Ex. M-11 is the Enquiry Proceedings. It will show that Thiru Narayanan, Mines Manager (the complainant) has deposed as M. W. 1. He has stated that the delinquent workman threw the shoe which fell in front of his feet and he could not wear it and he should be given another shoe. He asked him to speak to him in polite way and asked him to take back the shoe. The workman abandoned the shoe there and went away. On the side of the Management his evidence has been corroborated by Thiru Subbiah who was witnessing the occurrence and both were cross-examined by the delinquent workman. Ex. M-12 is the findings of the Enquiry Officer who has given a cogent reasons and came to a conclusion that the charge was proved. I find nothing perverse in his findings. The allegation against him is that the Enquiry Officer was employed by the Management and as such he was biased towards the Management. There is no bar in law for the industrial concern to appoint his own employee as an Enquiry Officer. Further he has been also given assistance by his co-employee to defend himself. Therefore there is no basis for the allegation that the Enquiry Officer was biased and the enquiry proceedings did not conform to the principles of natural justice. I find the Enquiry Officer has come to a proper conclusion that the charge had been proved. Therefore his finding has been accepted. The Management accepted his finding acted on it and they found the act of the worker was serious and dismissed him from service.

(9) As regards the quantum of punishment, I have to consider whether the facts of the case warrant the infliction of the punishment of dismissal. From the evidence it is seen that he approached the Manager with a view to replace the shoe. When he was told that it cannot be done, the worker got provoked and acted on the spur of the moment. In these circumstances it cannot be said that it was a calculated pre-planned misconduct. Therefore this case reserves sympathetic consideration. I feel that the punishment of dismissal is too severe and he could be given a chance to reform himself and behave properly towards the superior officers in future. Therefore the order of dismissal has been set aside; instead he is directed to tender apology in person before the Enquiry Officer for his misconduct by filing an undertaking that he will not behave in indecent manner in future and in case he behaves badly he could be removed from service.

(10) In the result, my finding on the issue is that he was guilty of misconduct and the punishment of dismissal is set aside. He is directed to apologise before the Mines Manager and file an undertaking in the above terms. He will be reinstated without back wages within one month from the date of publication of the Award in the Official Gazette. An Award is passed accordingly on issue No. 1 (a).

Dated, this 14th day of August, 1978.

K. SELVARATNAM, Presiding Officer.

WITNESSES EXAMINED

For workmen and Management : Nil.

DOCUMENTS MARKED

For workmen : Nil.

For Management :

- Ex. M-1/8-9-76—Report of the Quarry Manager against Thiru Subramanian.
- Ex. M-2—Report of Thiru Subbiah against Thiru Subramanian.
- Ex. M-3/13-9-76—Charge sheet issued to Thiru Subramanian.
- Ex. M-4/14-9-76—Explanation of Thiru Subramanian.
- Ex. M-5/26-9-76—Letter from the Management to Thiru Subramanian calling for explanation.
- Ex. M-6/27-9-76—Reply by Thiru Subramanian to Ex. M-5.
- Ex. M-7/11-11-76—Letter authorizing Thiru S. Bajarman to conduct enquiry into the charges against Thiru S. Subramanian.
- Ex. M-8/12-11-76—Enquiry notice issued to Thiru S. Subramanian.
- Ex. M-9/15-11-76—Letter from Thiru S. Subramanian requesting to permit the President of the Union as observer in the enquiry.
- Ex. M-10/15-11-76—Reply letter from the Enquiry Officer to Ex. M-9.
- Ex. M-11/16-11-76—Enquiry proceedings.
- Ex. M-12—Findings of the Enquiry Officer.
- Ex. M-13/25-11-76—Dismissal order issued to Thiru S. Subramanian.
- Ex. M-14/25-1-76—Memorandum of Settlement u/s. 12(3) of the I.D. Act, 1947 between parties.
- Ex. M-15/25-12-75—Charge sheet issued to Thiru Subramanian for short load.
- Ex. M-16/16-1-76—Dismissal order issued to Thiru Subramanian on a prior charge.
- Ex. M-17—Apology letter given by Thiru Subramanian.
- Ex. M-18—Standing Orders of the Company.

K. SELVARATNAM, Presiding Officer

[No. L-29011/9/77-D. III. B]

NOTE:—Parties are directed to take return of their document/s within six months from the date of the Award.

S.O. 2720.—In pursuance of section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Parshva Properties Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on the 26th August, 1978.

AWARD

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1 AT DHANBAD

In the matter of a reference under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

Reference No. 11 of 1977

PARTIES :

Employers in relation to Parshva Properties Limited
AND
Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Employers.—Shri D. Mukherjee, Advocate.
For the Workmen.—Shri B. Lall, Advocate.

STATE : Bihar INDUSTRY : Lime Stone Quarry.

Dhanbad, the 11th August, 1978

AWARD

This is a reference made by the Government of India in the Ministry of Labour vide its Order No. L-29011/39/76-D. III(B), dated the 28th February, 1977, for adjudication of the following industrial dispute :

"Whether the action of the management of Messrs Parashva Properties Limited, P. O. Pararia (Dist. Roh-tas) in terminating the service of Shri Jagdish Singh, Mate of Upper Murli Lime Stone Quarry w.e.f. 3-6-1976 is justified? If not, to what relief the workman is entitled?"

2. The parties have filed a settlement. The settlement appears to be reasonable and terms of which are verified. The award is given in terms of settlement which shall form part of the award.

S. N. JOHRI, Presiding Officer

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT.
INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

Reference No. 11 of 1977

Employers in relation to Parashva Properties Ltd.

AND

Their Workmen, Sri Jagdish Singh.

That without prejudice to the respective contentions contained in their Written Statements, the Parties have settled their dispute on the following terms :—

1. That Sri Jagdish Singh will be re-instated in service as a Mate.

2. That the period from the date of the termination of service of Sri Jagdish Singh, namely, with effect from 3-6-76 till he joins his duties will be treated as if he is on leave without pay for the purpose of continuity of service only.

3. That Sri Jagdish Singh will have no other claim against the Management on any other account, whatsoever.

4. That the above terms finally settles the present dispute between the parties.

It is, therefore, humbly prayed that the above terms may kindly be accepted and an Award passed in terms thereof.

For Workman—Jagdish Singh.

For Employers—Adishwar Prasad, Commercial Manager.

[No. L. 29011/39/76-D. III. B.]

S. N. JOHRI, Presiding Officer

New Delhi, the 8th September, 1978

S.O. 2721.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Bhubaneswar in the industrial dispute between the employers in relation to M/s. Modern Construction Concern Contractor s under the M/s. Orissa Mineral Development Company and their workmen, which was received by the Central Government on the 24th August, 1978.

INDUSTRIAL TRIBUNAL, BHUBANESWAR

Industrial Dispute Case No. 4 (Central) of 1975

Bhubaneswar, the 19th August, 1978

BETWEEN

The employers in relation to Messrs. Modern Construction Concern, Contractors under the Messrs. Orissa Mineral Development Company, Post Office Barbil, District Keonjhar.

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the employers.—Shri M. R. Ganguli, Managing Partner, Shri R. K. Nair, Administrative and Personnel Manager.

For the workmen.—Shri D. C. Mohanty, President, Keonjhar Mines and Forest Workers' Union, Barbil.

AWARD

In exercise of the powers conferred by Section 7-A and clause (d) of Sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Government of India in the Ministry of Labour have referred the following disputes to this Tribunal for adjudication in their Order No. L-26012/8/75-DIV(B) dated 13-8-1975 :

"Whether the following actions of Messrs Modern Construction Concern, contractors under Messrs Orissa Mineral Development Company, Post Office Barbil, District Keonjhar were justified :

(1) Dismissal of Shri Atmaram Gond, Miner with effect from 19th February, 1975.

(2) Transfer of Sarvashri Ramesh Munda, Lakhan Gope, and Mathura Das, Miners with effect from 26th February, 1975 from their establishment at Thakurani Mines to their establishment at Bolani Iron Ore Mines of Messrs Bolani Ores Limited and subsequent termination of their services with effect from 12th March, 1975.

If not, to what relief are the workmen entitled."

2. Both the sides submitted a Memorandum of Settlement duly signed on behalf of the employers and the workmen and both the sides have submitted that an Award may be passed in terms of the settlement. The parties have admitted the terms of the settlement and have submitted that a settlement has voluntarily been arrived at in the interests of industrial peace.

3. I accept the settlement between the parties and pass the Award in terms of the settlement in respect of the disputes referred to. The Memorandum of Settlement shall form part of the Award.

M. V. GANGARAJU, Presiding Officer

Dated : 19-8-1978.

FORM H

(See Rule 58)

Form of memorandum of settlement.

NAME OF THE PARTIES :

Representing the Employer.—Sri M. R. Ganguli.

Representing

Modern Construction Concern, Thakurani, Keonjhar.

Representing the workmen—Shri D. C. Mohanty, President; Shri D. Satapathy, Vice-President; Shri D. Ray, General Secretary.

Konjhar Mines & Forest Workers' Union, Barbil.

Short Recital of the case

The management of Modern Construction Concern, Thakurani Contractor of M/s. O.M.D. Co. Ltd., Barbil, transferred Sarvasree Ramesh Munda, Laxman Gope and Mathura Das, Miners to Bolani and subsequently terminated their services. Sri Atmaram Gond Miner was dismissed from service on charges of misbehaviour to the superior authority. The cases were taken up in conciliation and subsequently referred by the Govt. of India to Presiding Officer, Industrial Tribunal (Central), Bhubaneswar vide Govt. Order No. F. No. 1-260/2-8-1975 for adjudication and has been recorded as I/D case No. 4 of 1975 (Central).

The parties to the disputes had mutual discussions out of court had come to the following terms of settlement out of their free volition.

Terms of Settlement

1. It is agreed between the parties that Shri Atmaram Gond, Miner, shall be reinstated in his service in Thakurani Mines of the management with continuity of service and all other consequent benefits.

2. It is agreed that Shri Ramesh Munda, Miner shall be reinstated in his service in Thakurani Mines of the management with full back wages. He shall be paid the full average pay paid to him during the last three months of his service i.e. between 24-11-1974 to 24-2-1975 from 24-2-1975 till the date of his joining work on 20-9-1977.

He shall be paid all the dues and benefits paid to a permanent workmen of the Company.

3. It is agreed that Shri Laxman Gope and Shri Mathura Das, Miners, shall be reinstated in their work in the Thakurani Mines of the management with continuity of service. They shall not be paid wages for the period from 26-2-1975 till the 31st January, 1977. Thereafter till the date of their joining they shall be paid a lump sum of Rs. 400.00 each which settles the claims for the wages in full for the period.

4. It is agreed that the aforesaid settlement covers the terms of reference to the Tribunal and shall be considered full, final and fair settlement of items 1 & 2 of the above reference.

The parties shall jointly present the settlement before the Industrial Tribunal and shall request the Tribunal to pass an award in terms of this settlement in respect of item Nos. 1 & 2 of the aforesaid reference in Case No. 4 of 1975 (Central).

SIGNATURE OF THE PARTIES

Representing the Management:

Shri M. R. Ganguli, Representative, Modern Construction Concern.

Representing the workmen:

1. D. C. Mohanty, President.
2. D. Satapathy, Vice-President
3. D. Ray, General Secretary.
Konjhar Mines & Forest Workers' Union, Barbil.

Copy to:—

The Assistant Labour Commissioner (Central) Rourkela.

The Chief Labour Commissioner, Govt. of India, New Delhi.

The Additional Secretary, Labour & Employment, Govt. of India, New Delhi.

M. V. GANGARAJU, Presiding Officer
[No. L-26012/8/75-D. IV B]

R. KUNJITHAPADAM, Under Secy.

New Delhi, the 2nd September, 1978

S.O. 2722.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Newton Chickli Colliery of Western Coalfields Limited and their workmen which was received by the Central Government on the 30th August, 1978.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL— CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M. P.)

Case No. CGIT/LC(R)(18) of 1978

PARTIES:

Employers in relation to the Management of Newton Chickli Colliery of Western Coalfields Limited, Pench Area Newton Group, Post Office, Parasia District Chhindwara and their workman through the President Bhartiya Koyla Khadan Mazdoor Sangh, P. O. Chandametia, Distt. Chhindwara (M. P.).

APPEARANCES:

For Management.—Shri P. S. Nair, Advocate.

For Workman.—Shri S. S. Sakarwar.

INDUSTRY : Western Coalfields DISTRICT : Chhindwara (M.P.)

Dated August 24, 1978

AWARD

This is a reference made by the Government of India in the Ministry of Labour vide its order No. L-22013(1)/77-D-IV(A), dated 4th April, 1978, for the adjudication of the following industrial dispute :

"Whether the action of the management of Newton Chickli Colliery, Newton Group, Western Coal Fields Ltd., Pench Area in dismissing Shri Sheikh Iklaam, Ex-timber mistry from service with effect from 16th February, 1975, is justified ? If not to what relief is the concerned workman entitled ?"

It is not disputed that Sheikh Iklaam was ordered to take Friday as rest day while he was insistent that he will avail Sunday as rest day. It was in this context that he was served with a charge-sheet signed by Shri S. L. Sachdev, manager on 3-1-75 (Friday) that he had forced his entry into the mine that day and was suspended with effect from 4-1-75. Two days later another charge-sheet signed by the Production Superintendent, dated 6-1-75 was served upon him with the allegation that on 4-1-75 at about 8.30 a.m. while Shri S. L. Sachdev, manager was going on duty towards the siding from his bungalow on foot, Sheikh Iklaam assaulted him with a lathi causing injuries on his hands, legs and arms in an attempt to cause injuries on the head. He was further charged of using filthy and threatening language as under :—

"SALE MADARCHOD CHARGE SHEET DEGA, SUSPEND KAREGA, ABHI TUMKO JAAN SE KHATAM KAR DETA HOON".

The acts were alleged to be amounting to misconduct under clauses 17(1)(e), (g) and (r) of the Standing Orders applicable to Newton Chickli Colliery. Said provisions of standing orders the abstracts of which were quoted in the charge-sheet may be reproduced as follows :

"17(1) The following shall denote misconduct :

- (e) Drunkenness, fighting or riotous, disorderly or indecent behaviour, while on duty at the place of work;

(g) Habitual indiscipline;

(r) Threatening, abusing or assaulting any superior or co-worker."

Sheikh Iklaam denied the charge on 8-1-75. Shri N. V. Pavgi, Senior Personal Officer conducted the domestic enquiry in which the delinquent was represented by his co-worker Shri Bhanu Pratap. The Enquiry Officer found him guilty of the misconducts only under clauses 17(1)(c) and (r) and exonerated him of the misconduct under clause 17(1)(g). The findings were accepted by the Production Superintendent (punishing authority) who dismissed him on 16-2-75. Appeal to Sub area Manager was rejected.

Simultaneously for the same incident the police prosecuted Sheikh Iklaam for offences u/s. 294, 506 and 323 but Shri L. N. Mishra, learned magistrate, Amarwada acquitted him in the case 868, of 1977. The Judgement of acquittal was pronounced more than 2 years after his dismissal on 30-4-77.

Union's case is that Sheikh Iklaam was the Vice-President of Koyla Khadan Mazdoor Sangh. The management's action was only an act of victimisation through got up story of assaults etc. It acted mechanically in appointing Shri Pavgi as Enquiry Officer.

Later on further pleas were raised by way of amendment of the written statement. Accordingly it was ultimately alleged that the enquiry was vitiated because :

- (i) Second notice to show cause against proposed punishment was not given ;
- (ii) Personal hearing was not granted by the punishing authority ;
- (iii) The judgement of the criminal court vitiated the findings of enquiry officer ;
- (iv) The findings were perverse; and
- (v) It was a case of victimisation for union activities.

Management denied these allegations. However, learned counsel for the union conceded that proper opportunity to defend was given by the enquiry officer and therefore there was no need to reopen the enquiry or give any opportunity to the parties to prove their case before this Tribunal. Neither side wanted to produce any evidence after admission of the enquiry papers. Hence the case was taken up for final arguments.

The plea of mechanical appointment of the Enquiry Officer is meaningless and has not been pressed before me.

Clause 17 (iv) of the standing orders does not say that an opportunity to show cause against the quantum of punishment, should be provided to the delinquent hence not granting such an opportunity is neither violative of any rule nor of any principle of natural justice.

So far as the plea of denial of the opportunity of personal hearing is concerned no such right is envisaged under the standing orders nor any such right is considered to be a requirement of natural justice and it's denial is not fatal. In the present case there is no evidence that any such prayer was even made before the punishing authority.

The report of the Enquiry Officer is a well reasoned report. He has not relied on any material which is not on record. Marshalling of the evidence is proper. Evidence of both sides has been considered and cogent reasons for acceptance of one and rejection of the other have been given. Learned Counsel for the union has not been able to show as to how the report is perverse.

It is true that subsequently the delinquent was acquitted by the Criminal Court. He was prosecuted for the same incident and the same witnesses, as were examined before the domestic enquiry, were examined before the Criminal Court, which disbelieved them giving benefit of doubt to the

accused delinquent. Firstly according to the principle No. (3) summed up in Delhi Cloth and General Mills Co. Vs. Luddh Budh Singh 1972 (9) SCLJ 229 (251) if the domestic enquiry was properly and validly held, 'the question of considering the evidence adduced before it (before the Tribunal) on merits, no longer survives'. In the present case validity and propriety of the enquiry has not been challenged and the above findings confirm that it was valid and proper. In view of this no evidence produced before this Tribunal i.e. the Certified Copy of the judgement of Criminal Court can at all be considered.

Secondly the Criminal Court has not spelled out the alleged discrepancies and has not reasoned out the weight which was given to them. Mere writing that there are discrepancies hence the evidence cannot be relied upon is not a convincing argument. As against that the report of the enquiry officer is quite a well reasoned out report. The Criminal Court failed to consider that it was undisputed that the accused and the victim of assault had met at the alleged place and time. It has not said as to how discrepancies in the evidence against the co-accused could weaken the strength of the testimony of those witnesses against this delinquent accused. It is not discussed as to why offence u/ss. 294 and 506 were not made out.

Thirdly in the Criminal Court prosecution is bound to prove the guilt beyond shadow of doubt but that very high standard of assessment of evidence is not applicable to domestic enquiries. Hence even if the Criminal Court acquits a delinquent giving him benefit of doubt that will not vitiate the report and finding of the Enquiry Officer.

Lastly the order of dismissal in the present case was not based on any judgement of the Criminal Court. It was based on the independent finding of the Enquiry Officer. In such a case the ultimate result cannot be nullified or otherwise adversely affected by some subsequent verdict of the Criminal Court and that too when it is based on the application of the principle of benefit of doubt. Thus I am of the view that the verdict of the Criminal Court is of no consequence.

Nothing has been said about quantum of punishment and it is obvious that assault on the manager needs no soft considerations. The punishment thus does not call for re-consideration.

Before I close, I will like to say that the question of victimisation due to union activity, has no legs to stand when the misconduct is proved by cogent evidence. In such a case motives become irrelevant. No office bearer of a union can with impunity indulge in unlawful acts grossly subversive of discipline.

It is therefore held that dismissed was the justified punishment. The award is given accordingly.

S. N. JOHRI, Presiding Officer

24-8-78

[F. No. L-22013(1)/77-D. IV(A)]

New Delhi, the 8th September, 1978

S.O. 2723.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Bangalore in the industrial dispute between the employers in relation to the management of New Mangalore Port, Panambur P.O. (Via) Mangalore and their workmen which was received by the Central Government on the 5th September, 1978.

**BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL IN
KARNATAKA, BANGALORE**

Reference No. 1 of 1977 (Central)

I PARTY:

The workmen of New Mangalore Port, Panambur,
P.O. via Mangalore.

II PARTY:

The Chief Engineer & Administrator, New Mangalore
Port, Panambur P.O. (via) Mangalore.

APPEARANCES:

For the I Party.—Shri P. M. N. Murthy, President, New
Mangalore Port and Dock Workers' Union.

For the II Party.—J.F.B. Frank, Government Pleader
and Shri Sequeria, Advocate, Mangalore.

Order of Reference

(Order No. L-45012(2)/77-D.IV(A) dated 4-5-1977 of the
Government of India, Ministry of Labour).

AWARD

As per Government Order No. L-45012(2)/77-D.IV(A)
dated 4-5-1977, issued in exercise of its powers conferred
by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of Section
10 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Govern-
ment has referred the following dispute for adjudica-
tion to this Tribunal:—

"Whether the action of the management of New
Mangalore Port in allowing Shri V. S. Lasrado,
Driver, to draw less pay than Shri K. Narayana,
Driver, his junior, for the period from 31st May
to 17th December, every year since 31-5-1973 is
justified? If not, to what relief is Shri V. S.
Lasrado entitled?"

2. In the II Party's statement which was filed in the first
instance on 30-7-1977, it is stated that V. S. Lasrado was
appointed as a Driver on 17-12-1966 on the pay scale of
Rs. 110-3-131-EB-4-155. The Central Civil Services (Revised
Pay) Rules came into force from 1-1-1973 and as from the
date, revised scales of pay, viz., Rs. 260-6-326-EB-8-350,
was implemented for the category of drivers. Immediately
prior to the implementation of the Central Services (Revised
Pay) Rules the pay of Lasrado on the old scale was Rs. 128.
On revision, his pay was fixed on the stage of Rs. 284.
His increments fell due on 18th December each year and
he has accordingly drawn his increments. K. Narayana was
also appointed as driver in the same pay scale but with
effect from 31-5-1967. His pay immediately before the
revised pay scales came into force was Rs. 125 and on
revision, his pay was fixed on the next stage at Rs. 284.
His increments fell due on 2nd June of each year and he
has drawn his increments. The II Party further averred
that there are separate and distinct recruitment rules for the
work charged category of lorry drivers (lorry and bus) and
category of jeep drivers. Separate seniority lists for the two
categories were also finalised after necessary circulation.
As the two categories are separate and distinct, protection
given under the Revised Pay Rules for stepping up the pay
of a Senior to the same stage as that of his junior, who is
drawing a higher pay, will not apply. Therefore, the drawal
of pay of Lasrado is correct.

3. In the I party's statement filed subsequently on
18-8-1977, it is contended that K. Narayana is junior to
Lasrado and that, though the revised scales of pay were

implemented as on 1-1-1973 fixing the pay of both of them
at Rs. 284, K. Narayana has been given his next increment
on 31-5-1973 whereas Lasrado has been given his increment
on 18-12-1973. An anomaly has arisen on account of not
giving effect to Rule 8 of the Revised Pay Rules. It is not
true that the Recruitment Rules of Lorry Drivers are separate
and distinct from Jeep drivers. They are recruited as drivers
and are enjoined to work on any vehicle assigned to them.
The same system continues even today. It is not true that
a seniority list was prepared. If some list is there with
the management, it is not prepared by the Management after
giving necessary opportunity to make representations on the
part of the effected workmen against such lists. At any rate,
even if such a list was prepared, it has not come into opera-
tion and work was not assigned to the drivers accordingly.
The I Party, therefore, prays that an Award may be passed
directing the II Party to give Lasrado the increments from
31-5-1973 onwards.

4. After hearing both the Counsels, the point of dispute
was treated as the issue arising for consideration. By consent
of parties Ext. W-1 to W-16 and Ext. M-1 to M-11 have
been marked. Both the parties have stated that they do not
have any oral evidence.

5. Point of Dispute.

Ext. M-1 is the order dated 21-12-1966 appointing V. S.
Lasrado as driver. K. Narayana was appointed subsequently
on 31-5-1967 as per Ext. M-2. Ext. M-2 mentions that K.
Narayana was appointed as Jeep driver. Both the workmen
drew their annual increment of Rs. 3. As on 31-12-1972,
Lasrado was drawing Rs. 128 per month and K. Narayana
was drawing Rs. 125 per month. The Central Civil Services
(Revised Pay) Rules, 1973 came into force with effect from
1-1-1973. On revision, the pay of both Lasrado and K.
Narayana was fixed at Rs. 284. There is no dispute about
the correctness of such fixation. What happened subsequently
was, as usual, K. Narayana got his increment on 31-5-1973
and his pay was enhanced to Rs. 287, but Lasrado had to
wait for his increment to fall due on 17-12-1973 and get his
pay raised to Rs. 287. Thus, it happens that K. Narayana
earns his increment earlier in the course of the year. This
state of affairs occurs every year. Lasrado now contends
that he is senior to K. Narayana, he having joined service
on 17-12-1966 before K. Narayana joined service on 31-5-1967
and that he should be given his increment as from the date
on which K. Narayana earns his increment, i.e., on 31st
May, and not later, during the course of the year, on 17th
December.

6. The question that falls for consideration is whether
Lasrado's contention is sustainable.

7. Both the parties relied upon the 2nd proviso to Rule 8
of the Revised Pay Rules which reads as follows:—

"Provided further that, in case other than those covered
by the preceding proviso, the next increment of a
Government servant, whose pay is fixed on 1st of
January, 1973 at the same stage as one fixed for
another Government servant junior to him in the
same cadre and drawing pay at a lower stage than
his junior in the existing scale shall be granted on
the same date as admissible to his junior, if the
date of increment of the Junior happens to be
earlier."

According to the II Party, Lasrado and K. Narayana belong
to different cadres, the former belonging to the cadre of
Lorry drivers which, as seen from Ext. M. 3 Recruitment
Rules for the posts of work-charged establishments, falls
in category No. 13 and K. Narayana falls in the category of
jeep drivers which is category No. 14 in Ext. M. 3 Rules
of Recruitment. Therefore, according to the II Party, K.
Narayana cannot be considered to be junior to Lasrado in the
same category and, therefore, finally Lasrado cannot be
given the benefit of an advanced date of increment, viz., the
same date as K. Narayana's date of increment. In this con-
nection, to prove that the names of Lasrado and K. Narayana
are entered in separate seniority lists relating to category
No. 13—Lorry Drivers and Category No. 14—Jeep Drivers res-
pectively, the II Party has produced Ex. M. 4 revised seniority
list of the work-charged establishment as on 30-6-1973.

8. On the other hand, it is urged by the I Party in the first instance that Lazrado was not appointed specifically as lorry driver as per Ext. M. 1. Then it is further urged that even if Lazrado was appointed as a lorry driver, there is a system prevailing in the II Party-Establishment according to which, any driver can be directed to operate any other vehicle. In this connection, the I Party has relied upon the log books maintained by the II Party in connection with the vehicles belonging to it. Attention is invited by the I Party's Counsel to Ext. W-3 dated 21-9-1973 order directing Lazrado to be in charge of the Ambulance Van/or any other vehicle as driver. As per Ext. W-4 order dated 24-3-76, Lazrado was asked to be in charge of Explosive van bearing No. MYX 6253. Ext. W. 11 log sheet relating to explosive van MYX 6253 shows that on certain days, it was not Lazrado who was in charge, but one Jacob. Therefore, according to the I Party's Counsel, the posts of drivers whether of lorries, vans or jeeps are inter-changeable and thus K. Narayana cannot be treated as not a Junior to Lazrado and an employee working in a different category or set up. The Seniority list Ext. M. 4 was challenged on the ground that it was prepared on 30-6-1973 issued on 20-9-1973 and served on Lazrado on 11-10-73. According to the I Party's Counsel, the seniority list Ext. M. 4 is ineffective because by the time it was prepared and issued, K. Narayana had already drawn his increment i.e., 31-5-1973, and this should not have been allowed to happen.

9. I have considered the rival submissions. That Lazrado and K. Narayana belong to separate categories of service admits of no doubt. It is clearly stated in Ext. M. 1 appointment order relating to Lazrado that his pay is debitable to the expenditure to the truck bearing No. MYX 6056. When such is the case, it is clear that, though Ext. M. 1 order does not say so in as many words, Lazrado was appointed as a lorry driver. In the case of K. Narayana, it is specifically mentioned in Ext. M. 2 order that he is appointed as Jeep driver. In fact, the very circular Ext. W. 1 dated 13-1-1970 issued by the II Party covering drivers of all vehicles who are informed that their duty is to drive the vehicle given to them whether it would be a jeep or a Station Wagon, a lorry, a water lorry, an Ambulance or an Explosive Van, itself shows that there were separate categories of drivers one relating to the drivers of jeeps another relating to drivers of station wagons, etc. The spirit behind the direction to drive any vehicle that is given is to keep the drivers engaged when they are being paid wages in case any particular vehicle which is assigned to his care is not available to be run on account of dis-repair and his services are required to drive another type of vehicle whose driver was on leave. Therefore, the Party's Counsel does not derive any support for his contention that K. Narayana is junior to Lazrado in the very same cadre by pointing out that there is a mix-up of drivers in the actual discharge of their duties. Whatever interchange of work is done, it is subject to the Cadre & Recruitment Rules which cannot be disturbed. As per the Cadre and Recruitment Rules, the drivers of lorries and jeeps belong to different categories and as per the Seniority List Ext. W. 4 Lazrado cannot be considered to be senior to K. Narayana because their names are entered in different categories of service. The II Party's Counsel also cannot raise any objection to Ext. M. 4. Ext. M. 4 is a revised list that was prepared as on 30-6-1973. The fact that Ext. M. 4 is a revised list impliedly shows that there was another list which was prepared earlier. Apart from this, the Seniority List on finalisation, would relate back to an earlier date. The seniority list cannot, therefore, be considered to be purely prospective from the date of its preparation. Finally, Lazrado has not challenged ext. M-4 Seniority List saying that he and Narayana should have been placed in the same category with the name of Narayana entered below his name.

9. It follows from the foregoing that K. Narayana is not junior to Lazrado. He can, therefore, have no grievance as against Narayana earning his annual increment earlier in the course of the year on 31st of May. Both Lazrado and Narayana have to be content with whatever prospects they have in their respective categories of service and Lazrado cannot point out the case of K. Narayana who had joined service later on, as a case of discrimination in the fixation of his own pay. This point is held accordingly.

10. In the result, an Award is passed rejecting Lazrado's claim, vis-a-vis, K. Narayana in the matter of drawal of pay.

(Dictated to the Stenographer, transcribed by him and corrected by me).

Dated : 26-8-78.

[L-45012(2)/77-D.IV(A)]

F. L. F. ALVARES, Presiding Officer,

New Delhi, the 8th September, 1978

S.O. 2724.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur (M. P.) in the industrial dispute between the employers in relation to the management of the Bank of Maharashtra and their workmen over the alleged wrongful termination of Shri S. T. Badvekar, Bills Collector of Dharampeth Branch which was received by the Central Government on the 1-9-1978.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

PRESENT :

CASE NO. CGTI/LC (R) (36)/1978

PARTIES :

Employers in relation to the management of the Bank of Maharashtra and their workmen represented through the Vidharba Bank Employees Federation, Near Jathar Building, New Datta Mandir Road, Itwari, Nagpur (M. S.)

APPEARANCES :

For Union.—Shri S. P. Chowdhury, President.

For Bank.—Shri A. S. Pote, Officer in Legal Department.

INDUSTRY : Bank

DISTRICT : Nagpur (M.S.)

AWARD

This is a reference made by the Government of India in the Ministry of Labour vide its Order No. L-12011/7/78-D.II.A. dated 13-8-1978, for the adjudication of the following industrial dispute :

"Whether the action of the management of Bank of Maharashtra, Nagpur in terminating the services of Shri S. T. Badvekar, Bill Collector Dharampeth Branch of the Bank of Maharashtra, Nagpur is legal and justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. The parties have filed two separate applications incorporating the terms for consent award. Accordingly the management shall reinstate Shri S. T. Badvekar on the post of Bill Collector Dharampeth Branch, Nagpur with effect from 1-9-1978. He will draw the basic wage as he was drawing on 3rd October, 1973. The service shall be deemed to have continued from the date of his initial employment for the purposes of determining his entitlement to the benefits of seniority. Shri Badvekar shall not be entitled to wages for the period from 4-10-1973 to 31-8-1978 and no increment shall be deemed to have accrued during this period. The incre-

ments after reinstatement shall be due in the month of July, 1979 and that shall be the date for further increments. The terms being reasonably beneficial to the workman, the award is given accordingly.

S. N. JOHRI, Presiding Officer

Dated : 28th August, 1978.

[L-45012(2)/77-D.IV(A)]

NAND LAL, Desk Officer

S.O. 2725.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta in the industrial dispute between the employers in relation to the West Bengal State Cooperative Bank Limited, Calcutta and their workmen which was received by the Central Government on the 21-8-78.

**CENTRAL GOVERNMENT LABOUR COURT
AT CALCUTTA**

Misc. Application No. LC 2 of 1977

PARTIES :

Sri Iyotirmoy Sen, C/o The West Bengal State Cooperative Bank Ltd., 24A, Waterloo Street, Calcutta-1.
..Applicant.

Versus

The West Bengal State Cooperative Bank Limited, 24-A, Waterloo Street, Calcutta-1. ..Opp. Party.

APPEARANCES :

On behalf of Applicant.—Sri A. K. Bose, Advocate.

On behalf of Opp. Party.—Sri A. Choudhury, Bar-at-Law, with Sri K. K. Das Gupta, Advocate.

STATE: West Bengal

INDUSTRY: Banking

AWARD

This is an application by a clerk in the employment of the Opposite Party under Section 33A of the Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication as to whether his condition of service was in any manner changed, and for an award against the Opposite Party directing it to cancel or revoke an order, dated 13th May, 1977 and to continue to employ him as a Clearing House Representative as before. The application was made in aid of the main application which is one under Section 33-C(2) of the Industrial Disputes Act, 1947.

2. At the hearing of this application a preliminary objection on the point of jurisdiction was taken on behalf of the Opposite Party. It was submitted that Opposite Party has no branch or establishment outside the State of West Bengal. The Opposite Party is therefore not a Banking Company in the contemplation of the Industrial Disputes Act having regard to the definition of a Banking Company in Section 2(bb) of the said Act. In that view of the matter, it was further submitted that this Court which has been constituted by the Central Government has no jurisdiction to entertain this application having regard to the definition of 'appropriate Government' in Section 2 of the said Act. Under that Section, the Central Government is the appropriate Government in relation to any industrial dispute concerning a Banking Company, but the Opposite Party, not being a Banking Company within the meaning of the Industrial Disputes Act, is not amenable to the jurisdiction of this Court.

3. It is not in dispute that the Opposite Party has no branch or establishment outside the State of West Bengal. It is therefore not a Banking Company in the contemplation of the Industrial Disputes Act and this Court has therefore no jurisdiction over an industrial dispute between the Opposite Party and its workman. In that view of the matter the application is dismissed on the ground that this Court has no jurisdiction to entertain it.

581 GI/78—7

4. The applicant will be at liberty to institute such proceedings before an appropriate court or tribunal as are available to him in law.

S. K. MUKHERJEA, Presiding Officer

Dated : Calcutta,

The August 14, 1978.

[No. L-12025/132/78-D.II.A]

S.O. 2726.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Ahmedabad in the industrial dispute between the employers in relation to the Central Bank of India, Jamnagar and their workmen over wrongful termination of service of Shri Osman Juma, Guard which was received by the Central Government on the 24-8-78.

**BEFORE SHRI R. C. ISRANI, B.A. (Hons), LL.B.,
PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL AT AHMEDABAD**

Reference (ITC) No. 3 of 1977

ADJUDICATION

BETWEEN

Central Bank of India, Jamnagar..First Party;

AND

Their workmen..Second Party.

In the matter of discontinuing the services of Shri Usman Juma, Ramoshi, etc.

APPEARANCES :

Shri A. R. Buch, Divisional Manager, Jamnagar—
for the First Party; and

Shri Usman Juma in person.

STATE: Gujarat

INDUSTRY: Banking

AWARD

This is a reference made by the Government of India to this Tribunal under Section 33B(1) of the Industrial Disputes Act, 1947, hereinafter to be referred to as 'the Act', vide Government of India, Ministry of Labour, New Delhi's Order No. L-12012/34/77-D.IIA, dated the 2nd July, 1977, in respect of an industrial dispute which has arisen between the Central Bank of India, Jamnagar, hereinafter to be referred to as 'the Bank' and the workmen employed under it.

2. The dispute as it appears from the Schedule attached to the original order under which this reference has been made, relates to two demands which are as under :—

"(1) Whether the action of the Branch Manager, Central Bank of India, Jamnagar in stopping Shri Usman Juma, Ramoshi from service with effect from 1-11-76 is justified? If not, to what relief is the workman entitled?

(2) Whether Shri Usman Juma, Ramoshi, Central Bank of India, Jamnagar Branch is entitled to the pay scale and other benefits admissible to other Class IV employees of the Bank employed in the Jamnagar Branch? If so, to what relief is the workman entitled?"

3. In support of these demands, the concerned workman, viz., Shri Osman Juma, hereinafter referred to as 'the workman' has filed his statement of claim Ex. 4/2, dt. 17-10-77. It is the case of the workman that he was appointed as a Ramoshi (watchman) by the Bank with effect from 4-3-66. It is his case that he was in the employment of the Bank and used to perform various duties assigned to him by the authorities of the Bank, especially the Manager of the Bank

at its Jamnagar Branch. It is explained by him that he was performing the duties as directed by the Manager of the Bank including the duty of accompanying the cash carrier at the time the cash was to be transported from the premises of the Bank to any other place. It is also his case that he was performing his duties quite honestly and diligently. However, it is his grievance that he was not being paid his wages on the same lines as they used to be paid to other Class IV employees of the Bank employed in its Jamnagar Branch. The complaint of the workman is that without giving him any previous notice and without assigning any reason, he was stopped from performing his duties in that branch of the Bank with effect from 1-11-76. It is his contention that this action of the Bank was illegal and unjustified. He approached the authorities of the Bank to withdraw these orders preventing him from performing his duties. But since the authorities were not in a mood to do so, the present industrial dispute was raised and ultimately the Government of India was pleased to make this reference. The reference was at first made to the Industrial Tribunal consisting of Shri M. U. Shah, but after he ceased to be such Tribunal, the reference was transferred to this Tribunal.

4. On behalf of the Bank, the written statement Ex. 6 has been filed on 26-11-77. Through this written statement, certain legal preliminary contentions have been taken to the effect that this Tribunal has no jurisdiction to entertain or decide the dispute covered by this reference; that the present workman cannot claim the status of a 'workman' as defined under the Act and that the workman was not in the employment of the Bank. It is explained by the Bank that there is a scheme with the Police Department governed by the rules and regulations for the "Administration of Police Ramoshi Funds" under which the Police Department makes available the services of retired Police Personnel for employment under private parties including the banks, etc. for which those parties make payments to the Police Department. It is explained by the Bank that in the instant case, the workman was not directly employed by the Bank. The Bank had requested the District Superintendent of Police, Jamnagar, to provide the services of a retired Police constable to work as the Ramoshi or watchman for the Bank. It was the D.S.P. of Jamnagar who sent the workman to the Bank to work there as the watchman; that his wages or remuneration was also fixed by the D.S.P. and in fact the wages to be paid to the workman used to be deposited by the Bank with the D.S.P. who used to pay the same to the workman. It is also contended by the Bank that there was no relationship of an employer and an employee between the Bank and the workman and, therefore, also the present demand would not survive. It is explained by the Bank that when it was found that it was no more necessary for the Bank to have the services of the workman, an intimation to that effect was given to the D.S.P. who advised the Bank that a notice of 15 days was required to be given to the workman before his services were dispensed with as envisaged under the relevant rules relating to the scheme of employing the Police Ramoshi. Consequently, the Bank sent a cheque of Rs. 122/25 being the wages for 15 days to the D.S.P., Jamnagar for the purpose of paying the same to the workman. However, it appears that the workman refused to accept that amount as it was perhaps his contention even at that stage, that he was a regular employee of the Bank. In view of this position, it is contended by the Bank that the workman was not in the employment of the Bank and, therefore, he cannot claim the status of a 'workman' as defined u/s. 2(s) of the Act. If that is so, the further contention of the Bank is that the present dispute would not amount to an 'industrial dispute' as envisaged u/s. 2(k) of the Act. Such a dispute can exist only between employers and employees or between employers and employees or even between workmen and workmen. In the instant case, since there is no relationship of employer and employee between the Bank and the workman, the present dispute cannot be defined as an 'industrial dispute' and therefore, the present reference will have to be rejected.

5. When this reference was taken up for consideration, it was found that the Bank was represented by Shri A. R. Buch, the Divisional Manager of the Bank and so far as the workman is concerned, he himself had remained present. Unfortunately neither any union representative nor any other person came forward to either help or represent the workman. This being the position, great care has been taken to see whether the demands made on behalf of the workman can be legally granted? The workman himself has entered into the wit-

ness box and his evidence is recorded at Ex. 12. Thereafter he passed the purshis Ex. 17 on 20-6-78 stating that he had no further evidence to lead. On behalf of the Bank also the purshis Ex. 18 was given on 17-7-78 stating that no oral evidence was to be led on behalf of the Bank. I have heard the workman in person and Shri A. R. Buch on behalf of the Bank. After hearing the parties and after perusing the evidence on record, the only short point which would call for determination at this stage would be, "whether it can be said, in the instant case, that the workman was in the employment of the Bank at the time his services were terminated with effect from 1-11-76"?

6. It is an admitted fact that the workman was employed as a Police Constable in the Police Department at Jamnagar. As regards his appointment as the Ramoshi in the Bank, he himself has given the details during his examination-in-chief at Ex. 12, it will be important to reproduce the relevant passage from his evidence which is as under :—

"Before I was re-employed by the bank, I was serving as a Police Head Constable in the Police Deptt. I had retired from that service about 6 months before I was reemployed by the bank. I was appointed by the chief agent of the bank by oral order and an assurance was given to me that I would be confirmed in that post of watchman. The demand was made by the bank authorities for a watchman through the D.S.P. and my name was also suggested by the D.S.P. My monthly wages were Rs. 80, which were also being paid to me by the bank through the D.S.P. The bank authorities used to send the cheque to the D.S.P. through the bank where it used to be cashed and I used to be paid my wages from the office of the D.S.P."

It is clear from this evidence that he was not appointed directly by the Bank but it was through the D.S.P., Jamnagar that his services were secured by the Bank for the purpose of working as the watchman in the Bank. During his cross-examination he has stated as under :—

"It is true that I was not directly appointed by the bank, but I was sent to work under the bank by the Police Deptt. through D.S.P. Jamnagar. It is also true that my wages used to be paid from the office of the D.S.P. I have no knowledge about the terms and conditions between the Police Deptt. and the bank, on which I was directed by the Police Deptt. to go and serve with the bank."

It is thus clear that the services of the workman were obtained by the Bank through the Police Department under the scheme which exists for the purpose of engaging the services of retired police constables and police head constables.

7. The Bank has produced certain documents in this reference which clearly show that such persons whose services are given by the Police Department to private parties under that scheme remain under the control of the Police Department and for all purposes they are considered to be under the Police Department. They have only to work with those private parties to whom their services are assigned and for which the payment is made by these parties, not directly to the persons concerned, but through the Police Department. In this connection, a reference is invited to Ex. 22. It is the office order dt. 13-9-61. This order was passed by the then D.S.P. for the district of Jamnagar in respect of one retired Constable by name Kasam Abdulla to work as a Police Ramoshi with the Central Bank of India. From this order it becomes clear that the orders for providing the services of such persons to such private parties were being made by the Police Department. In the same way is the other order at Ex. 21/7, dt. 29-12-71. Through that order also the then D.S.P. Shri V. K. Zafa provided the services of retired Police Constable Ibrahim Valli to the Central Bank of India, Jamnagar, to work there as Police Ramoshi on a monthly remuneration of Rs. 35 plus the D.A. of Rs. 116 p.m. From these two orders it clearly appears that the Police Department makes available the services of such persons to work as Police Ramoshi for the private parties. The order in respect of the workman is not on the record, as it has been explained by the Bank that in spite of so many efforts to trace out that order, it has not been found. However, the

Bank authorities had requested the D.S.P., Jamnagar to supply them with a copy of that order. But, the D.S.P. replied to the Bank authorities vide his letter dt. 1-8-78, Ex. 21/8. While referring to this aspect of the case, the D.S.P. stated in the concluding para of that letter as under :—

"It is also seen from the appointment order of Ramoshi Osman Juma that a copy was already endorsed to the Bank and they must be having the same."

It is clear from this averment that the original order of appointment was made by the D.S.P., Jamnagar even in respect of the workman and a copy of that appointment order was forwarded to the Bank. From these three documents, it becomes amply clear that no direct appointment of the concerned workman was made by the Bank. But, his services were made available to the Bank by the Police Department through the D.S.P., Jamnagar, in pursuance of the scheme of the Police Department for the re-employment of retired police constables and head constables. There is documentary evidence on record that even after the appointment, it was the Police Department which was taking care for the welfare of such persons whose services were placed at the disposal of the private parties. It was the Police Department which was taking care that such persons received proper treatment, that they received D.A. consistent with the situation and that they were given leave, etc. in accordance with the prevalent practice in other departments or establishments. In this connection, reference is invited in the first instance to the urgent letter addressed by the D.S.P., Jamnagar to various institutions including the Bank to whom the services of such persons were made available. That letter is dt. 17-9-75 at Ex. 21/1. Through this letter the attention of all these establishments was invited to the fact that Police Ramoshi employed by them should be given enhanced rate of D.A. The other such document is at Ex. 21/9 dt. 21-10-78. This letter is addressed by the Branch Manager of the Bank at Jamnagar to the D.S.P., Jamnagar. Through this letter the manager informed the D.S.P. that it was no more necessary to retain the workman as Ramoshi under the Bank and, therefore, the intimation was given that his services may be withdrawn with effect from 31-10-76. This letter is a direct testimony to the fact that the appointment of the workman was made by the Police Department and it is, therefore, that a request was made by the Bank to that department to withdraw his services with effect from a particular date. To the letter of the Bank, the D.S.P. replied through the letter dt. 30-10-76, Ex. 21/2. Through this letter the D.S.P. drew the attention of the Bank that according to the rules, a 15 days notice was required to be given to such persons before their services could be withdrawn. He, therefore, advised the Bank to give such notice to the workman. After the receipt of this letter, the Bank authorities immediately sent the 15 days wages to the D.S.P. through the cheque Ex. 21/4 dt. 4-11-76. Through the letter Ex. 21/3 dt. 18-12-76, the D.S.P. informed the Bank that the workman had refused to accept the amount sent by the Bank through that cheque. The last document to be referred to in this connection is the letter dt. 2-9-72 addressed by the D.S.P., Jamnagar to various institutions including the Bank regarding the facility of leave to be given to Police Ramoshis whose services were made available to those institutions. From this entire documentary evidence it becomes very clear that such persons including the present workman were not directly appointed by those institutions but their services were made available to them by the Police Department in pursuance of the scheme to that effect as contained in the Police Manual, Vol. III. Such persons, therefore, were under the direct control of the Police Department through which department they were paid even their wages and it was the Police Department which cared for their welfare and also looked after their conditions of service while serving these private institutions. These persons only work for these institutions for which these institutions pay their wages again through the Police Department. In view of these admitted facts, it will have to be found out, whether the workman can be said to be in the employment of the Bank and consequently whether he can claim the status of a 'workman' so as to locally raise this present industrial dispute through this reference?

8. The point involved in this reference is fully covered by a decision of the Supreme Court of India reported in 1963-1 L.J. p. 126, in the case between Kirloskar Oil Engines,

Ltd. v/s. Hanumant Laxman Bibawe. A copy of that judgement has been produced by the Bank in this reference at Ex. 13/1. In that case before the Supreme Court of India. Their Lordships were considering a similar question regarding the relationships of a Police Ramoshi and a private party for whom the said Police Ramoshi was working. On p. 128, the Supreme Court has discussed the scheme of providing the services of Police Ramoshi to private individuals or parties by the Police Department. The said scheme has been disclosed as under in that case :—

"Turning to the scheme under which the respondent was asked to do the work as a watchman by the appellant, most of its material terms emphatically bring out the fact that the respondent cannot be treated as the appellant's employee and cannot claim the status of an industrial employee. It appears that the scheme has been evolved by which watchmen are supplied by the Police Department to different employers and this scheme was evolved because it was found that there was a demand for such watchmen by private individuals. There are several paragraphs which set out the material terms and conditions of the scheme. The private persons who require the services of watchmen have to apply to the District Superintendent of Police. The District Superintendent of Police supplies a watchman if he thinks a suitable watchman is available. The amount on account of pay of the watchman is recovered per month in advance from the employer. This amount has to be credited to the watchman fund on receipt of advance bills submitted from the office of the Superintendent of Police. Out of the amount thus recovered from the employer Rs. 2-8-0 per month are deducted on account of the cost of clothing supplied and the balance is paid to the watchman. It is significant that the Inspector-General of Police is authorized to vary this rate in any district under his control subject to the maximum of Rs. 30 per annum. The work done by the watchman is supervised by the subordinate police, particularly at night by the night patrols who know where police watchmen are employed and look them up to see if they are alert. The men thus sent as watchmen are mustered for duty in the police section in which their employer's bungalow are situated. They are paid by the Superintendent of Police direct like ordinary police. They are entirely under the departmental control and orders of the Superintendent of Police and he alone can fine or punish them; the employers are not authorized to do so. In supplying watchmen the Superintendent has to be very careful to see that the employer who asks for a watchman is a person likely to be punctual in his payments and likely to pay without the amount having to be demanded and without correspondence. An employer is requested to give a fortnight's notice in case he wants to discontinue the service of the watchman. The credits on account of the pay of watchmen are made to the watchman fund. Under this system the Superintendent of Police is the agent through whom such watchmen are employed and he alone is vested with such powers as vest in a master over his servant, and he takes this special duty upon himself in the interest of the public safety which it is his duty to secure. These are the main features of the scheme under which the respondent's services were made available as watchman to the appellant."

After considering the said scheme Their Lordships came to the following conclusion which may be reproduced as under :—

"It would be noticed that almost each one of these terms emphatically brings out the fact that though the respondent was working as a watchman of the appellant, strictly speaking, in law the relationship of master and servant did not subsist between the two. The payment was not made directly by the appellant to the respondent. He could not supervise his work; he could not take any action against him in case his conduct was found to be unsatisfactory and in terms the scheme provides that it is the District Superintendent of Police in whom the rights of the master vested qua persons like the respondent whose services were loaned to private individuals. In our

opinion, having regard to these terms of the scheme, it is difficult to accept the view taken by the tribunal that the respondent was an employee of the appellant, that he was an industrial employee and therefore he was a workman concerned in the dispute which was pending adjudication on the date of his discharge."

Ultimately, in that case Their Lordships came to the conclusion that the Police Ramoshi or watchman whose services were made available to the company was not an employee of the Company and therefore, he could not claim the status of a 'workman' and consequently no industrial dispute could be raised by him. **The concluding paragraph of that decision on p. 130 is to the following effect :—**

"In the present case, where the respondent became the watchman of the appellant under a scheme which has been evolved for supplying watchmen to private employers, the fact that the private employer may issue orders to the watchmen will not be an important consideration at all. It is the other terms and conditions of the system under which the arrangement has been made which may have to be borne in mind and it is in the light of all the relevant facts that one has to reach the final decision. Having regard to all the relevant facts in this case, we are satisfied that the respondent cannot be said to be an employee of the appellant ; and so, he cannot claim to be an industrial employee and as

such, a workman concerned in the above industrial dispute pending adjudication at the relevant time."

This decision of the Supreme Court, therefore, fully covers the present case and on the strength of that decision it can be legitimately held that even in the instant case, the workman cannot be treated as an 'employee' of the Bank and if that is so, there is no relationship of employer and employee between the two. In that case, there cannot be any industrial dispute between the two as according to the definition of 'industrial dispute', it can be only between an employer and an employee, so far as the present case is concerned. In view of this decision, the present dispute cannot be said to be an industrial dispute and, therefore, legally it cannot be adjudicated upon by this Tribunal through this reference. The reference itself is incompetent and, therefore, will have to be rejected.

9. The result, therefore, is that the present reference fails and is directed to be rejected with no order as to costs.

R. C. ISRANI, Presiding Officer.

Ahmedabad,
Dt. 8th August, 1978.

[No. 1-12012/34/77-D-IIA1

R. P. NARULA, Under Secy.